



संख्या: 2-236/2021-हि0प्र0वि0वि0(सामान्य)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
“सामान्य प्रशासन शाखा”

प्रेषित,

1. आचार्य सिकन्दर कुमार, माननीय कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला-5
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हि०प्र० सरकार, शिमला-2
3. सचिव (शिक्षा), हि०प्र० सरकार, शिमला-2
4. शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-1
5. आचार्य पी०के० गर्गा, अधिष्ठाता पर्यावरण विकास और स्थिरता अध्ययन, हि०प्र०वि०, शिमला-5
6. आचार्य नागेश ठाकुर, अधिष्ठाता, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, भौतिक विज्ञान विभाग, हि०प्र०वि०, शिमला-5
7. डॉ० अनिल कुमार जरयाल, प्राचार्य, राज० महाविद्यालय खुंडिया, जिला कांगडा, हि.प्र.
8. श्री राकेश कुमार, माननीय विधायक, विधान सभा, सुन्दरनगर निर्वाचन क्षेत्र, गोंव पुंघ, डा० व तह० सुन्दरनगर-1, जिला, मण्डी, हि०प्र०। (alongwith supplementary agenda and on spot item)
9. आचार्य यशवंत कुमार, हि०प्र०विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, हि०प्र०वि०शिमला-5
10. श्री सुभाष ठाकुर, माननीय विधायक, विधान सभा, बिलासपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र, मकान न० 23/4, सैक्टर -2, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, (हि०प्र०) (alongwith supplementary agenda and on spot item)
11. श्रीमती राज कुमारी, सहायक कुलसचिव, U.I.L.S, हि०प्र०वि०शिमला-5
12. आचार्य एन०के० शारदा, मांगल्यम, कंगनाधार, फेज-III, शिमला-9
13. आचार्य वी०पी० शर्मा, वशिष्ठ भवन, बिलो पुलिस पोस्ट समरहिल, शिमला-5
14. डॉ० अश्विनी राणा, सह आचार्य (अंग्रेजी), ICDEOL, हि०प्र०वि०शिमला-5

दिनांक: शिमला-5.

24 DEC 2021

विषय:- कार्यकारिणी परिषद की वर्ष 2021 की तृतीय नियमित बैठक की कार्यवाही।

महोदय/महोदया,

कार्यकारिणी परिषद की वर्ष 2021 की तृतीय नियमित बैठक जो दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में सम्पन्न हुई, की कार्यवाही आपके अवलोकनार्थ एवं पुष्टिकरण हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

कुलसचिव
सदस्य-सचिव

पृष्ठांकन संख्या: सम ।

प्रतिलिपि कार्यवाही की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित है:-

दिनांक:

24 DEC 2021

1. सचिव कुलाधिपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल, हि०प्र० राज भवन, शिमला-2 (alongwith supplementary agenda and on spot item)
2. अधिष्ठाता अध्ययन/छात्र कल्याण/मुख्य छात्रपाल/निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र/ वित्त अधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक, हि०प्र०वि०, शिमला-5
3. समस्त संकायों के अधिष्ठाता/ समस्त अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्ष, हि०प्र०वि०, शिमला-5
4. संयुक्त परीक्षक, स्थानीय लेखा विभाग/ उप-कुलसचिव (स्था०), हि०प्र०वि०, शिमला-5
5. प्राचार्य, हि०प्र०वि०, सांध्यकालीन अध्ययन विभाग, शिमला-1
6. सचिव-कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला-5
7. प्रभारी, बैंक-साईट, हि०प्र०वि०, शिमला-5 को उपरोक्त कार्यवाही को विश्वविद्यालय बैंक-साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
8. अनुभाग अधिकारी (कुलपति कार्यालय), हि०प्र०वि०, शिमला-5
9. विशेष निजी सचिव-कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला-5
10. रक्षक मिसिल।

कुलसचिव

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
'सामान्य प्रशासन शाखा'

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2021 की द्वितीय नियमित बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आचार्य सिकन्दर कुमार, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. आचार्य सिकन्दर कुमार, माननीय कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला-5
2. श्री राकेश कंवर, विशेष सचिव (वित्त), हि०प्र० सरकार, शिमला-2
3. श्री अश्विनी राज शाह, विशेष सचिव (शिक्षा), हि०प्र० सरकार, शिमला-2
4. निदेशक (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-1
5. आचार्य पी० के० गर्गा, अधिष्ठाता पर्यावरण विकास और स्थिरता अध्ययन, हि०प्र०वि०, शिमला-5
6. आचार्य नागेश ठाकुर, अधिष्ठाता, इंजिनियरिंग और प्रौद्योगिकी, हि०प्र०वि०, शिमला-5
7. डॉ० अनिल कुमार जरयाल, प्राचार्य, राज० महाविद्यालय खुंडिया, जिला कांगडा, हि.प्र.
8. आचार्य यशवंत कुमार, हि०प्र० विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, हि०प्र०वि०, शिमला-5
9. श्रीमती राज कुमारी, सहायक कुलसचिव, UILS, हि०प्र०वि० शिमला-5
10. आचार्य एन०के० शारदा, मांगल्यम, कंगनाधार, फेज-III, शिमला-9
11. आचार्य वी०पी० शर्मा, वशिष्ठ भवन, बिलो पुलिस पोस्ट समरहिल, शिमला-5
12. डॉ० अश्विनी राणा, सह आचार्य (अंग्रेजी), ICDEOL, हि०प्र०वि० शिमला-5

मद संख्या-1: कुलपति महोदय का वक्तव्य।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2021 की तीसरी नियमित बैठक में मैं आप सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

सर्वप्रथम मैं कार्यकारिणी परिषद् के पूर्व में सदस्य रहे श्री विपन कुमार का कार्यकारिणी परिषद् में उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ तथा उनके स्थान पर नव निर्वाचित सदस्य श्रीमती राजकुमारी का कार्यकारिणी परिषद् में स्वागत करता हूँ।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएँ आयोजित की गई:-

1. दिनांक 24 अगस्त, 2021 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों, सांध्यकालीन अध्ययन विभाग, क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला तथा विभिन्न केन्द्रों / संस्थानों में नव-नियुक्त आचार्यों, सह-आचार्यों एवं सहायक आचार्यों के साथ विश्वविद्यालय सभागार में विचार-विमर्श किया गया।
2. दिनांक 26 अगस्त 2021 को विश्वविद्यालय में स्थापित ई.आर.पी. सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
3. दिनांक 6 सितम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय के गणित विभाग की बैठक की ऑनलाइन अध्यक्षता की।
4. दिनांक 7 सितम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय के विधि विभाग तथा पीएचडी बौद्धिक संपदा सुविधा केन्द्र नई दिल्ली, के संयुक्त तत्वावधान में "उद्यमिता पर विशेष ध्यान देने के साथ नवाचार बौद्धिक संपदा के अधिकार" विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
5. दिनांक 10 सितम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय के सभी अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों, निदेशकों के साथ "आज़ादी का अमृत महोत्सव" विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
6. दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय के यू०आई०टी०, के स्थापना दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
7. दिनांक 14 सितम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा 'हिन्दी उत्सव' के अवसर पर आयोजित 'वर्चुअल मीटिंग' में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
8. दिनांक 16, 17, 20 व 21 सितम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय द्वारा गठित विभिन्न समितियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

9. 17 सितम्बर, 2021 को भारत के माननीय प्रधान मन्त्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्म दिवस के सुअवसर पर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया।
10. दिनांक 17 सितम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र (इक्डोल) ने इकोमओसियाना टेक्नोलॉजी प्रा.लि. मोहाली, पंजाब के साथ कौशल विकास, परिणाम आधारित प्रशिक्षण, प्लेसमेंट, अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धित सेवाओं के सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
11. दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
12. दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को सेंट बीड्स कॉलेज, शिमला द्वारा "आई.एस.सी.ए. चैप्टर शिमला" विषय पर आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता की।
13. दिनांक 23 सितम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा "हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ" विषय पर आयोजित वेबिनार की ऑनलाईन अध्यक्षता की।
14. दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को होटल पीटर हॉफ, शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया।
15. दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय परिसर में हमीरपुर छात्र संघ द्वारा आयोजित वृक्षारोपण अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
16. दिनांक 28 सितम्बर, 2021 को एन.आई.डी.एम. भारत सरकार तथा यू.आई.टी. के संयुक्त तत्वावधान में हिमालयी क्षेत्र में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर तीन दिवसीय ऑनलाईन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
17. दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को कुलसचिव, निदेशक (यू.आई.एल.एस) तथा वित्त अधिकारी के साथ विश्वविद्यालय के विधिक अध्ययन संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
18. दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 को विश्वविद्यालय तथा इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय ऑन-लाईन सम्मेलन "सांस्कृतिक अध्ययन" में मुख्य अतिथि के रूप में भाग की।
19. दिनांक 5 अक्टूबर, 2021 को विश्वविद्यालय में "विश्व अध्यापक दिवस" के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
20. दिनांक 5 अक्टूबर, 2021 को विश्वविद्यालय की "कॉफी टेबल बुक" के प्रकाशन से सम्बन्धित प्रगति के सम्बन्ध में बैठक की अध्यक्षता की।
21. दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 को भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा वरिष्ठ शिक्षाविदों के साथ "Leadership Development on Circular Economy" विषय पर आयोजित ऑनलाईन कार्यशाला में भाग लिया।
22. दिनांक 6, 7, 8 अक्टूबर, 2021 को विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के उत्थान से सम्बन्धित गठित विभिन्न समितियों के साथ आयोजित बैठकों की अध्यक्षता की।
23. दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व छात्र संघ की संचालन मण्डल की बैठक की अध्यक्षता की।
24. दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विधिक अध्ययन संस्थान तथा कैरियर प्वाइंट विश्वविद्यालय, भोरंज, जिला हमीरपुर के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
25. दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को विश्वविद्यालय के यू.आई.टी. द्वारा सभागार में आयोजित इंडक्शन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
26. दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को विश्वविद्यालय के समन्वयकों के साथ बैठक आयोजित की गई।
27. दिनांक 19 अक्टूबर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा राजस्व आपदा प्रबन्धन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
28. दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा Research for Resurgence Foundation (RFRF), Nagpur के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

29. दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 को विश्वविद्यालय सभागार में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शोध एवं भारतीय ज्ञान परम्परा का योगदान" विषय पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
30. दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विधि विभाग तथा डॉ. भीम राव अम्बेदकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
31. दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 को प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवम् विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रतिभागियों के सम्मान में संकल्प फाउंडेशन व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया।
32. दिनांक 8 नवम्बर, 2021 को कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में आयोजित "Azadi Ka Amrit Mahotsav: Ecological Concerns in Select Punjabi Fiction" विषय पर ऑन-लाईन प्रस्तुति में भाग लिया।
33. दिनांक 8 नवम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष में "सामाजिक और ऐतिहासिक विज्ञान अनुसंधान पद्धति" विषय पर सात दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
34. दिनांक 9 नवम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय तथा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
35. दिनांक 9 नवम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारियों एवं पूर्व छात्र सभ्यत्वों की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी भी उपस्थित रहे।
36. दिनांक 9 नवम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आंतरिक गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता प्रकोष्ठ की विशेषज्ञ समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
37. दिनांक 12 नवम्बर, 2021 को गैयटी थियेटर, शिमला में आयोजित "स्वाधीनता के 75-वर्ष" कार्यक्रम में भाग लिया।
38. दिनांक 15 नवम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल तथा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर जी ने "उमंग फाउंडेशन" द्वारा विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित "दिव्यांगजनों की प्रतिभा का सम्मान" समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
39. दिनांक 23 नवम्बर, 2021 को अमेरिकी दूतावास, नई-दिल्ली से आए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक में भाग लिया।
40. दिनांक 24 नवम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय के ई.आर.पी. सिस्टम को सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से ई.आर.पी., नई-दिल्ली के पदाधिकारियों तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलसचिव, अधिष्ठाता योजना, वित्ताधिकारी, उप-कुलसचिव (मूल्यांकन), प्रभारी कम्प्यूटर केन्द्र एवम् डॉ० सुमेश सूद, सह-आचार्य (ईकडोल) के साथ बैठक की अध्यक्षता की।
41. दिनांक 25 नवम्बर, 2021 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शिमला के अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा विश्वविद्यालय के अधिशासी अभियन्ताओं (निर्माण एवम् रख-रखाव) के साथ विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
42. दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय सभागार में शारीरिक शिक्षा एवम् युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित खेल-कूद एवम् अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित 49वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की।
43. दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय के डॉ. केशव बलीराम हेडगेवार समिति कक्ष में आयोजित "संविधान दिवस" कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के माननीय शिक्षा मन्त्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने मुख्य-अतिथि के रूप में भाग लिया।
44. 29 नवम्बर, 2021 को विश्वविद्यालय के गणित विभाग द्वारा आयोजित "वैदिक गणित" ऑन-लाईन कार्यशाला की अध्यक्षता की।

अब मैं, विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह करता हूँ कि आज के लिए प्रस्तावित सत्र के परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या-2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 21.08.2021 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 21.08.2021 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया।

मद संख्या-3 : कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 21.08.2021 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 21.08.2021 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट कर अनुमोदित किया।

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 21.08.2021 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट कर निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित किया:-

मद संख्या 15:- The Executive Council approved:-

1) The Extra Ordinary Leave (Without Pay), in public interest, in favour of Prof. Sat Prakash Bansal, Professor, Institute of Vocational Studies, HPU, Shimla-5 in term of provision of Ordinance 36.1(b) and Ordinance 36.4 (d) of the First Ordinances of HP University w.e.f. 12.06.2018 to 24.07.2021 on his appointment as Vice-Chancellor, HP Tehnical University, Hamirpur.

2) The Extra Ordinary Leave (Without Pay), in public interest, in favour of Prof. Sat Prakash Bansal, Professor, Institute of Vocational Studies, HPU, Shimla-5 in term of provision of Ordinance 36.1(b) and Ordinance 36.4 (d) of the First Ordinances of HP University to join as Vice-Chancellor of Central University of Himachal Pradesh w.e.f. 27.07.2021 for a period of five years or till the date of his superannuation in this University.

यथा स्थान चर्चाएँ मद संख्या-1 The Executive Council vide item No. 1 of "On the spot item" of its meeting held on 21.08.2021 had approved one supernumerary seat for admission in Ph.D. in every Department for the wards of HP University working employees (Teaching and Non-teaching) with one time payment/ remittance of Rs. 1,00,000 (One lac). However, the Executive Council after detailed deliberations approved one supernumerary seat for admission to Ph.D. course in each Department for the wards of HP University working employees and retirees without Entrance Test with the regular admission schedule. However, Dr. Anil Kumar Jaryal, Member Executive Council expressed his dissent.

After detailed deleberations the Council also decided that one supernumerary seat each in all Ph.D. Courses be reserved for Assistant Professors of the University as well as for College teachers separately.

मद संख्या-4 : माननीय कुलपति महोदय द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12-C(7) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिए गए निर्णय के संदर्भ में कृत कार्रवाई कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ/ पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है।

कुलपति महोदय ने उपरोक्त निहित शक्तियों के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की है।

मद संख्या-5 कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त बारे।

कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समयावधि में कोई मद प्राप्त नहीं हुआ है।

मद संख्या-6: To place before the Executive Council the matter regarding the nomination of one Member on the Finance Committee under Statute 14(i)(3) of the First Statutes of the Himachal Pradesh University for consideration and decision.

.....
The Executive Council nominated Prof. N.K. Sharda, Member of Executive Council to the Finance Committee under Statute -14(i)(3) of the First Statutes of the University. His name was proposed by Prof. P.K. Garga and seconded by Prof. Nagesh Thakur.

मद संख्या-7: To place before the Executive Council the matter regarding grant of Extra Ordinary Leave (without pay) w.e.f. 11.06.2018 (AN) to 24.07.2021 on his appointment as Vice-Chancellor, H.P. Technical University, Hamirpur in respect of Dr. Sat Prakash Bansal, Professor, Institute of Vocational Studies, H.P. University, Shimla-5 under the provision of Ordinance 36.4(d) of the First Ordinances of Himachal Pradesh University.

.....
Necessary amendment has been incorporated under item No. 3 above.

मद संख्या-8: To place before the Executive Council, the Gazette notification No. F. 9-1/2010 (PS/MISC) Pt. Vol. I dated 11.10.2021 circulated by the Secretary, University Grants Commission vide letter F.No. 9-1/2010 (PS/MISC) pt. Vol-II dated 12.10.2021 regarding UGC (Minimum Qualifications for Appointment of Teacher and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Amendment Regulations, 2021 for its consideration and approval.

.....
The Executive Council approved the adoption of UGC guidelines issued vide F.No. 9-1/2010 (PS/Misc) pt. Vol-II dated 12.10.2021, as per annexure, with regard to extend the date of applicability of Ph.D. as mandatory qualification for direct recruitment of Assistant Professors in the Universities from 01.07.2021 to 01.07.2023.

मद संख्या-9: To place an item before the Executive Council of the University for seeking approval to adopt University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020 published in the Gazette of India dated 04.09.2020 to run courses through Open Distance Learning (ODL) mode (ICDEOL) Himachal Pradesh University, Shimla as per Annexure-A.

.....
The Executive Council accorded its approval for adoption of UGC Regulation-2020 issued vide Notification No. F.1-1/2020 (DEB-I) dated 04.09.2020 as per Annexure.

मद संख्या-10: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 22.09.2021 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

.....
कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 22.09.2021 की सिफारिशों को संलग्नकानुसार अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा नए सृजित पदों को रोस्टर अपनाकर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार विज्ञापित करने का भी अपनी स्वीकृति प्रदान की।

कार्यकारिणी परिषद की सम्मानीय सदस्या, श्रीमति राज कुमारी ने वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 की कार्यवाही रिपोर्ट की मद संख्या 5(B) पर दर्शाये गये Jr. Library Attendant के पदों के grade pay रु० 1300/- को मर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार जांच पड़ताल कर उन पदों को विज्ञापित किया जाए।

अतः जांच पड़ताल के उपरान्त Jr. Library Attendant के पदों के grade pay रु० 1300/- को मर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार सही पाया गया है।

श्रीमति राज कुमारी द्वारा वित्त समिति की दिनांक 22.09.2021 की कार्यवाही के खण्ड-III, मद संख्या -6 पर भी आपति दर्ज करवाते हुए अपना पक्ष रखा कि वित्त समिति द्वारा सहायक कुलसचिव के 10 पदों को सैद्धांतिक रूप से सीधी मर्ती द्वारा न भर कर पूर्व की भांति पदोन्नति द्वारा ही भरा जाए। जिस पर कार्यकारिणी परिषद के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस विषय को पुनः परीक्षण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया जो पूरी स्थिति का अवलोकन कर कार्यकारिणी की आगामी बैठक से पूर्व अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:-

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. आचार्य एन०के० शारदा | - अध्यक्ष |
| 2. कुलसचिव | - सदस्य |
| 3. वित्त अधिकारी | - सदस्य |
| 4. उप कुलसचिव (स्थापना) | - संयोजक |

मद संख्या-11: To place before the Executive Council the decision taken by the Standing Committee of Academic Council vide Item No.1 and 7 in its meeting held on 17.09.2021 for consideration and approval.

.....

The Executive Council approved the recommendations of Standing Committee of Academic Council of its meeting held on 17.09.2021 as per annexure. The Council further resolved that the creation of posts and other financial matters relating to the newly created departments be placed before the Finance Committee.

मद संख्या-12: To place before the Executive Committee, the matter to engage the services of Shri Gian Chand Raita as Consultant for six months in the first instance which shall be extended on mutual consent of both the parties on the fixed consultancy fee of Rs. 50,000/- per month to be paid out of the interest amount earned on bank account of Amalgamated Fund of ICDEOL at par with the Pool Officer for the speedy settlement of Advances, updation of Accounts Manual, Settlement of Audit Paras of A.G., H.P. and State Audit Department, updation of cashbook & Annual accounts of the Amalgamated Fund of ICDEOL and any other advice.

.....

The Executive Council after detailed discussions approved to engage the services of Shri Gian Chand Raita, retired Finance Officer of the University initially for a period of six months as Consultant on a fixed salary Rs. 50,000/- per month to be paid out of the interest amount earned from Amalgamated Fund of ICDEOL for the purpose of settlement of advances, updation of Accounts Manual, Settlement of Audit Paras of A.G., H.P. and State Audit Department, updation of Cashbook & Annual accounts of the Amalgamated Fund of ICDEOL and advice on other related issues as may be required by the Hon'ble Vice-Chancellor.

मद संख्या-13: To place before the Executive Council the matter for extension of time period of the Advertisements No. Rectt. 21/2020 and No. Rectt. 22/2020 dated 07.12.2020 issued for filling up of teaching and non-teaching posts.

.....
The Executive Council after detailed discussions decided to extend the time period of Advertisements No. Rectt. 21/2020 and No. Rectt. 22/2020 dated 07.12.2020 for next 6 months for filling up of teaching and non-teaching posts.

मद संख्या-14: To place before the Executive Council matter with regard to provide free Hostel accommodation to the students with disabilities w.e.f. 15.11.2021.

.....
The Vice-Chancellor informed the Members of the Executive Council that Hon'ble Governor/ Chancellor of the University during his visit to the University on 15.11.2021 directed the University authorities to provide free Hostel facilities to the students with disabilities. Accordingly, the Executive Council approved providing of free Hostel facility to the students with disabilities with immediate effect.

अनुपूरक मदें

मद संख्या-15: To place before the Executive Council of Himachal Pradesh University regarding the Establishment of "Centre for Indian Mathematics" in the Department of Mathematics & Statistics, Himachal Pradesh University.

.....
The Executive council approved for Establishment of Centre for Indian Mathematics in the Department of Mathematics and Statistics HP University, Shimla.

मद संख्या-16: To place the matter before Executive Council for grant of relaxation in the approved length of service for promotion to the post of Assistant Librarian in r/o Shri Rajinder Singh, Senior Professional Assistant.

.....
The Executive Council, after detailed deliberations as per advice of the Legal Advisor of the University on the matter, approved the grant of relaxation of six months in the approved length of service for promotion to the post of Assistant Librarian under the Recruitment & Promotion Rules of the University in respect of Shri Rajinder Singh, Senior Professional Assistant.

मद संख्या-17: To place before the Executive Council the matter regarding considering the NFSC/NFST candidates for admission to the Ph.D. programme as over and above seats by adding to the maximum number of students allowed as prescribed by the University Grants Commission.

.....
The Executive Council approved the adoption of guidelines issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment vide No. 11023/8/2019-SCD-V/NFSC dated 01.04.2020 and further notified by the University Grants Commission vide notification No. 82-44/2020(SA-III) dated 29.09.2021 for considering the NFSC/NFST candidates for admission to the Ph.D. programme over and above the seats by adding to the maximum number of students allowed/allotted as prescribed by the University Grants Commission.

-8-

मद संख्या-18: To place before the Executive Council the request of Dr. Dinesh Sharma, Head, Dr. Keshav Baliram Hedgevar Chair with regard to fixation of pay according to Professor Scale.

.....

The Members of the Executive Council after detailed deliberations decided that the matter be placed before the Finance Committee.

यथा स्थान मद

मद संख्या -1: शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की बैठक परिचालन द्वारा (By circulation) दिनांक 03.12.2021 में लिए गए निर्णय एवं सिफारिश को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

.....

स्वीकृत संलग्नकानुसार।

यथा स्थान चर्चाएँ

- माननीय कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा कामधेनु हितकारी मंच, व्यासपुर, हिमाचल प्रदेश जो कि माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा भी सम्मानित हैं तथा दूध एवं दूध से बनी वस्तुओं का उत्पादन करती है, को विश्वविद्यालय के छात्रों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों तथा आगंतुकों की सुविधा हेतु, इस मंच की एक शाखा को विश्वविद्यालय परिसर में खोला गया है। कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कामधेनु हितकारी मंच के उत्पादों को विश्वविद्यालय परिसर में बेचने के लिए उनके मुल्यों को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया:-

1. अधिष्ठाता छात्र कल्याण	--	अध्यक्ष
2. कुलसचिव	--	सदस्य
3. वित्त अधिकारी	--	सदस्य
4. सदस्य विश्वविद्यालय कोर्ट	--	सदस्य
5. सहायक कुलसचिव (शिक्षण)	--	संयोजक

- Representation submitted by Prof. Nagesh Thakur, Member of Executive Council before the Executive Council :-**

A representation submitted by Dr. Arun Sharma, Former Director Forensics Services, Shimla addressed to Prof. Nagesh Thakur, Member of Executive Council, was placed before the Executive Council regarding consideration of his candidature for Adjunct Faculty in the Department of Forensic Science of the University under UGC Scheme. The Executive Council after detailed deliberations constituted a Committee consisting of the following members to examine the matter and submit its report to the Vice-Chancellor for necessary action in the matter:-

1. Dean of Studies	-	Chairman
2. Prof. V.P. Sharma, Member EC	-	Member
3. Chairman, Deptt. of Forensic Science	-	Member
4. Assistant Registrar (Teaching)	-	Convener

- Representations submitted by Smt. Raj Kumari, Member of Executive Council before the Executive Council:-**

On the issue of revocation of expulsion of Mr. Vikram Kaith, student of IVS, the Executive Council after detailed deliberations decided to revoke his expulsion after obtaining the necessary affidavit from the Magistrate. It was also decided that he will remain on probation for a period of one year and if his conduct is not found satisfactory during his probation period, he will stand automatically expelled.

- Smt. Raj Kumari also raised the matter of upgradation of Mr. Sandesh

-9-


Kumar and Mr. Baldev Singh Rana on the analogy of upgradation of Shri Rajinder Singh, Senior Professional Assistant to the post of Assistant Librarian. She also raised the matter of grant of relaxation in Recruitment & Promotion Rules to Shri Puran Dutt, Deputy Registrar and Shri Jagdish Ram Thakur, Assistant Registrar (Retd.) which was rejected by the Finance Committee vide item No. 18 of its meeting held on 22-09-2021. She further suggested that such items may be placed before the concerned Committees for decision.

छात्र प्रतिवेदन

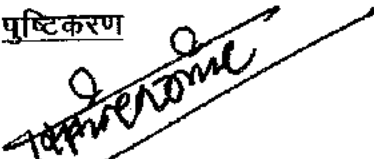
कार्यकारिणी परिषद् ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई (ABVP), National Students' Union of India (NSUI) और Students Federation of India (SFI) द्वारा सौंपे गए अभ्यावेदनों पर चर्चा की जिन्हें कुलपति महोदय ने मदवार मांग-पत्र परिषद् के समक्ष पढ़कर प्रस्तुत किए और कार्यकारिणी परिषद् को सूचित किया कि छात्र-संगठनों द्वारा समय-समय पर उठाई गई उनकी उचित मांगों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है और कुछ पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित के मुद्दों के प्रति सदैव तत्पर रहता है और छात्रों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों पर उचित कार्यवाई प्रशासनिक स्तर पर अमल में लाई जाती रही है।

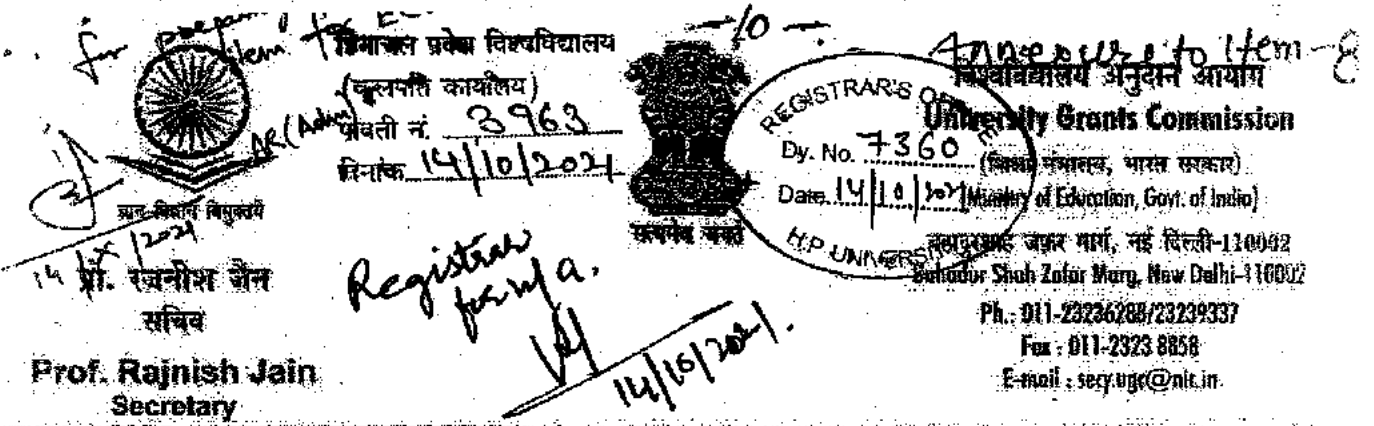
कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य डॉ० अमरजीत सिंह निदेशक (शिक्षा) द्वारा विश्वविद्यालय में चल रहे शैक्षणिक और छात्रागत विकास कार्यों की सराहना की गई।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।


कुलसचिव
सदस्य-सचिव

पुष्टिकरण


(आचार्य सिकन्दर कुमार)
कुलपति / समापति



F.No.9-1/2010(PS/Misc)pt.Vol-II

12th October, 2021

Subject: Ph.D. as mandatory requirement for appointment of Assistant professors in departments of the Universities- Extension of date regarding

Respected Madam/Sir,

As you are aware, UGC (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018 stipulates that Ph.D. degree shall be mandatory qualification for direct recruitment to the post of Assistant professors in universities from 01.07.2021.

The UGC, in view of COVID-19 pandemic, has decided to extend the date of applicability of Ph.D. as mandatory qualification for direct recruitment of Assistant professors from 01.07.2021 to 01.07.2023. Accordingly, an Amendment to the aforesaid Regulations has been notified in the Gazette on 11.10.2021.

Copy of the UGC (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Amendment Regulations, 2021 is attached for your kind consideration and appropriate action.

With kind regards,

Yours sincerely,

Rajnish Jain

(Rajnish Jain)

To,

The Vice-Chancellor of all Universities

Rajnish Jain
16/10/21

So (Ahu)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102021-230355
CG-DL-E-12102021-230355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456]
No. 456]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 2021/आश्विन 20, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ASVINA 20, 1943

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2021

सं. एफ-8-1/2010 (पीएस/मिस०) भाग खंड.1.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के धारा 14 के साथ पठित धारा 26 की उप धारा (1) के खंड (ई) एवं (जी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2018, में निम्नलिखित संशोधन करता है नामतः-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) संशोधित विनियम, 2021 कहा जा सकता है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी) विनियम, 2018, विनियम 3, के उप-विनियम 3.10, में निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

3.10 "दिनांक 01 जुलाई, 2023 से विश्वविद्यालयों के विभागों में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य बर्हता होगी"।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./320/2021-22]

नोट : प्रमुख विनियम का प्रकाशन भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 के अंतर्गत संदर्भ सं. एफ. 1-2/2017 (ईसी/पीएस) दिनांक 18 जुलाई, 2018 को हुआ था।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021

No. F.9-1/2010(PS/MISC)Pt. Vol.I.—In exercise of the powers conferred under clause (e) and (g) of sub-section (1) of section 26 read with section 14 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following amendment in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, in regulation 3, for sub-regulation 3.10, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

3.10 "The Ph.D. Degree shall be a mandatory qualification for direct recruitment to the post of Assistant Professor in Departments of the Universities with effect from 01.07.2023."

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./320/2021-22]

Note: The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary under Part III, Section 4 vide No. F.1-2/2017(EC/PS) dated 18th July, 2018.

Adms.

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05092020-221580
CG-DL-E-05092020-221580

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 2020/भाद्र 13, 1942

No. 354]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020/BHADRA 13, 1942

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मितम्बर, 2020

सं. मि. 1-1/2020 (डेब-I).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12 के खंड (अ) के माध्य पठित धारा 26 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ साध्यों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से एतद्वारा इन विनियमों को बनाता है, नामतः

भाग-I

प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारंभ – (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ ज्ञान अर्जन कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 कहा जायेगा।
- (2) इन विनियमों में मुक्त और दूरस्थ ज्ञान अर्जन पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के साध्यम से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर डिग्री और स्नातकोत्तर स्तर पर डिप्लोमा प्रदान करने के न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया गया है और यह आयोग द्वारा जारी अन्य विनियमों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों अथवा अनुदेशों को निष्प्रभावी नहीं बनायेगा बल्कि उनके अनुपूरक होंगे।

J095 G/2020

(1)

उप कुलसचिव (प्रशासन)

अ०द०शि० एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र

हि०प्र० विश्वविद्यालय, दिल्ली-5।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2020

No. F. 1-1/2020(DEB-I).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and in supersession of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and University Grants Commission (Online Courses or Programmes) Regulations, 2018 except as respect of things done or omitted to be done before such supersession, the University Grants Commission with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations, namely:—

PART I

PRELIMINARY

1. **Short title, application and commencement.**— (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020.
- (2) These regulations lay down the minimum standards of instruction for the grant of degrees at the undergraduate and post graduate levels and grant of post graduate diploma, through Open and Distance Learning mode and Online mode and shall be in addition to and not in derogation of any other regulations, Notifications, Guidelines or Instructions issued by the Commission.
- (3) These regulations shall apply to a University referred to under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), an Institution Deemed to be University under section 3 of the said Act:

Provided that the University Grants Commission may, by order, exempt a Higher Educational Institution or Higher Educational Institutions from the application of these regulations.

- (4) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.


2. **Definitions.**— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Academic Council or Senate” means the body empowered to take decisions regarding all academic matters in a Higher Educational Institution including the decision permitting to offer Open and Distance Learning Programmes and/or Online Programmes in compliance to these regulations;
- (b) “Academic session” means duration of twelve months beginning either in January to February or in the month of July to August, as the case may be, of every calendar year;
- (c) “Act” means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (d) “Centre for Internal Quality Assurance” (CIQA) means a Centre established by a Higher Educational Institution for ensuring the quality of programmes being offered in Open and Distance Learning mode and Online mode, as specified in Annexure-I;
- (e) “Commission” means the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (f) “Conventional mode” means a mode of providing learning opportunities through face to face interaction between the teacher and learner in regular class room environment but does not exclude supplementary instructions if any for the learner through use of online;
- (g) “Credit” means the Unit award gained by a learner with study efforts of minimum number of hours required to acquire the prescribed level of learning in respect of that Unit;

(12)

उप कुलसचिव (प्रशासन)
अण्डोलिंग एवं युक्त अध्ययन केन्द्र
हिन्दू विश्वविद्यालय, शिवपुरी - 5

- Explanation.- For the purpose of this clause, A study effort for one credit shall mean time required by a learner to understand the contents equivalent to 15 hours of classroom teaching or 30 hours including self-learning time required to acquire the prescribed level of learning in respect of that Unit;
- (h) "degree" means a degree specified under sub-section (3) of section 22 of the Act;
- (i) "Dual Mode University" means a Higher Educational Institution offering programmes under conventional mode and also under Open and Distance Learning mode and/or Online mode;
- (j) "e-Learning Material" means and includes contents in the form of structured course material, as a part of one or more courses in the Online Programme, in digital format delivered through Learning Management System, which is *inter alia* self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study, but does not include text-books or guide-books; as defined in these regulations;
- (k) "Examination Centre" means a place where examinations are conducted, *inter alia*, for assessment of the learners pursuing programmes under Open and Distance Learning mode and Online mode and is having the requisite infrastructure relevant to respective mode of education including adequate manpower for smooth conduct of examinations and adhering to such minimum standards as specified in these regulations;
- (l) "Franchising" for the purpose of these regulations, means and includes the practice of allowing, formally or informally, any person or institution or organisation, other than the Higher Educational Institution recognised under these regulations for offering programmes under Open and Distance Learning mode and Online mode, to offer such programmes of study or any related activity on behalf of or in the name of the recognised Higher Educational Institution, and the terms 'franchise' and 'franchisee' shall be construed accordingly;
- (m) "Higher Education" means such education imparted by conventional mode or through open and distance learning mode or through online mode conducting regular classes or through Open and Distance Learning mode or through Online mode, beyond twelve years of schooling leading to the award of a Degree at undergraduate or postgraduate level or Certificate or Diploma or Postgraduate Diploma;
- (n) "Higher Educational Institution" means a university under clause (f) of section 2 and an Institution Deemed to be a University under section 3, of the University Grants Commission Act, 1956, which is offering programmes through conventional mode and/or through Open and Distance Learning mode and/or through Online mode, in the field of higher education or research therein;
- (o) "Information and Communication Technology" means the diverse set of tools and resources used to communicate, create, disseminate, store, manage information and be deployed for realising the goals of interactive teaching-learning, enhancing access, ensuring knowledge cum information sharing, building capacities and management of the educational system and resources;
- (p) "Integrated Programme" shall have the same meaning as defined in UGC Notification on Specification of Degree, 2014;
- (q) "Learning Management System" means a system to keep track of delivery of e-Learning Programmes, learner's engagement, assessment results, reporting and other related details in one centralised location;
- (r) "Learner Support Centre" means a centre established or recognised by the Higher Educational Institution for advising, counselling, providing interface between the teachers and the learners, rendering any academic and any other related service and assistance required, *inter alia*, by the learners of Open and Distance Learning mode;


उप कुलसचिव (प्रशासन)

अ.दू.वि. एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
हि.प्र. विश्वविद्यालय, दिल्ली-5

- (s) "Learner Support Services" means and includes such services as are provided by a Higher Educational Institution in order to facilitate the acquisition of teaching-learning experiences by the learner to the level prescribed by or on behalf of the Commission in respect of a programme of study under Open and Distance Learning mode and/or Online mode;
- (t) "MOOCs" shall have the same meaning as assigned to it under sub-regulation 3.6 of regulation 3 of UGC (Credit Framework for Online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016;
- (u) "Online Mode" means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using internet, e-Learning Materials and full-fledged programme delivery through the internet using technology assisted mechanism and resources;
- (v) "Open and Distance Learning Mode" means a mode of providing flexible learning opportunities by overcoming separation of teacher and learner using a variety of media, including print, electronic, online and occasional interactive face-to-face meetings with the learners or Learner Support Services to deliver teaching-learning experiences, including practical or work experiences;
- (w) "Open University" means a Higher Educational Institution which imparts education only through Open and Distance learning mode and/or Online mode using variety of media including print, electronic, online, information and communication technology educational aids including Open Educational Resources (OERs) or Massive Open Online Courses (MOOCs) etc. and is not having any provision for offering higher education in conventional mode in its Act or Memorandum of Association or other statutory documents governing the Higher Educational Institution;
- (x) "Post Graduate Diploma" means a programme with minimum duration of two years, minimum entry level qualification as graduation, minimum 80 credits and nomenclature as recognised by the Commission and regulatory authority or statutory council, as applicable;
- (y) "Proctored Examination" means the examination conducted under the supervision of approved person or technology enabled proctoring which ensures the identity of the test taker and the integrity of the test taking environment, either in pen-paper mode or in computer based testing mode or in full-fledged Online mode; as permissible in Open and Distance Learning mode and Online mode under these regulations;
- (z) "Prohibited programmes" means such programmes which shall not be permitted to be offered in Open and Distance Learning Mode and Online Mode in Higher Education, as detailed under:
- The programmes in the disciplines (including their allied domains) of Engineering, Medical, Physiotherapy, Occupational Therapy and other Para-Medical disciplines, Pharmacy, Nursing, Dental, Architecture, Law, Agriculture, Horticulture, Hotel Management, Catering Technology, Culinary Sciences, Aircraft Maintenance, Visual Arts and Sports;
 - The research based programmes such as M.Phil and Ph.D;
 - Such other Programmes not permitted to be offered through Open and Distance Learning mode and/or Online mode by any concerned statutory or regulatory body or council:

Provided that, if the concerned statutory or regulatory body or council permits any of the prohibited programmes, as mentioned above, under its domain, in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, the same may be considered by the Commission, and the decision so taken shall be notified by an Order.



उप कुलसचिव (प्रशासन)

आन्दोलन एवं स्वतंत्र अध्ययन बोर्ड

हि० प्र० विश्वविद्यालय, दिल्ली - 5

- (za) "Prospectus" includes any publication, whether in print or e-form, issued for providing fair and transparent information, relating to a Higher Educational Institution and its programmes, to the general public (including to those seeking admission in such Higher Educational Institution) by the management of such Higher Educational Institution or any authority or person authorised by such Higher Educational Institution to do so;
- (zb) "Regional Centre" means a Centre established or maintained by the Higher Educational Institution for the purpose of coordinating and supervising the work of the Learner Support Centres in the region as per its territorial jurisdiction and for performing such other functions as may be conferred on such Centre by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;
- (zc) "Self-Learning e-Module" for Online mode means a modular unit of course material in e-learning form which is *inter alia* self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study and includes contents in the form of a combination of the following e-Learning content, namely:-
- e-Text Materials;
 - Video Lectures;
 - Audio-Visual interactive material;
 - Virtual Classroom sessions;
 - Audio Pod casts;
 - Virtual Simulation; and
 - Self-Assessment Quizzes or Tests;
- (zd) "Self-Learning Material" for Open and Distance Learning mode means and includes contents in the form of course material, whether print or in e-form, which is *inter alia* self-explanatory, self-contained, self-directed at the learner, and amenable to self-evaluation, and enables the learner to acquire the prescribed level of learning in a course of study, but does not include text-books or guide-books;
- (ze) "SWAYAM" (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) means the learning management system as specified in the UGC (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016.

PART II

RECOGNITION PROCESS FOR OFFERING PROGRAMMES UNDER OPEN AND DISTANCE LEARNING (ODL) MODE AND ONLINE MODE

3. Institutional Level Eligibility Criteria.-

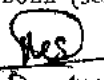
- (A) **Open and Distance Learning Mode:** Any Higher Educational Institution, may apply for offering programmes through the Open and Distance Learning mode, which fulfils the following conditions, namely:-

- (i) shall be accredited by the National Assessment and Accreditation Council with minimum score of 3.01 on a 4-point scale;

or

having rank in top-100 in University category of National Institutional Ranking Framework, at least once in two preceding cycles (at the time of application):

Provided that the NAAC and NIRF Ranking requirements shall be valid for academic session 2020-2021 (session beginning July, 2020 and January, 2021) only and shall be reviewed subsequently by the Commission for the academic session 2021-2022 (session beginning July 2021) and onwards:


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अ० द० शि० एवं दूर० अध्ययन केन्द्र
 नि० प्र० विश्वविद्यालय, दिल्ली-5

Provided further that in view of unprecedented circumstances due to COVID-19 pandemic, the Higher Educational Institutions recognised by the University Grants Commission to offer programmes in Open and Distance Learning mode till the academic session 2019-2020 to enable them to reach the prescribed quality National Assessment and Accreditation Council benchmark and had submitted an undertaking to the effect that they will attain a National Assessment and Accreditation Council score of 3.26 on a 4-point scale before the end of academic session July 2019 - June 2020, and have also submitted an application to the National Assessment and Accreditation Council till 29 February 2020, shall continue to offer programmes, already recognised for the academic session 2019-2020, in Open and Distance Learning mode for a period of one year, academic session 2020-2021, starting from July 2020. Thereafter these Higher Educational Institutions shall be required to attain the eligibility mentioned at sub-clause (i) above:

Provided also that the NAAC condition mentioned above shall not be applicable to the Open Universities already recognised by the Commission for offering Open and Distance Learning Programmes for the academic year 2019-2020. These Open Universities shall be required to submit an affidavit that they shall obtain NAAC accreditation prior to the completion of the current recognition period, as specified in the Commission order already issued, failing which the Commission shall not accord further recognition to the programmes of such Open Universities under Open and Distance Learning mode:

Provided also that Open Universities not recognised by the Commission under UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 shall be required to obtain National Assessment and Accreditation Council (NAAC) accreditation within one year of their becoming eligible for accreditation by the National Assessment and Accreditation Council (NAAC), failing which the Commission shall not accord further recognition to the programmes of such Open Universities under Open and Distance Learning mode:

Provided also that an Institution Deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 shall offer programmes in Open and Distance Learning mode in accordance with the extant Deemed to be University Regulations and also in compliance to the provisions of these regulations;

(B) Online Mode

- (a) Higher Educational Institutions having NAAC score 3.26 and above or having rank in Top-100 in University category of National Institutional Ranking Framework, at least twice in three preceding cycles (at the time of application), shall be permitted to start full-fledged Online programmes without prior approval of the UGC, provided it satisfies all the conditions mentioned in these regulations:

Provided that the Higher Educational Institutions can start maximum of three (03) Under Graduate (UG) programmes and ten (10) Post Graduate (PG) programmes with the approval of its statutory authorities and in strict compliance with the provisions of these regulations:

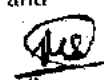
Provided further that the NAAC and NIRF Ranking requirements shall be valid for academic session 2020-2021 (session beginning July, 2020 and January, 2021) only and shall be reviewed subsequently by the Commission for the academic session 2021-2022 (session beginning July 2021) and onwards:

Provided also that Higher Educational Institutions shall be required to submit application and desired information, and comply to all the provisions of the regulations and shall be required to submit an affidavit to the UGC:

Provided also, that in case, the Higher Educational Institutions want to start more than the defined number of programmes, then they shall seek prior permission from the Commission.

- (b) Any Higher Educational Institution, may apply for offering programmes through the Online mode, which fulfils the following conditions, namely:-

- (i) shall be in existence for at least three years; and


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अन्दूजिठ एवं गुणन सहायन केन्द्र
 हि०प्र० विश्वविद्यालय, दिल्ली-5

- (ii) shall be accredited by the National Assessment and Accreditation Council with minimum score of 3.01 on a 4-point scale;

or

shall be in the top-100 in University category in the National Institutional Ranking Framework for at least once in last two preceding cycles (at the time of application):

Provided that the NAAC and NIRF Ranking requirements shall be valid for academic session 2020-2021 (session beginning July, 2020 and January, 2021) only and shall be reviewed subsequently by the Commission for the academic session 2021-2022 (session beginning July 2021) and onwards:

Provided further that the condition mentioned at item (ii) of sub-clause (b) shall not be applicable to the Open Universities already recognised by the Commission for offering Open and Distance Learning programmes or Online programmes for the academic year 2019-2020. These Open Universities shall be required to submit an affidavit that they shall obtain National Assessment and Accreditation Council (NAAC) accreditation prior to the completion of the current recognition period, as specified in the Commission order already issued, failing which the Commission shall not accord further recognition to the programmes of such Open Universities under Online mode:


Provided also that a Higher Educational Institution having National Assessment and Accreditation Council (NAAC) valid score equal or more than 3.26 or having rank in Top-100 in University category of National Institutional Ranking Framework at least twice in three preceding cycles shall be permitted to enroll International Learners also:

Provided also that an Institution Deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 shall offer programmes in Online mode in accordance with the extant Deemed to be University Regulations and also in compliance to the provisions of these regulations.

4. Requirements for Submission of Proposals.—

- (A) **Common Provisions for Open and Distance Learning Mode and Online Mode:** Every Higher Educational Institution eligible as per regulation 3 and intending to offer a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode from the academic session shall make an application to the Commission in the format mentioned in sub-regulation (1) of regulation 5 with documentary evidence for grant of recognition on fulfilment of the following conditions, namely:

- (i) the Higher Educational Institution has complied with the Institutional eligibility criteria as per regulation 3 of these regulations;
- (ii) the Higher Educational Institution has the approval of the statutory bodies under its Act for offering the programme in Open and Distance Learning mode or Online mode, as the case may be;
- (iii) the list of proposed programmes to be offered in Open and Distance Learning mode or Online mode, as applicable, the expected enrolment of learners; the learning outcome of each programmes and other requirements as notified by the Commission from time to time;
- (iv) for the programmes falling under the ambit of a statutory or regulatory authority or regulatory council, the Higher Educational Institution has the approval or recommendations of the respective statutory or regulatory authority or regulatory council for offering the programmes in Open and Distance Learning mode or Online mode, as applicable;


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अ.द.श. एवं युवा अध्ययन केन्द्र
 हि.प्र. विश्वविद्यालय, जिला-5

Explanation: Programmes as mentioned at clause (iv) shall be considered only when these are recommended by the respective statutory or regulatory authority or regulatory council to offer in Open and Distance Learning mode or Online mode, as applicable. Also, statutory or regulatory authority or regulatory council shall either maintain the minimum standards for the programmes in Open and Distance Learning mode or Online mode as stipulated in these regulations or set higher standards while making recommendations to the Commission.

- (v) the entry level qualifications, curriculum, teaching-learning scheme, pattern of question papers for end semester examination or term end examination, pass or fail criteria in Dual Mode University are the same for conventional programme and the proposed Open and Distance Learning programme or Online programme, as applicable, and in case of Open University, these parameters are same for Open and Distance Learning programme and proposed Online programme;
- (vi) weightages to continuous assessment and end semester examinations or term end examinations for the proposed Open and Distance Learning programmes or Online programmes, as applicable, is in conformity with regulation 15;
- (vii) submission of the fee as notified by Commission;
- (viii) a copy of such application is displayed on the website of the Higher Educational Institution by way of self-disclosure;
- (ix) submission of affidavit in the format notified by Commission;
- (x) preparedness status, as decided by the Commission from time to time for various stages of recognition process for the following, namely:-
 - (a) establishing Centre for Internal Quality Assurance as specified in Annexure-I;
 - (b) for establishing Learner Support Centres (Open and Distance Learning programmes) as specified in Annexure-VIII;
 - (c) providing systems for Learner Support Services as specified in Part IV;
 - (d) availability of Director, academic and other staff, qualified Counsellors/ Co-ordinators/ Mentors, (for ODL and Online modes, as applicable) meeting such standards of competence as specified in Annexure-IV;
 - (e) administrative arrangements, infrastructure and technology support for effective delivery of programmes in Open and Distance Learning and Online mode as specified in Annexure- IV.

Explanation: A Private University established under a State Act shall be eligible to offer programmes under Open and Distance Learning mode through its Head Quarters only and duly recognised off-campus centres. A Private University shall not offer programmes under Open and Distance Learning mode through any Learner Support Centre.

(B) Provisions for Open and Distance Learning Mode:

- (i) The Higher Educational Institution shall adhere to the policy of territorial jurisdiction as specified in Annexure-III;
- (ii) A Higher Educational Institution shall be eligible to offer only those degree programmes at undergraduate and postgraduate levels and post graduate diploma programmes, which it has already been offering in conventional mode of classroom teaching and from which at least one batch has passed out:

Provided that this sub-clause shall not be applicable to Open Universities:

Provided further that Science based programmes, which require hands-on experience, experimental setup, shall be offered only by the Higher Educational Institutions having NAAC score of 3.26 and above or by the Open universities or by the Higher Educational Institutions having rank in top-100 in University

उप कुलसचिव (प्रशासन)
अ०००३१० एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
हि०००० विश्वविद्यालय, शिमला - 5


category of National Institutional Ranking Framework (NIRF), at least twice in three preceding cycles:

Provided also that the Science based programmes shall be offered from the Head Quarters and/or only from such Learner Support Centres which are offering same programme under conventional mode atleast for seven years.

- (iii) The application is accompanied with evidence of having prepared the self-learning materials required as decided by the Commission, for the proposed programmes of study, duly approved by the statutory bodies of the Higher Educational Institutions empowered to decide on academic matters.
- (iv) The application is accompanied with evidence of availability/ preparedness, as decided by the Commission from time to time, of Open and Distance Learning resources, adequate for effective delivery of all the proposed programme(s) of study considering the expected enrolment of learners.

(C) Provisions for Online Mode:

- (i) Territorial Jurisdiction shall not be applicable to the Higher Educational Institutions for offering recognised Online programmes under these regulations.
- (ii) A Higher Educational Institution, shall be eligible to offer only those degree programmes at undergraduate and postgraduate levels and post graduate diploma programmes, which it has already been offering in conventional mode of classroom teaching or in Open and Distance Learning mode and from which at least one batch has passed out:
Provided that any programme requiring practical or laboratory course as a curricular requirement, shall be prohibited through Online mode, except in cases where practical component is limited to programming and coding including software tools.
- (iii) The application is accompanied with demonstrated capability of Higher Educational Institution for development and production of Online Programmes for the proposed programmes of study, duly approved by the statutory bodies of the Higher Educational Institution empowered to decide on academic matters.
- (iv) The application is accompanied with evidence of Higher Educational Institution having access to SWAYAM or other learning platform for the proposed programmes of study, duly approved by the statutory bodies of the Higher Educational Institution empowered to decide on academic matters, for-
 - (a) learner authentication - Integrated with Aadhaar or other government recognised identity for Indian learners and Passport for foreign learners;
 - (b) learner registration - through a web application with supporting documents;
 - (c) payment gateway - using Digital Payment system;
 - (d) learning management System - which tracks the delivery of Programme, learner's engagement, assessment, results, and reporting supported by analytical tools that can help the teachers to extract and use the relevant reports.
- (v) The application is accompanied with the evidence of ability to conduct proctored examinations with all the security arrangements ensuring transparency and credibility of the examinations.
- (vi) The application is accompanied with evidence to ensure that the Higher Educational Institutions offering Online Programmes is not having any franchise arrangement with a private service provider and the ownership of offering Online programmes including all the required components of Online education and compliance to all the provisions of the regulations shall be that of Higher Educational Institutions only.
- (vii) The application is accompanied with evidence of availability/ preparedness, the administrative arrangements for supportive services for effective delivery of all the proposed programme(s) of study considering the expected enrolment of learners.


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अन्दोलन एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 विश्वविद्यालय, दिल्ली-5

5. **Programmes Recognition Process.**— (1) A Higher Educational Institution intending to offer a programme through Open and Distance Learning mode and/or Online mode for academic session and for subsequent years, shall make an online application, as invited by the Commission in the format notified by Commission and upload the same on the specified portal along with scanned copy of all the documents specified therein, at least three months prior to commencement of the academic session of the programme intended to be offered by such Higher Educational Institution:

Provided that the programmes of the Higher Educational Institutions recognised by the Commission under UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and UGC (Online Courses or Programmes) Regulations, 2018 shall remain valid programmes for the period as mentioned in the Commission Orders. These Higher Educational Institutions shall submit an affidavit to the Commission that they shall comply to provisions of these regulations prior to the beginning of next academic session from the notification of these regulations. However, after the expiry of the recognition period as specified in the already notified Commission Orders, the Higher Educational Institution for the said programmes shall be required to apply afresh as per the sub-regulation (1) of regulation 4.

- (2) The Commission shall process the application received under sub-regulation (1) of regulations 5 in the following manner, namely:-

- (i) any deficiency or defect in the application shall be communicated by the Commission to the Higher Educational Institution and the Higher Educational Institution shall be required to remove or rectify such deficiencies or defects with the necessary documents or information, if any, within fifteen days;
- (ii) where the Higher Educational Institution has made an application for offering programme(s) in Open and Distance Learning mode and/ or Online mode, the Commission may cause an inspection, in respect of such programme(s), of the Higher Educational Institution at its discretion through an Expert Committee;
- (iii) the Commission shall examine the application with the help of an Expert Committee constituted by Chairman of the Commission and the recommendations of the Committee shall be placed before the Commission for its consideration.


- (3) After processing the application in the manner laid down under sub-regulation (2) of regulation 5 for offering programme(s) through Open and Distance Learning mode and/or Online mode, the Commission shall-

- (i) if it is satisfied that such Higher Educational Institution fulfils the conditions laid down and the quality parameters specified under these regulations, pass an order granting recognition to such Higher Educational Institution for a period of five years in respect of such programmes either in Open and Distance Learning mode or in Online mode or in both modes, as it may specify in the order, and subject to such conditions as it may specify:

Provided that while passing an order, where the Commission does not grant recognition in respect of one or more programmes, the Commission shall specify the grounds of such refusal in the order.

- (ii) If the Commission is of the opinion that such Higher Educational Institutions does not fulfill the requirements laid down in clause (i) in respect of any of the programme intended to be offered by the Higher Educational Institution either in Open and Distance Learning mode or in Online mode or in both modes, it shall pass an order refusing recognition to such Higher Educational Institution for reasons to be recorded in writing.

- (4) Every order granting or refusing recognition to a Higher Educational Institution for programme(s) in Open and Distance Learning mode and/or Online mode under sub-regulation (3) of regulation 5 shall be communicated in writing for appropriate action to such Higher Educational Institution and to the concerned State Government and the Central Government.


उप कुलसचिव (प्रशासन)
अंशुमति एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
हिप्पो विश्वविद्यालय, शिमला-5

- (5) Every Higher Educational Institution, in respect of which recognition for programme(s) has not been granted by the Commission, shall discontinue the programme(s) in Open and Distance Learning mode and/or Online mode with immediate effect:
Provided that the learners already enrolled in the currently recognised programmes shall be allowed to complete the Programmes in the laid down manner.
- (6) Every Higher Educational Institution which is accorded recognition by the Commission under these regulations shall offer programme(s) in Open and Distance Learning mode and/or Online mode from the academic session as mentioned in the Commission Order.
- (7) No Higher Educational Institution shall offer any Open and Distance Learning Programme and/or Online Programme and admit learners thereto unless it has been granted recognition by the Commission and admission shall not be made in anticipation of the recognition.
6. **Appeal.**— (1) Any Higher Educational Institution aggrieved by an order made under sub-regulation (3) of regulation 5 and withdrawal of recognition under sub-regulation (1) of regulation 7 may prefer an appeal to the Commission within a period of thirty days from the date of issue of communication;
- (2) No appeal shall be accepted after the expiry of the prescribed period under sub-regulation (1).
- (3) Every appeal made under these regulations shall be accompanied by a copy of the order appealed against along with a fee of Rs. 10,000/- per programme.
- (4) The procedure for disposing off an appeal shall be as under:
(i) The Commission shall examine the appeal with the help of a Standing Appellate Committee constituted by Chairman of the Commission.
(ii) The Committee will examine the appeals of the Higher Educational Institutions received against the Commission decision for rejection of programme and make recommendation whether to confirm or reverse the Commission decision on rejection of programmes.
- (5) The Commission may confirm or reverse the order appealed against.
- (6) The decision of the Commission shall be final and binding on the Higher Educational Institutions.
7. **Withdrawal of recognition.**— (1) Where the Commission is, on its own or on any representation received from any person, or any information received from any authority or a statutory body, or on the basis of any enquiry or inspection conducted by it, satisfied that a Higher Educational Institution has contravened any of the provisions of these regulations or guidelines and orders made or issued there under, or has submitted or produced any information and documentary evidence which is found to be false at any stage or any condition subject to which recognition under clause (i) of sub-regulation (3) of regulation 5 has been granted, it may withdraw recognition of such Higher Educational Institution in respect of such programme(s) as it may specify, for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such order against the Higher Educational Institution shall be passed unless a reasonable opportunity of making representation against the proposed order has been given to such Higher Educational Institution:

Provided further that the order withdrawing or refusing recognition passed by the Commission shall come into force with immediate effect.

- (2) If a Higher Educational Institution offers any programme in Open and Distance Learning mode or Online mode after the coming into force of the order withdrawing recognition under sub-regulation (1) or fails to obtain recognition under these regulations for offering programmes in Open and Distance Learning mode or Online mode for academic session and subsequent academic sessions, the degree obtained pursuant to such programme or after undertaking a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode in such Higher Educational Institutions, shall not be treated as a valid qualification:

(स)
उप कुलसचिव (प्रशासन)
अठ्ठार्विंश एवं युक्त अध्ययन केन्द्र
विश्वविद्यालय, दिल्ली-5


Provided that the programmes of the Higher Educational Institutions recognised by the Commission under UGC (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and UGC (Online Courses or Programmes) Regulations, 2018 shall remain valid programmes for the period as mentioned in the Commission Orders.

- (3) In the event of any Higher Educational Institution found offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode without recognition of the Commission or in violation to any of the provisions of these regulations and guidelines or orders made there under, the Commission may-
- (i) issue Show-Cause Notice;
 - (ii) withdraw the recognition of a programme or some programmes or all the programmes for an academic session or withdraw the recognition, maximum up to next five academic sessions not only for such Open and Distance Learning programmes and/or Online programmes but also for other programmes offered by the institutions in regular and conventional mode;
 - (iii) if, in spite of above, the Higher Educational Institution is found continuing the violations, a First Information Report may be lodged against the officials or management of the errant Higher Educational Institution to take action as per law;
 - (iv) withhold or debar from receiving University Grants Commission grants;
 - (v) refer the matter to the Central or State Government, as applicable for withdrawal of Higher Educational Institution status;
 - (vi) take action as per the provisions of the Act or Rules or Regulations as applicable to the Higher Educational Institution;
 - (vii) put in the public domain a list of such defaulters Higher Educational Institutions;
 - (viii) in case of a non-recognized Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, punitive action mentioned at clauses (i), (iii), (v) and (vii) shall be exercised by the Commission keeping in view future of the learners.

PART III

MAINTENANCE OF INFRASTRUCTURAL, ACADEMIC AND OTHER QUALITY STANDARDS BY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

8. **Systems Management, Structure and Processes.**— (1) An Open University shall have designated Schools of Studies for design and development of programmes in Open and Distance Learning mode and, which shall be headed by a regular functionary on full time dedicated basis not below the rank of an Associate Professor and shall have appropriate and adequate academic, technical, administrative staff and infrastructural resources as specified in **Annexure-IV**. The Open University shall also have appropriate departments such as operational department for admissions, learner support and examinations.
- (2) An Open University shall have a designated Centre for Online Education (COE) for operationalising the programmes designed and developed by the Schools of Studies for Online Learning mode and, which shall be headed by Director, a regular functionary on full time dedicated basis not below the rank of an Associate Professor and shall have appropriate and adequate academic, technical, administrative staff and infrastructural resources as specified in **Annexure-IV**.
- (3) A Higher Educational Institution other than an Open University shall have a designated Centre for Distance and Online Education (CDOE) for operationalising the programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, which shall be headed by Director, a regular functionary on fulltime dedicated basis not below the rank of an Associate Professor and shall have appropriate and adequate academic, technical, administrative staff and infrastructural resources as specified in **Annexure-IV**.


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 आन्दोलन एवं सुसज्जित अध्ययन केन्द्र
 हि.प्र. विश्वविद्यालय, शिवाजी-5

- (4) A Higher Educational Institution shall plan, implement, coordinate and monitor operationalisation and quality assurance of the programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode and shall ensure adherence to the regulations and guidelines of the Commission and other regulatory authorities.
9. **Self-regulation through disclosures, declarations and reports.**— A Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall display on its website a joint declaration by authorised signatories, Registrar and Director of Centre for Internal Quality Assurance, authenticating that the following documents have been uploaded on the Higher Educational Institution's website, namely:—
- the establishing Act and Statutes there under or the Memorandum of Association, as the case may be or both of the Higher Educational Institution, empowering it to offer programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode;
 - copies of the letters of recognition from Commission and other relevant statutory or regulatory authorities;
 - programme details including brochures or programme guides inter alia information such as name of the programme, duration, eligibility for enrolment, programme fee, programme structure;
 - programme-wise information on syllabus, suggested readings, contact points for counselling/mentoring, programme structure with credit points, programme-wise faculty details, list of supporting staff, list of Learner Support Centres with addresses and contact details (for Open and Distance Learning mode), their working hours and counselling (for Open and Distance Learning mode)/mentoring (for Online mode) Schedule;
 - important schedules or date-sheets for admissions, registration, re-registration, counselling/mentoring, assignments and feedback thereon, examinations, result declarations etc.;
 - detailed strategy plan related to Online programme delivery, if any including learning materials offered through Online and learner assessment system and quality assurance practices of Online learning programmes;
 - the feedback mechanism on design, development, delivery and continuous evaluation of learner-performance which shall form an integral part of the transactional design of the Open and Distance Learning mode programmes and/or Online programmes and shall be an input for maintaining the quality of the programmes and bridging the gaps, if any;
 - information regarding all the programmes recognised by the Commission;
 - data of year-wise and programme-wise learner enrolment details in respect of degrees and/or post graduate diplomas awarded;
 - complete information about 'Self Learning Material' including name of the faculty who prepared it, when was it prepared and last updated for Open and Distance Learning Programmes; Similarly information about 'E-Learning Materials' in 4 quadrants in case of Online programmes;
 - a compilation of questions and answers under the head 'Frequently Asked Questions' with the facility of online interaction with learners providing hyperlink support for Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes;
 - list of the 'Learner Support Centres' along with the number of learners who shall appear at any examination centre and details of the Information and Communication Technology facilities available for conduct of examination in a fair and transparent manner, for Open and Distance Learning programmes;
 - list of the 'Examination Centres' alongwith the number of learners in each centre, for Open and Distance Learning programmes;

418

उप कुलसचिव (प्रशासन)
अनुसंधान एवं सुपन्न अध्ययन केन्द्र
हिंदू विश्वविद्यालय, शिमला - 5

- (n) details of proctored examination in case of Online programmes for all the exams;
- (o) details of proctored examination in case of end semester examination or term end examination of Open and Distance Learning programmes;
- (p) academic Calendar mentioning period of the admission process along with the academic session, dates of continuous and end semester examinations or term end examinations, etc;
- (q) reports of the third party academic audit to be undertaken every five years and internal academic audit every year by Centre for Internal Quality Assurance.
- 10. Quality Assurance.—** (1) A Higher Educational Institution recognised for offering programme(s) in Open and Distance learning mode and/or Online mode shall, take the following steps, namely:-
- establish a Centre for Internal Quality Assurance, common for programmes in the Open and Distance Learning mode and/or Online mode as per Annexure I;
 - follow the Quality Assurance Guidelines on learning materials in multiple media, curriculum and pedagogy, as specified by the Commission in Annexure VI and shall post its quality assurance mechanism on the website;
 - take adequate measures for training and capacity building of its teaching and administrative staff and counsellors/co-ordinators/mentors at regular intervals;
 - ensure that the quality of programmes of study offered through Open and Distance Learning mode and/or Online mode are maintained at par with standards as defined for the conventional mode of teaching, in conformity with the provisions as stipulated under section 22 of UGC Act, 1956 and UGC notification on specification of degrees, 2014 as notified by the Commission;
 - exhibit the copies of the approval letters duly obtained or received from the concerned statutory or regulatory authority or council to offer programmes under its domain on the Higher Educational Institution's website as well as against the name of the each programmes in the brochure or bulletin of the respective Higher Educational Institution and inform the same to the University Grants Commission from time to time in the matter:
- Provided that in case of violation of these regulations, the provisions specified under sub-regulation (3) of regulation 7 shall apply;
- ensure that the academic and instructional facilities at its Learner Support Centres for Open and Distance Learning mode, and information resources for online delivery of programmes meet the guidelines laid by the Commission from time to time, and are commensurate with the number of programmes and enrolments thereto.
- (2) Every Higher Educational Institution recognised to offer programme in Open and Distance Learning Mode and/or Online mode shall adhere to all the provisions regarding mandatory disclosure of information as stipulated under regulation 9.
- 11. Teachers and Academic Staff working in Higher Educational Institutions.—** (1) Teacher and equivalent academic staff in the Schools of Studies or Centre of Distance and Online Education or Centre for Online Learning and Learner Support Centres (for Open and Distance Learning only) shall be appointed as per the minimum qualifications laid down in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018 and there shall be positions for Assistant Professor, Associate Professor and Professor in the Schools of Studies or Centre for Online Education for an Open University or in the Centre of Distance and Online Education for a dual mode University on permanent and/or full time dedicated basis, for performing academic functions.
- (2) Every teacher, beside his or her academic responsibilities shall participate in teaching.

उप कुलसचिव (प्रशासन)
अठ्ठोशो एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
हि०प्र० विश्वविद्यालय, शिमला-5

curriculum and course material development, undertake examination or test or evaluation or invigilation work, general assistance to learners in removing their academic difficulties, and participate in extracurricular and institutional support activities as required.

- (3) The workload of a teacher shall take into account teaching, research and extension activities, preparation of lessons, evaluation of assignments, term papers etc. shall be in accordance with the guidelines issued by the Commission:

Provided that the time spent on extension work where it forms an integral part of the course specified shall count towards the teaching load.

- (4) The number of full-time dedicated teachers exclusively for Open and Distance Learning Mode and/or Online mode and other administrative and technical staff shall be appointed as stipulated under Annexure-IV of these regulations.

- (5) The details of the faculty in the Schools of Studies or Centre for Online Education or Centre of Distance and Online Education of the Higher Educational Institution and in the Learner Support Centres (for Open and Distance Learning Mode only) shall be declared on the website of the Higher Educational Institution and be linked to Aadhaar details or other Government identifiers.

12. **Use of e-resources for Open and Distance Learning mode.**— (1) A Higher Educational Institution offering programme(s) in Open and Distance Learning mode shall take such measures as are necessary to blend Information Communication Technologies (ICT) including those developed by National Mission on Education through Information and Communication Technology, for enhancing effectiveness of teaching – learning process, and administrative functioning and for maintenance of updated information at all times in respect of status of admissions, registration, for managing teaching-learning activities through online support for interactive learning with learner feedback, to facilitate the use of Open Educational Resources (OER), Massive Open Online Courses and for continuous as well as comprehensive evaluation, certification, and other aspects of learner support.

- (2) A Higher Educational Institution may allow up to forty per cent. of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the Online Learning courses/ Massive Open Online Courses.

13. **Programme Launching Process for Higher Educational Institution.**—

(A) **Common Provisions for Open and Distance Learning Mode and Online Mode:**

- (1) The proposed programmes shall be designed for conventional learners, as well as for working professionals and other individuals aspiring to acquire knowledge and associated academic credentials through Open and Distance Learning Mode and/or Online mode.

(2) **Minimum and Maximum Duration of Programme:**

- (i) The minimum duration for completion and award of degrees at the undergraduate and postgraduate levels in Open and Distance Learning mode and Online mode shall be in accordance with the UGC notification of specification of degrees, 2014;
- (ii) The minimum duration for completion and award of post graduate diploma shall be two years;
- (iii) The maximum duration for completion and award of degree at the undergraduate and postgraduate levels or post graduate diploma in Open and Distance Learning mode and Online mode shall be double the minimum duration of the respective programmes as per items (i) and (ii).

- (3) Before offering any programme, the Higher Educational Institution shall prepare a Programme Project Report as per Annexure-V for each programme which shall include the following, namely:-

- (i) information on relevance of programme to the Institution's mission and goals, objectives of the programme, nature of prospective target group of learners, and




उप कुलसचिव (प्रशासन)

अन्दोलन एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र

हिंमन् विश्वविद्यालय, शिमला-5

- appropriateness of Open and Distance Learning mode and/or Online mode for acquiring specific competencies or skills;
- (ii) instructional design which shall include duration of programme(s), faculty and support staff requirements, instructional delivery mechanisms, identification of media – print, audio or video, online, computer aided, and learner support service systems;
 - (iii) procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation;
 - (iv) details of laboratory support required for the programme(s), if any;
 - (v) library Resources;
 - (vi) cost estimate of the programme and the provisions there for, indicating the amount assigned for programme development, delivery and maintenance;
 - (vii) quality assurance mechanism and expected programme outcomes;
 - (viii) curriculum and detailed syllabi of the programme(s); and
 - (ix) guidelines on launching programme(s) design, development and any such matters as specified by the Commission and other regulatory bodies which shall be followed by the Higher Educational Institutions.
- (4) A Higher Educational Institution other than an Open Universities shall offer programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode with total credits and minimum duration for the programmes kept same as that of corresponding programmes in conventional mode.
- (5) An Open University shall offer programmes in Open and Distance mode with total credits and minimum duration for programmes kept same as that of corresponding programmes in conventional mode by the Central and/or State Universities and for offering programmes in Online mode, total credits and minimum duration for programme shall be the same as that of corresponding programme in Open and Distance Learning mode.
- (6) The Programme Project Report shall be approved by the appropriate authorities of the Higher Educational Institution, which shall put in place a monitoring mechanism to ensure its proper implementation.
- (B) **Provisions for Open and Distance Learning mode:** A Higher Educational Institution offering programme in Open and Distance Learning mode shall, in order to facilitate the pace of learning and multiple choice for learners, prepare Self Learning Material as per Annexure-VI and Annexure-VII taking into consideration the following, namely:-
- (i) Self Learning Material has clearly stated objectives, intended learning outcomes, study guidance and advice for the learners as to how to optimally use the material and suggestive related reference material to enhance the learning experience, and linkage within the text with other media (for digital SLM) is maintained for easy referencing and progress;
 - (ii) At least 60 per cent. of Self Learning Materials shall be developed by the in-house faculty of the Higher Educational Institution and the remaining per cent. of the materials can be sourced from available resources such as other Higher Educational Institutions, Open Educational Resources (OER), and SWAYAM, duly approved by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;
 - (iii) Self Learning Materials developed and offered by it is self-explanatory, self-contained, illustrative, easily comprehensible, and in manageable modules such as units and blocks;
 - (iv) Self Learning Materials provides adequate mechanism for the learners to provide feedback on their understanding of the subject;


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अ० दूर० शि० एवं सुदूर अध्ययन केन्द्र
 वि० प्र० विश्वविद्यालय, दिल्ली - 5

- (v) Self Learning material is revised periodically from the perspective of improving quality and learner support:

Provided that a Higher Educational Institution shall prepare the Self Learning Material only after approval of the Programme Project Report:


Provided further that no programme in Open and Distance Learning mode shall be launched by a Higher Educational Institution unless it has prepared the Self Learning Material taking into consideration the above factors.

- (C) **Provisions for Online mode.**— (1) A Higher Educational Institution offering programme in Online mode shall prepare the E-Learning Materials as per Annexure-VI and Annexure-VII, taking into the consideration the following, namely:—

- (i) The Online Learning shall have the four quadrant approach; as per UGC (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016;
- (ii) At least 60 per cent. of e-Learning Material shall be developed by the in-house faculty of the Higher Educational Institution and remaining per cent. of the material can be sourced from available e-resources such as Open Educational Resources (OER), SWAYAM or other source, duly approved by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;
- (iii) A Higher Educational Institution shall have demonstrated capability, for developing and production of Online programmes with the technology for production including in-house or duly out-sourced production facilities for converting the courses of a Programme into Online Programmes, defined as under—
 - (a) learning videos with recording or dubbing or editing facilities for graphics or animation creation;
 - (b) e-content for reading and improving comprehension of learners;
 - (c) tests and assignments that test the understanding;
 - (d) discussion forum that clarifies the doubts of the learners.
- (iv) The Online programmes' delivery shall be through the SWAYAM portal or any other learning platform duly approved by the Commission on the recommendation of the Technical Expert Committee broadly complying to the features mentioning at Annexure-IX.
- (v) The Programme offered under Online mode shall conform to the condition that apart from the Programme delivery, other components such as Counselling Process, Online Application Processing and fee payment shall also be provided through Online mode.

- (2) The Higher Educational Institution may evolve the curricular aspects, assessment criteria etc. for the award of Degree at the undergraduate and postgraduate levels and/or Post Graduate Diploma adopting the following requirements, namely:—

- (i) the course content for each course shall be clearly defined, each having modular e-content, delivery online in a structured format, with clearly spelt out learning outcomes which learners are expected to attain at the end of the module;
- (ii) programmes (including courses in a programme) architecture shall permit the online teacher or instructor to add multi-media enriched and interactive content, activities and assessments to extend learning opportunities and shall be easy to navigate;
- (iii) availability of assessment mechanism - each course in the Online Programme shall have a precise assessment mechanism for the identified learning outcomes at each level for both continuous formative and summative assessments;
- (iv) identified technological interface and interoperability - the Online Programme shall be able to utilise a variety of technology tools, shall have a user friendly interface


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 जे.ए.पी. एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 जे.ए.पी. विश्वविद्यालय, दिल्ली - 5

and meet accessibility standards for interoperability and access for learners with special needs.

- (3) Learners' Requirements for Enrolment to Online Programmes - Learners to be enrolled for the Online Programmes shall be acquainted with the requisite information or literacy skills for which there shall be a helpline for technical assistance throughout the semester/course of study.
- (4) Learner's Authentication Requirements -
 - (i) the Higher Educational Institutions shall exercise proper learner's authentication practice to ensure the academic integrity and all the Indian learners, at the time of enrolment, synchronous /asynchronous participations and all assessments for examinations, shall be required to provide the Aadhaar number or other government recognised identifier, as applicable and verify their information for authentication for which necessary infrastructure or support shall be provided to them by the Higher Educational Institutions;
 - (ii) all the International learners shall authenticate their credentials through Passports only. These learners shall pursue Online programmes from their country of residence.
- (5) Active Engagement of the Learners - Active engagement in Online or virtual class shall be monitored via participation in asynchronous or synchronous discussions, assignment activity and Programme involvement and the analytics of Learning Management System shall be used for ensuring the learner's participation at least for two hours every fortnight.
- (6) Technical Know-how or Skills Requirements - The Higher Educational Institutions shall have defined criteria or guidelines for the technical know-how and skill requirements of the Online Programme Coordinators, Course Coordinators, Course Mentors and other staff and ascertain that all the resources are competent to deliver online education effectively from the learner learning perspective and continuous upgradation of skills shall be essential for embracing newer methodologies and Information and communication technology tools for enhancing the development and delivery of the Online Programmes in the long run.
- (7) Learners' Support Services and E-Learning Materials - Higher Educational Institutions shall provide adequate support for advising, counselling, mentoring and guidance so as to ensure the best possible learning experience for the learners and there shall be clear guidelines on academic integrity and netiquette (internet etiquette) expectations regarding lesson activities, group discussions, chats and plagiarism.
- (8) A Higher Educational Institution shall provide the details of all International learners enrolled immediately after the beginning of the academic session to the Ministry of External Affairs, Ministry of Education and University Grants Commission.


PART IV

ADMISSIONS, EXAMINATIONS AND LEARNER SUPPORT

14. Admission and fees.— (1) On being granted recognition under clause (i) of sub-regulation (3) of regulation 5, a Higher Educational Institution shall admit learners to its recognised programmes only from the academic session specified in the Commission order:

Provided that the intake capacity under Open and Distance Learning mode for a programme under science discipline to be offered by a Dual Mode University shall be three times of the approved intake in conventional mode and in case of Open University, it shall be commensurate with the capacity of the Learner Support Centres (for Open and Distance Learning only) to provide lab facilities to the admitted learners:

Provided further that enrolment of learners to the Higher Educational Institution, for any reason whatsoever, in anticipation of grant of recognition for offering a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, shall render the enrolment invalid:


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अणुशिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 डिग्री विश्वविद्यालय, बिमल - 5

Provided also that if the Higher Educational Institution is found violating any of the provisions of these regulations, punitive action shall be taken by the Commission in accordance with the sub-regulation (3) of regulation 7.

- (2) In order to provide opportunities for Higher Education to a larger segment of the population and to promote the educational wellbeing of the community in general, the fee structure shall be devised by the Higher Educational Institutions in such a manner that it is affordable to all the stake holders including students from the deprived sections of society and the Higher Educational Institutions shall comply with the following:-


- (i) A Higher Educational Institution shall, for admission in respect of any programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, accept payment towards admission fee and other fees and charges-
 - (a) as may be fixed by it and declared by it in the prospectus for admission, and on the website of the Higher Educational Institutions;
 - (b) with a proper receipt in writing issued for such payment to the concerned learner admitted in such Higher Educational Institutions;
 - (c) only by way of online transfer, bank draft or pay order directly in favour of the Higher Educational Institution.
- (ii) It shall be mandatory for the Higher Educational Institution to upload the details of all kind of payment or fee paid by the learners on the website of the Higher Educational Institution.
- (iii) The fee waiver and/or scholarship schemes for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Persons with Disabilities category of learners and students from deprived section of society shall be in accordance with the instructions or orders issued by Central Government or State Government:

Provided that a Higher Educational Institution shall not engage in commercialisation of education in any manner whatsoever, and shall provide for equity and access to all deserving learners.

- (iv) Admission of learners to a Higher Educational Institution for a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall be offered in a transparent manner and made directly by the Head Quarters of the Higher Educational Institution which shall be solely responsible for final approval relating to admissions or registration of learners:

Provided that a Learner Support Centre shall not admit a learner to any programme in Open and Distance Learning for or on behalf of the Higher Educational Institution.


- (v) Every Higher Educational Institution shall-
 - (a) record Aadhaar details or other Government identifier(s) of Indian learner and Passport for an International Learner;
 - (b) maintain the records of the entire process of selection of candidates, and preserve such records for a minimum period of five years;
 - (c) exhibit such records as permissible under law on its website; and
 - (d) be liable to produce such record, whenever called upon to do so by any statutory authority of the Government under any law for the time being in force.
- (vi) Every Higher Educational Institution shall publish, prior to the date of commencement of admission to any of its programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, a prospectus (print and in e-form) containing the following for the purposes of informing those persons intending to seek admission to such Higher Educational Institutions and the general public, namely:-


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 आंध्रप्रदेश एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 डि०प्र० वि०वि०, शिमला - 5

- 32 -
- (a) each component of the fee, deposits and other charges payable by the learners admitted to such Higher Educational Institutions for pursuing a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, and the other terms and conditions of such payment;
 - (b) the percentage of tuition fee and other charges refundable to a learner admitted in such Higher Educational Institutions in case such learner withdraws from such Higher Educational Institutions before or after completion of programme of study and the time within, and the manner in, which such refund shall be made to the learner;
 - (c) the number of seats approved in respect of each programme of Open and Distance Learning mode and/or Online mode, which shall be in consonance with the resources;
 - (d) the conditions of eligibility including the minimum age of a learner in a particular programme of study, where so specified by the Higher Educational Institution;
 - (e) the minimum educational qualifications required for admission in programme(s) specified by the Commission or relevant statutory authority or councils, or by the Higher Educational Institution, where no such qualifying standards have been specified by any statutory authority;
 - (f) the process of admission and selection of eligible candidates applying for such admission, including all relevant information in regard to the details of test or examination for selecting such candidates for admission to each programme of study and the amount of fee to be paid for the admission test;
 - (g) details of the teaching faculty, including therein the educational qualifications and teaching experience of every member of its teaching faculty and also indicating therein whether such member is employed on regular or contractual basis or any other;
 - (h) pay and other emoluments payable for each category of teachers and other employees;
 - (i) information in regard to physical and academic infrastructure and other facilities, including that of each of the learner support centres (for ODL programmes) and in particular the facilities accessible by learners on being admitted to the Higher Educational Institution;
 - (j) broad outline of the syllabus specified by the appropriate statutory body or by higher educational institution, as the case may be, for every programme of study;
 - (k) activity planner including all the academic activities to be carried out by the higher educational institution during the academic sessions:

Provided that the Higher Educational Institution shall publish information referred to in sub-clauses (a) to (k) on its website, and the attention of the prospective learners and the general public shall be drawn to such publication on its website and Higher Educational Institution admission prospectus and the admission process shall necessarily be over within the time period mentioned in the Commission Order.

- (vii) No Higher Educational Institution shall, directly or indirectly, demand or charge or accept, capitation fee or demand any donation, by way of consideration for admission to any seat or seats in a programme of study conducted by it;
- (viii) No person shall, directly or indirectly, offer or pay capitation fee or give any donation, by way of consideration either in cash or kind or otherwise, for obtaining admission to any seat or seats in a programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode offered by a Higher Education Institution;


 उप कुलपति (प्रशासन)
 जे.ए.पी.ए. एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हिंदू विश्वविद्यालय, शिमला - 5

- (ix) No Higher Educational Institution, who has in its possession or custody, any document in the form of certificates of degree, diploma or any other award or other document deposited with it by a person for the purpose of seeking admission in such Higher Educational Institution, shall refuse to return such degree, certificate award or other document with a view to induce or compel such person to pay any fee or fees in respect of any programme of study which such person does not intend to pursue or avail any facility in such Higher Educational Institution;
- (x) In case a learner, after having admitted to a Higher Educational Institution, for pursuing any programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode subsequently withdraws from such Higher Educational Institution, no Higher Educational Institution in that case shall refuse to refund such percentage of fee deposited by such learner and within such time as notified by the Commission and mentioned in the prospectus of such Higher Educational Institution;
- (xi) No Higher Educational Institution shall, issue or publish-
- any advertisement for inducing learners for taking admission in the Higher Educational Institution, claiming to be recognised by the appropriate statutory authority or by the Commission where it is not so recognised;
 - any information, through advertisement or otherwise in respect of its infrastructure or its academic facilities or of its faculty or standard of instruction or academic or research performance, which the Higher Educational Institution, or person authorised to issue such advertisement on behalf of the Higher Educational Institution knows to be false or not based on facts or to be misleading.

15. Evaluation.—


(A) Common Provisions for Open and Distance Learning Mode and Online Mode:

- The Higher Educational Institution shall adopt the guidelines issued by the Commission for the conduct of proctored examinations.
- A Higher Educational Institution offering Open and Distance Learning Programmes and/or Online programmes shall have a mechanism well in place for evaluation of learners enrolled through Open and Distance Learning mode and/or Online mode and their certification.
- The evaluation shall include two types of assessments; (i) continuous or formative assessment; and (ii) summative assessment in the form of end semester examination or term end examination:

Provided that no end semester examination or term end examination shall be held in a subject unless:

- the Higher Educational Institution is satisfied that at least 75 per cent. of the programme of study stipulated for the semester or year has been actually conducted;
- For Open and Distance Learning mode: the learner has minimum attendance of 75 per cent. in the programme specific Personal Contact Programme (excluding counselling) and lab component of each of the programmes; and detailed attendance records have been maintained by Learner Support Centre/Regional Centre/Higher Educational Institution;
- For Online mode: the learner has minimum participation of 75 per cent. in all the activities of Online programme prior to end semester examination or term end examination:

Provided further that the curricular aspects, assessment criteria and credit framework for the award of Degree programmes at undergraduate and postgraduate level and/or Post Graduate Diploma programmes through Open and Distance Learning mode and through Online mode shall be evolved by adopting same standards as being followed in conventional mode by the dual mode Higher Educational Institutions and in Open Distance Learning mode by the Open Universities;


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अ०दू०शि० एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हि०प्र० विश्वविद्यालय, शिमला - 5

Provided also that the weightage for different components of assessments for both Open and Distance Learning mode and Online mode shall be as under:

- (i) continuous or formative assessment (in semester): Maximum 30 per cent.
- (ii) summative assessment (end semester examination or term end examination): Minimum 70 per cent.


The Higher Educational Institution shall notify all assessment tools to be used for formative and summative assessments.

- (4) Marks or grades obtained in continuous assessment and end semester examinations or term end examinations shall be shown separately in the grade card.
- (5) A Higher Educational Institution offering a Programme in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall adopt a rigorous process in development of question papers, question banks, assignments and their moderation, conduct of examination, evaluation of answer scripts by qualified teachers, and result declaration, and shall so frame the question papers as to ensure that no part of the syllabus is left out of study by a learner.
- (6) The examination of the programmes in Open and Distance learning mode and/or Online mode shall be managed by the examination or evaluation Unit of the Higher Educational Institution and shall be conducted in the examination centre as given under these regulations.
- (7) The 'Examination Centre' shall be established as per Annexure-I and Annexure II, on due approval of the statutory authority of the Higher Educational Institution, subject to the following:-
 - (i) The Examination Centre shall have proper monitoring mechanisms for Closed-Circuit Television (CCTV) recording of the entire examination procedure and biometric system and in case of non-availability of the Closed-Circuit Television facilities, the Higher Educational Institution shall ensure that proper videography be conducted and video recordings are submitted by particular in charge of examination centre to the concerned Higher Educational Institution.
 - (ii) The Higher Educational Institution shall retain all such Closed-Circuit Television recordings in archives for a minimum period of five years.
 - (iii) There shall be an observer for each of the Examination Centre appointed by the Higher Educational Institution and it shall be mandatory to have observer report submitted to the Higher Educational Institution.
- (B) **Provisions for Open and Distance Learning Mode:** (1) All end semester examination or term end examinations for programmes offered through Open and Distance Learning mode shall be conducted through proctored examination (pen-paper or online or computer based testing) within Territorial Jurisdiction, in the examination centre as mentioned in these regulations. The Exams shall be under the direct control and responsibility of the Open and Distance Learning mode Institution.
- (2) All Government Institutions like Kendriya Vidyalaya(s), Navodaya Vidyalaya(s), Sansad School(s), State Government Schools, etc. can also be identified as examination centres under direct overall supervision of a Higher Educational Institution offering education under the Open and Distance Learning mode including approved affiliated colleges under the University system in the Country and no Examination Centres shall be allotted to private organisations or unapproved Higher Educational Institutions.
- (3) The Learner Support Centres, as defined in the regulations and within the territorial jurisdiction, can also be used as examination centres provided they fulfill the criteria of an examination centre as defined in these regulations.
- (4) The attendance of examinees shall be authenticated through biometric system or per Aadhaar details or other Government identifiers of Indian learners.



उप कुलसचिव (प्रशासन)
अनुसंधान एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
20 विश्वविद्यालय, दिल्ली-5

- (C) **Provisions for Online Learning mode:** (1) An Higher Educational Institution offering programme through Online mode shall conduct examinations either using technology enabled online test with all the security arrangements ensuring transparency and credibility of the examinations, or through the Proctored Examination and in conformity with any other norms for such examination as may be laid down by the Commission;
- (2) As restriction of territorial jurisdiction is not applicable for Online learning, such Higher Educational Institutions which are recognised to enroll international learners shall endeavour to conduct proctored examinations for such learners;
- (3) The attendance of examinees shall be authenticated through biometric system as per Aadhaar details or other Government identifiers of Indian learners and Passports for International learners.
16. **Certification.**— (1) Each award of Degree at undergraduate and postgraduate level and post graduate diploma for both Open and Distance Learning and Online mode shall be assigned a unique identification number and shall have photograph and Aadhaar number or other government recognised identifier or Passport number, as applicable, along with other relevant details of the learner along with the Programme name. Each award shall also be uploaded on the National Academic Depository.
- (2) It shall be mandatory for Higher Educational Institution to mention the following on the backside of each of the degrees/certificates and mark sheets issued by the Higher Educational Institution to the learners (for each semester certificate and at the end of the programme):
- Mode of delivery;
 - Date of admission;
 - Date of completion;
 - Name and address of all Learner Support Centres (only for Open and Distance Learning);
 - Name and address of all Examination Centres.
17. **Learner Support Centre for Open and Distance Learning.**— (1) A Higher Educational Institution offering programme in Open and Distance Learning mode shall, ensure that a Learner Support Centre is established as per Annexure-VIII only in a college or institution affiliated to a University or in a Government recognised Higher Educational Institution offering programmes in the same broad areas having the necessary infrastructure and human resources for offering the programme:
- Provided that a Learner Support Centre defined under these regulations shall not be the Learner Support Centre for more than two Higher Educational Institutions at a time to offer programmes in Open and Distance Learning mode:
- Provided further that a Learner Support Centre of a State University should be in the same state in which the State University has been established:
- Provided also that a Higher Educational Institution may establish a special Learner Support Centre for imparting instruction to persons referred to in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act, 1999 and other persons in difficult circumstances, including jail inmates:
- Provided also that a Learner Support Centre shall not be set up under a franchisee agreement in any case.
- (2) A Learner Support Centre shall be the contact point or centre managed by the Higher Educational Institution for providing academic as well as administrative support to its learners and shall perform such other functions as specified in Annexure-VIII.
- (3) The Learner Support Centre shall be headed by a Coordinator who shall be a regular teacher


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अठ्ठारविंश एंव मुक्त अध्ययन केंद्र
 हिंदू विश्वविद्यालय, शिमला - 5


not below the rank of a qualified Assistant Professor of the concerned College or the Educational Institution and assisted by the counsellors as decided by the Higher Educational Institution.

- (4) The Higher Educational Institution shall have a Standard Operating Procedure for the smooth functioning of the Learner Support Centre which shall include functions of the Learner Support Centres and its different functionaries, monitoring mechanism of different services provided by the Centre, and it shall be mandatory for the Learner Support Centre to maintain the learner data related to conduct of counselling sessions, evaluation of assignments and grievance redressal.
18. **Learner Support Services.**— (1) A Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall have guidelines for learner support services which is made available to all the Co-ordinators/ Counsellors and is accessible to the learners.
- (2) The learner support services to be provided by the Higher Educational Institution shall include broadly the following, namely:—
 - (i) pre-admission counselling for prospective learners to provide information and facilitate them in taking an informed decision on joining a specific programme;
 - (ii) support for admission related matters;
 - (iii) details of study material and information shall also be available on the website of the Higher Educational Institution;
 - (iv) arrangement to ensure the delivery of self learning material to learners for ODL programmes as defined in Annexure-VI and Annexure-VII within a fortnight from the date of admission and in addition, the Higher Educational Institution may provide additional learning resources through on-line mode, Compact Disks etc.;
 - (v) a full-time dedicated help desk well versed with the learner information database providing single window services for all learner related queries.
- (3) The University Grants Commission (Grievance Redressal) Regulations, 2012, shall be adopted and operationalised by the Higher Educational Institution, and the Higher Educational Institution shall institute a system of Grievance Redressal, in accordance with the guidelines specified in Annexure-X.
- (4) The Higher Educational Institution shall provide facilities for online guidance and counselling facilities to the learners.
- (5) The Higher Educational Institution shall create online discussion forum for learners.

Part V

ASSESSMENT, ACCREDITATION, AUDIT, INSPECTION AND MONITORING

19. **Assessment, Accreditation and Audit.**— (1) A Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall comply with University Grants Commission (Mandatory Assessment and Accreditation of Educational Institutions) Regulations, 2012 and in any case shall apply for accreditation under those regulations for assessment and accreditation of the programmes offered by it in Open and Distance Learning mode and/or Online mode.
Provided that Open Universities shall obtain accreditation as stipulated under regulations.
- (2) A Higher Educational Institution recognised under these regulations for important programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall get all its programmes assessed through the Centre for Internal Quality Assurance once in a year in the format prescribed by the Commission and the report on quality assurance shall, towards the end of the academic year, be prominently placed on its website and a copy furnished to the Commission.



 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अन्दूशो एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हि० प्र० विश्वविद्यालय, शिमला - 5

- (3) A Higher Educational Institution recognised under these regulations for imparting programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall undergo third party academic audit every five years and internal academic audit by Centre for Internal Quality Assurance every year as specified in Annexure-I.
20. **Powers to inspect and monitoring.**— (1) The Commission shall periodically review the performance of the Higher Educational Institution and for the purpose may direct the Higher Educational Institution to provide such information as it may require from the viewpoint of ensuring adherence of the regulations by the Higher Educational Institution, and the Higher Educational Institution shall be under obligation to provide such information in such time period as may be specified.
- (2) Where the Commission, either *suo motu* or on the basis of information received by it, considers it necessary, for reasons to be recorded in writing, may cause an inquiry through inspection or otherwise by such body of experts or as it may deem fit, to satisfy itself that all the mandatory requirements under these regulations are being complied with by the Higher Educational Institution imparting programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode and take appropriate action to get compliance enforced against the erring Higher Educational Institution.

PART VI

MISCELLANEOUS

21. **Authority.**— (1) The Commission may authorise the officials of the Commission to perform various functions for implementing these regulations.
- (2) For the purpose of these regulations, the Commission may delegate its power to the Chairman of the Commission, as it may specify in writing.
- (3) For the purposes of regulation 7, the Commission may delegate its power to hear and decide appeal to such person or persons, including officials of the Commission, as it may specify in writing.
22. **Equivalence of qualification acquired through Conventional or Open and Distance Learning and Online modes.**— Degrees at undergraduate and postgraduate level in conformity with UGC notification on Specification of Degrees, 2014 and post graduate diplomas awarded through Open and Distance Learning mode and/or Online mode by Higher Educational Institutions, recognised by the Commission under these regulations, shall be treated as equivalent to the corresponding awards of the Degrees at undergraduate and postgraduate level and post graduate diplomas offered through conventional mode.
23. **Learner centric provisions.**— (1) **Learner's mobility:** A learner enrolled for a programme under Open and Distance Learning mode and/or Online mode in a Higher Educational Institution recognised by the Commission under these regulations shall be eligible for mobility from one mode of learning to another mode of learning within the Higher Educational Institution as per the provisions stipulated under its Act and with the approval of statutory authorities of the Higher Educational Institution;
- Provided that in case a programme is under the domain of regulatory authority/statutory council, Higher Educational Institution shall take permission from the concerned regulatory authority/statutory council for mobility of learners under such programmes.
- (2) **Admission taken during recognition period:** Admission taken in a recognised programme under Open and Distance Learning mode and/or Online mode during the recognition period stands recognised till the completion of programme, even if the Higher Educational Institution does not have recognition for further years, provided the programme is offered as per the UGC norms of territorial jurisdiction and in conformity with the extant guidelines and/or UGC regulations and regulations of respective regulatory bodies.
- (3) **Learner's enrolment (for Open and Distance Learning mode):** A Learner residing in any part of the Country may enroll in any programme being offered by a Higher


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अन्दूजि० एवं मुक्ता अध्ययन केन्द्र
 डि०प्र० विश्वविद्यालय, गिमत-5

Educational Institution recognised by the Commission for offering programme under Open and Distance Learning mode provided that the Higher Educational Institution shall conduct all activities such as admissions, contact programmes, examinations etc. for learner strictly within the territorial jurisdiction of the Higher Educational Institution as specified in these regulations.

- (4) **Learner's enrolment (for Online mode):** A Learner residing within or outside India may enroll in any programme being offered by a Higher Educational Institution recognized by the Commission for offering programme under Online mode.
24. **Offering of Certificate and Diploma level Programmes.**— A Higher Educational Institution recognised for offering programmes at Under Graduate Degree or Post Graduate Degree or Post Graduate diploma levels in Open and Distance Learning mode and/or Online mode may offer Certificate or Diploma programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode in the domains other than prohibited programmes as per clause (2) of regulation 2 subject to the condition that before the actual start of such programmes, all the Certificate or Diploma programmes are duly approved by the statutory authorities of the Higher Educational Institutions and the regulatory authority/council, as applicable, and the delivery mechanism conforms to the quality standards of the Open and Distance Learning education and/or Online education. The Higher Educational Institution shall be solely responsible for any legal issues arising out of non-compliance of such requirements:
- Provided that, if the concerned regulatory authority/council permits any of the prohibited programmes, as mentioned above, under its domain, in Open and Distance Learning mode and/or Online mode, the same may be offered by the Higher Educational Institutions after the approval of its statutory authorities and Regulatory Authorities or Councils, as applicable and after conforming to the quality standards of Open and Distance Learning and Online mode of education.
25. **Integrated programme through Open and Distance Learning mode and/or online mode.**— Any proposal received from a Higher Educational Institutions for offering an integrated programme through Open and Distance Learning mode and/or online mode shall be considered by the Commission only if it is in compliance to the UGC notification on Specification of Degrees, 2014.
26. **Non-consideration of programmes proposed by the Higher Educational Institutions through affiliated colleges only.**— The Higher Educational Institutions shall be eligible to apply for only such programmes under Open and Distance Learning mode and/or Online mode which are being offered by its constituent Colleges or Departments or Centre for distance and online education. The Programmes which are being offered only through affiliated Colleges shall not be considered for recognition.
27. **Interpretation.**— If any question arises relating to interpretation of these regulations, the decision of the Commission shall be final and binding.

Annexure I


CENTRE FOR INTERNAL QUALITY ASSURANCE (CIQA)

I. Establishment of Centre for Internal Quality Assurance:

The Centre for Internal Quality Assurance shall be established in all Higher Educational Institutions offering programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode. It shall be headed by a full-time Director, being a senior academician not below the rank of an Associate Professor, preferably from the field of Open and Distance Learning and/or online education, who shall be supported by adequate number of academic and other staff.

II. Objective:

The objective of Centre for Internal Quality Assurance is to develop and put in place a comprehensive and dynamic internal quality assurance system to ensure that programmes of higher


उप कुलसचिव (प्रासासन)
अन्दोलन एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
डि० प्र० विश्वविद्यालय, शिमला - 5

education in the Open and Distance Learning mode and Online mode being implemented by the Higher Educational Institution are of acceptable quality and further improved on continuous basis.

III. Functions:

The functions of Centre for Internal Quality Assurance would, *inter alia*, include the following, namely:-

- (i) To maintain quality in the services provided to the learners.
- (ii) To undertake self-evaluative and reflective exercises for continual quality improvement in all the systems and processes of the Higher Educational Institution.
- (iii) To contribute in the identification of the key areas in which Higher Educational Institution should maintain quality.
- (iv) To devise mechanism to ensure that the quality of Open and Distance Learning programmes and Online programmes matches with the quality of relevant programmes in conventional mode.
- (v) To devise mechanisms for interaction with and obtaining feedback from all stakeholders namely, learners, teachers, staff, parents, society, employers, and Government for quality improvement.
- (vi) To suggest measures to the authorities of Higher Educational Institution for qualitative improvement.
- (vii) To facilitate the implementation of its recommendations through periodic reviews.
- (viii) To organise workshops/ seminars/ symposium on quality related themes, ensure participation of all stakeholders, and disseminate the reports of such activities among all the stakeholders in Higher Educational Institution.
- (ix) To develop and collate best practices in all areas leading to quality enhancement in services to the learners and disseminate the same all concerned in Higher Educational Institution.
- (x) To collect, collate and disseminate accurate, complete and reliable statistics about the quality of the programme(s).
- (xi) To ensure that Programme Project Report for each programme is according to the norms and guidelines prescribed by the Commission and wherever necessary by the appropriate regulatory authority having control over the programme;
- (xii) To put in place a mechanism to ensure the proper implementation of Programme Project Reports.
- (xiii) To maintain a record of Annual Plans and Annual Reports of Higher Educational Institution, review them periodically and generate actionable reports.
- (xiv) To provide inputs to the Higher Educational Institution for restructuring of programmes in order to make them relevant to the job market.
- (xv) To facilitate system based research on ways of creating learner centric environment and to bring about qualitative change in the entire system.
- (xvi) To act as a nodal coordinating unit for seeking assessment and accreditation from a designated body for accreditation such as NAAC etc.
- (xvii) To adopt measures to ensure internalisation and institutionalisation of quality enhancement practices through periodic accreditation and audit.
- (xviii) To coordinate between Higher Educational Institution and the Commission for various quality related initiatives or guidelines.
- (xix) To obtain information from other Higher Educational Institutions on various quality benchmarks or parameters and best practices.



उप कुलसचिव (प्रशासन)


अन्दूंगि एवं युवत अध्ययन केंद्र

डि०प्र० विश्वविद्यालय, शिमला-६

- (xx) To record activities undertaken on quality assurance in the form of an annual report of Centre for Internal Quality Assurance.
- (xxi) It will be mandatory for Centre for Internal Quality Assurance to submit Annual Reports to the Statutory Authorities or Bodies of the Higher Educational Institution about its activities at the end of each academic session. A copy of report in the format as specified by the Commission, duly approved by the statutory authorities of the Higher Educational Institution shall be submitted annually to the Commission.

IV. Centre for Internal Quality Assurance Committee:


- (1) Centre for Internal Quality Assurance Committee shall have the following composition, namely:-
- Vice Chancellor of the University – Chairperson;
 - Three senior teachers of Higher Educational Institution - Members;
 - Head of three Departments or School of Studies offering recognized programmes in Open and Distance Learning and Online mode - Members;
 - Two external experts of Open and Distance Learning and/or Online education - Members;
 - Officials from the Administration and Finance departments of the Higher Educational Institution – Members;
 - Director, Centre for Internal Quality Assurance – Member Secretary.
- (2) The members at clauses (b) to (e) shall be nominated by the Vice- Chancellor of the Higher Educational Institution.
- (3) The membership of such nominated members shall be for a period of two years. The Committee of Centre for Internal Quality Assurance shall meet at least once in a semester. The quorum for the meeting shall be two-third of the total number of members with mandatory presence of one external expert. The agenda, minutes and Action Taken Reports are to be documented with official signatures and maintained electronically in a retrievable format.
- (4) Centre for Internal Quality Assurance Committee shall perform the following functions, namely:-
- To oversee the functioning of Centre for Internal Quality Assurance and approve the reports generated by Centre for Internal Quality Assurance on the effectiveness of quality assurance systems and processes.
 - To facilitate adoption of instructional design requirements as per the philosophy of the Open and Distance Learning and/or Online learning decided by the statutory bodies of the HEI for its different academic programmes.
 - To promote automation of learner support services of the Higher Educational Institution.
 - To coordinate with external subject experts or agencies or organisations, the activities pertaining to validation and annual review of its in-house processes.
 - To coordinate with third party auditing bodies for quality audit of programme(s).
 - To oversee the preparation of Self-Appraisal Report to be submitted to the Assessment and Accreditation agencies on behalf of Higher Educational Institution.
 - To promote collaboration and association for quality enhancement of Open and Distance Learning and Online modes of education and research therein.
 - To facilitate industry-institution linkage for providing exposure to the learners and enhancing their employability.


उप कुलसचिव (प्रशासन)

अंशु एवं सुक्त अध्ययन केन्द्र
हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली-5

V. Quality Monitoring Mechanism


- (1) The guidelines on quality monitoring mechanism shall be adopted by the Centre for Internal Quality Assurance for conducting institutional quality audits, to promote quality assurance and enhance as well as spread best-in-class practices of quality assurance.
- (2) Quality monitoring shall be addressed under the following broad areas, namely:-
 - (i) **Governance, Leadership and Management:** This relates to the policies and practices of Higher Educational Institution in the matter of planning, human resources, recruitment, training, performance appraisal, financial management and the overall role of leadership, with a focus on the following key aspects:
 - (a) **Organisation Structure and Governance:** The Higher Educational Institution shall fill all sanctioned/required positions as prescribed by the Commission and establish a credible governance system.
 - (b) **Management:** The leadership and management of the Institution shall strive to assess and review the organisational culture to achieve its vision, mission and goals.
 - (c) **Strategic Planning:** The Higher Educational Institution shall undertake strategic planning of its activities and implement the same by aligning those with academic and administrative aspects to improve the overall quality.
 - (d) **Operational Plan, Goals and Policies:** The Higher Educational Institution shall have well defined goals which are realistic and measurable, well defined policies that are in sync with its strategic plan and are realistic and achievable, clearly stated guidelines for the implementation of its policies and plans, and transparent and accountable system for its policies and planning that are well communicated to its stakeholders.
 - (ii) **Articulation of Higher Educational Institution Objectives:** The Higher Educational Institution shall articulate a clear vision, mission, ethos and broad strategy consistent with the goals for offering programmes in Open and Distance Learning and Online mode.
 - (iii) **Programme Development and Approval Processes:** This area of concern relates to programme development and approval mechanism for the programme(s) to be launched, covering the following key aspects, namely:-
 - (a) **Curriculum Planning, Design and Development:** The curriculum planning, design and development of academic programmes is a major academic activity of the Higher Educational Institution. Therefore, it shall have processes, systems and structures in place to carry out these responsibilities.
 - (b) **Curriculum Implementation:** The Higher Educational Institution shall have specific implementation plans for identifying the time to be spent on specific components of the implementation phase. It is the basis for the effectiveness of the programme(s) and their usefulness as a whole.
 - (c) **Academic Flexibility:** The Higher Educational Institution shall adopt proper strategies for imparting academic flexibility, which refers to freedom in the use of the time-frame of courses, vertical mobility, and inter-disciplinary options facilitated by curricular transactions for learners.
 - (d) **Learning Resource:** The Higher Educational Institution shall ensure quality learning resources in the form of Self Learning Materials (SLMs) for Open and Distance Learning mode and e-learning material for Online mode of education as defined in these regulations. While deciding on the instructional packages, the Higher Educational Institution shall take into consideration various factors – the media and technology utilised matches the course content in order to enhance and expand learning, and to match to the learners' needs; that these are accessible, practical and equitable, and cost effective to the learners.


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान
 दिल्ली-110 047

- (e) **Feedback System:** The process of revision and re-design of curricula shall be based on feedback from all stakeholders in terms of its relevance and appropriateness in catering to the needs of the society, economy and environment.
- (iv) **Programme Monitoring and Review:** The Higher Educational Institution shall plan and execute programme monitoring and review system to conduct periodic internal reviews and maintain the quality of academic programmes. For such reviews, the Institution shall also consider the attainments of learning outcomes that are assessed through the various tools for direct and indirect assessment.
- (v) **Infrastructure Resources:** The Higher Educational Institution shall have a system to elicit data on the adequacy and optimal use of the facilities - physical facilities, library (or e-library), Information and Communication Technology infrastructure, etc. - available in a Higher Educational Institution to maintain the quality of academic programmes and ensure qualitative support to each of the stakeholders.
- (vi) **Learning Environment and Learner Support:** The learner support services including academic counselling and library services shall be a major pre-occupation of Higher Educational Institution for its Open and Distance Learning mode and Online mode learners. Additionally, Higher Educational Institution shall establish Information and Communication Technology facilities as component of the learning environment which is focused around the pedagogical use of modern educational practices to support blended learning. Learner Support Services shall be provided through the campus-wide portal and e-Learning platform. The Higher Educational Institution shall take a more sophisticated approach to the use of Information and Communication Technology and expertise in e-learning. The approach shall provide a seamless learner-centred environment.
- (vii) **Assessment and Evaluation:** All the stated Learning Outcomes of a Programme must be part of its evaluation protocol. The Higher Educational Institution shall execute the evaluation through varied assessment tools including multiple choice questions, projects, reports, case-studies, presentations, and term-end examinations, to suit the different learning outcomes expected of the course elements. The Higher Educational Institution shall have proper assessment and moderation system for assessing the learning outcomes of learners.
- (viii) **Teaching Quality and Staff Development:** The Higher Educational Institutions shall have a well established structure for promoting quality counselling, capacity building workshops, programmes, interactive teaching-learning and provide staff development programmes and activities to encourage academic staff to improve teaching and learning on continuous basis.

(3) **Process of Quality Audit**

- (i) **Academic Planning:** The Higher Educational Institutions shall have robust and appropriate academic planning procedures to ensure that the programmes offered by it are relevant to national economy, reflects the Institution's strategic direction and offers a high quality 'value-added' learner experience. The Institution shall have adequate and appropriate teaching and other support staff along with infrastructure and technology support to ensure that the curriculum remains up to date and the institutional goals are achieved.
- (ii) **Validation:** The Higher Educational Institution shall have a mechanism in place for validation to ensure that its programmes are academically viable, that academic standards have been appropriately defined and that these offer learners the best opportunity to learn.
- (iii) **Monitoring, Evaluation and Enhancement Plans:** Quality deliverance of the Open and Distance Learning programmes and Online programmes and the outcomes attainment and continual quality improvements shall be ensured by the Higher Educational Institution, shall be broadly as follows, namely:-


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 उद्घोषित एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 विद्यापीठ, वि.सं. - 5

- (a) **Reports from Learner Support Centres (for Open and Distance Learning programmes):** Report of academic activities and other related activities containing details of all the activities related to academic planning, counselling, learner support, etc. shall be collected periodically from Learner Support Centres. The Higher Educational Institution shall adopt the technological solutions for easy receipt of these reports.
- (b) **Reports from Examination Centres:** Report of conduct of examinations in both Open and Distance Learning Mode and Online mode, alongwith report of observers/proctors for all examinations shall be collected periodically from Examination Centres. The Higher Educational Institution shall adopt the technological solutions for easy receipt of these reports.
- (c) **External Auditor or other External Agencies report:** The Higher Educational Institution shall consider the comments made by External auditors, experts and third party of quality audit and implement as appropriate.
- (d) **Systematic Consideration of Performance Data at Programme, Faculty and Higher Educational Institution levels:** For effective evaluation and audit, the Higher Educational Institution shall ensure easy access to performance monitoring information such as course pass rates, learner entry profiles and progression and achievement reports, which should be available through web-based application and be used for report making by the Higher Educational institution.
- (e) **Reporting and Analytics by the Higher Educational Institution:** The Higher Educational Institution shall generate the required reports out of such web-based applications and analyze learner and academic analytics for deciding the improvements to be executed for better performance.
- (f) **Periodic Review:** The Higher Educational Institution needs to have an effective system for collecting feedback from the stakeholders regularly to improve its programmes. The Higher Educational Institution needs to conduct self-assessments regularly and use the results to improve its systems, processes etc. and finally quality of programmes.

Annexure II

CONDUCT OF EXAMINATION AND MINIMUM STANDARDS FOR EXAMINATION CENTRES

I. Conduct of End Semester or Term End Examination:

1. All processes of assessment of learners in different components of Examination shall be directly handled by the concerned Institution and no part of the assessment shall be outsourced.
2. For ensuring transparency and credibility, the full time faculty of the Open and Distance Learning and/or Online mode Higher Educational Institutions or qualified faculty from University Grants Commission recognised Higher Educational Institutions only should be associated to function as invigilators, examination superintendents, as observers etc.

A. For Open and Distance Learning programmes:

1. All Examinations for Open and Distance Learning mode programmes shall be conducted within the Institution where the Study Centres or Learner Support Centres is located under the direct control and responsibility of the Open and Distance Learning mode Institution. Also, all Government Institutions like Kendriya Vidyalaya(s), Navodaya Vidyalaya(s), Sainik School(s), State Government Schools, etc. can also be identified as examination centre(s) under direct overall supervision of a Higher Educational Institution offering education under the Open and Distance Learning mode including approved affiliated colleges under the University system in the country and no Examination Centres shall be



उप कुलसचिव (प्रशासन)
अठ्ठार्वींश एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
हि० प्र० विश्वविद्यालय, जमशेदपुर - 5

allotted to any private organisations or unapproved Higher Educational Institutions.

2. In case the types of Institutions mentioned at (i) above are not sufficient to meet the requirement in a city/town, the HEI may locate the Examination Centre(s) at Krishi Vigyan Kendras, State Training Institutes/Industrial Training Institutes, Government Organisations/Departments, Accredited Laboratory with the prior approval of its statutory bodies.

B. For Online Programmes

1. A Higher Educational Institution offering programme through Online mode shall conduct examinations either using Computer based test or pen and paper test in a proctored environment in designated test centre with all the security arrangements ensuring transparency and credibility of the examinations. It can also conduct online examination through technology mediated proctoring.
2. The attendance of examinees shall be authenticated through biometric system as per Aadhaar details or other Government identifiers for Indian learners and Passports for International learners.

II. Minimum Standards to be Maintained at Examination Centres

A. For Open and Distance Learning Programmes


1. The examination centre must be centrally located in the city, with good connectivity from railway station or bus stand, for the convenience of the students.
2. The number of examination centres in a city or State must be proportionate to the student enrolment from the region.
3. Building and grounds of the examination centre must be clean and in good condition.
4. The examination centre must have an examination hall with adequate seating capacity and basic amenities.
5. Fire extinguishers must be in working order, locations well marked and easily accessible. Emergency exits must be clearly identified and clear of obstructions.
6. The Examination Centre shall have adequate and comfortable seating capacity and amenities including adequate lighting, ventilation and clean drinking water facilities.
7. Safety and security of the examination centre must be ensured.
8. Restrooms must be located in the same building as the examination centre, and restrooms must be clean, supplied with necessary items, and in working order.
9. Provision of drinking water must be made for learners.
10. The Examination Centre shall have proper monitoring mechanisms for Closed-Circuit Television (CCTV) recording of the entire examination procedure and biometric system and in case of non-availability of the Closed-Circuit Television facilities, the Higher Educational Institution shall ensure that proper videography be conducted and video recordings are submitted by in-charge of examination centre to the concerned Higher Educational Institution.
11. Adequate parking must be available near the examination centre.
12. Facilities for Persons with Disabilities should be available.

B. For Online Programmes:

13. In addition to facilities mentioned in clause A of paragraph II, Online Examination shall have the following facilities, namely:-

(i) Requirements at Test Centres:

- (a) Provide adequate test room(s)/space for given number of examinees;
- (b) Examinees must be seated with separation distance that restricts view of others work;


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अंबूशि० एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हि०प्र० विश्वविद्यालय, शिमला - 5

- (c) Examination Centres must have backup plans in case of power or application failure;
- (d) The online examination application must be tested before commencement of the examination;
- (e) The check-in area should be located near the entrance to the testing room, in an area separate from other activities;
- (f) The building, testing rooms and rest rooms must be accessible to people with disabilities, including wheel chair access;
- (g) Each test room shall have proctoring facility either through human proctors or through technology mediated proctoring.


(ii) **Requirement of proctors:**

Each test centre requires one or more proctors in each room, whose responsibilities include the following, namely:-

- (a) Monitor the testing room to maintain security;
- (b) Interact with the testing workstations to start or pause tests;
- (c) Report any irregularities;
- (d) Other activities to ensure credibility and transparency of the examination.

(iii) **Security arrangements in the testing centre:**

- (a) Only authorised staff and if any external examiner(s) shall have access before exam time;
- (b) Only authorised staff and examinee shall have access during exams;
- (c) Authorised staff and external examiners to have only the level of access as required and mandated;
- (d) OS, Browser and the Software must be kept up-to-date and patched in a timely fashion;
- (e) The testing application shall be able to track and report all access attempts;
- (f) Each examination room shall have CCTV facility;
- (g) Centralised audio/video monitoring of all exam centers shall be ensured;
- (h) A separate examination application server or machine in each exam centre must be ensured which will be connected to a central server through virtual private network connectivity for secure delivery of question papers in encrypted form at a designated time prior to the exam;
- (i) Examination applications server must reside on a local area network in the same subnet to allow communication between test delivery applications without blocking any ports;
- (j) Audit Logging: the online examination system must provide a detailed audit logging facility recording activities like Login, Logout, Exam Access, Question Navigation, Answer Responses, etc. Using techniques like geo-tagging which will make it possible to track the exact location of the user during online exam activity.
- (k) IP based Authentication and Authorization: the access and operation of the examination program must be restricted or limited to a certain specified number of IP addresses specially in the case of admin login to ensure complete safety for the examination.
- (l) Examination Centre has to be connected to the internet via a good internet connection with a minimum download speed of 4 Megabits per second (Mbps) and upload speed of 1 Megabits per second (Mbps) for online question paper delivery and uploading of scanned answer scripts.


उप कुलसचिव (प्रशासन)

अठवूँशें एवं मुक्त अध्ययन केंद्र
डि० प्र० विश्वविद्यालय, शिमला - 5

- (m) There should be a separate device for Local Area Network (switch) and internet connectivity (router) instead of using an integrated device.
- (n) Staffs have to verify the student's original ID proof issued by Govt. of India with the ID proof for authentication.
- (o) External devices (i.e. mobile, pen drive, tab, laptop, smart watch etc.) or reading materials should not be permitted in exam centres.
- (p) The online exam Platform will be accessible via user id and password which is unique for each student for each session and exam.
- (q) After examination data shall be transferred in encrypted format through an encrypted virtual private network connection from examination application server to central server.

(iv) **Remote Proctoring:**

Following security measures to be ensured for conducting online examination through remote proctoring:

- (a) Secure browser: there must be custom application pre-installed on the machine for the examination preventing opening of any other windows or application. This application must prevent Screen Capturing, Recording and Remote Login or taking output to a remote screen through Video Graphic Array (VGA), Universal Serial Bus (USB) or High Definition Multimedia Interface (HDMI) ports features.
- (b) Remote Proctoring: remote proctoring shall involve image capturing in intervals or video streaming of the candidate through webcam or screen capturing of the current access screen of the candidate.
- (c) Data Encryption: Online examination system's data needs to be encrypted to prevent any kind of misuse. Question Bank and exam data must be stored in a highly secure and encrypted manner. The entire communication between server and client/student machine during the examination needs to be encrypted with a secure mode of communication.

Annexure III

**TERRITORIAL JURISDICTION AND REGULATING PROVISIONS FOR
DIFFERENT TYPES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

1. **Central Government and State Government University:**

1. A University established or incorporated by or under a Central Act shall offer programmes in Open and Distance Learning mode and operate all other related activities as per the territorial jurisdiction allotted to it under its Act.
2. A University established or incorporated by or under a State Act shall offer programmes in Open and Distance Learning mode and operate all other related activities only within the territorial jurisdiction allotted to it under its Act and in no case beyond the territory of the state of its location.
3. A Central Government or State Government University can offer recognised programmes under Open and Distance Learning mode and/or Online mode in accordance with the provisions of its respective Act and after the recognition of the University Grants Commission.
4. A Central Government or State Government University can offer recognised programmes under Open and Distance Learning mode through its own Schools/Departments/Centre and its constituent colleges.
5. No university can offer its programmes or other related activities through franchising arrangement for the purpose of conducting courses through Open and Distance Learning mode and Online mode.

उप कुलसचिव (प्रशासन)
अध्यक्ष एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली-5

6. Territorial Jurisdiction shall not be applicable to these category of Higher Educational Institutions recognised for offering programmes through Online mode under these regulations.

II. Private Universities:

1. Private Universities established or incorporated by or under a State Act shall offer programmes in Open and Distance Learning mode and operate all other related activities only within the territorial Jurisdiction allotted to it under its Act and in no case beyond the territory of the state of its location.
2. Private Universities shall be governed by UGC (Establishment and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003.
3. Private Universities shall be eligible to offer programmes under Open and Distance Learning mode through its Head Quarters only and duly recognised off-campus centres.
4. Private Universities shall not offer programmes under Open and Distance Learning mode through any Learner Support Centre.
5. A Private University established under the State Act shall be a unitary University.
6. Private Universities cannot affiliate any college or institution for conducting programmes leading to award of its diplomas, degrees or other qualifications.
7. No university can offer its programmes or other related activities through franchising arrangement for the purpose of conducting courses through Open and Distance Learning mode and Online mode.
8. Territorial Jurisdiction shall not be applicable to this category of Higher Educational Institutions recognised for offering programmes through the Online mode under these regulations.

III. Institutions Deemed to be Universities:

1. Institutions Deemed to be University shall be governed by UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019.
2. Institutions Deemed to be University shall operate only within its Head Quarters or from those off campuses which are approved by the Government of India through notification published in the Official Gazette.
3. Institutions Deemed to be Universities shall be a unitary in nature and cannot affiliate any college or institution for conducting programmes leading to award of its diplomas, degrees or other qualifications.
4. No university can offer its programmes or other related activities through franchising arrangement for the purpose of conducting courses through Open and Distance Learning mode and Online mode.
5. Territorial Jurisdiction shall not be applicable to this category of Higher Educational Institutions recognised for offering programmes through Online mode under these regulations.


Annexure IV

HUMAN RESOURCE AND INFRASTRUCTURAL REQUIREMENTS

I. Open Universities

A. Staffing Norms at Head Quarters:


1. The following positions are on full time and dedicated basis, excluding the designated positions in the Open Universities as per their respective Act(s):-
 - (i) Head for each school at the Professor level.


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अंबूशि० एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हि० प्र० विश्वविद्यालय, दिल्ली - ५

- (ii) Academic staff strength per programme under a school. Minimum three faculty members are required at Associate Professor/Assistant Professor level:
Provided that in case of Under Graduate and Post Graduate programmes in same discipline, instead of 6 faculty members, 5 faculty members shall be required.
- (iii) Administrative staff strength at Head Quarters or Main Campus (up to 10,000 students):
- Deputy Registrar - 1;
 - Assistant Registrar - 1;
 - Section Officer - 1;
 - Assistants - 3;
 - Computer Operator - 2;
 - Multi Tasking Staff - 2.
2. In case of the enrolment higher than 10,000 in Open and Distance Learning Programmes, Open University may increase the number of positions appropriately.

B. Centre for Online Education (COE):

- The Open University intending to offer the recognised programmes under Online mode shall have a Centre for Online Education for effective coordination among its Departments or Schools of Studies for offering the Online Programme, comprising Admission or Registration Unit, Examination Unit and Technology Support Unit. The Centre for Online Learning shall maintain and administer the Centralised Data Base of all the recognised programmes.
 - The Centre for Online Education shall have:
 - Director: Permanent, full-time Professor (preferably having professional experience in Open and Distance Learning and/or Online Learning);
 - Deputy Director (e-Learning and Technical): An employee having the Qualifications and Experience as specified for Associate Professor under the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018 shall be an e-learning expert with experience in technical coordination for modules development and Learning Management System (LMS). The Deputy Director can be appointed on full-time or contractual basis;
 - Assistant Director: Having qualifications and experience as specified for Assistant Professor under University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, initially one, who shall coordinate with Departments or Schools of Studies offering Online Programmes. The Assistant Director can be appointed on full-time or contractual basis.
 - The Departments or Schools of Studies shall be the academic home of the recognised Online programmes on offer.
 - The involvement of permanent and/or full time dedicated faculty of Schools of Studies/Departments in the Online programme(s) shall be in the following capacities, excluding the designated positions in the Open Universities as per their respective Act(s):
 - Programme Coordinator (One per Programme): A full-time Faculty at the level of Professor or Associate Professor or Assistant Professor in the subject area of the concerned Programme shall be the Programme Coordinator for an Online


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अन्दूकि एवं मुक्त अध्ययन बोर्ड
 हि०प्र० विश्वविद्यालय, गिमत - 5

Programme. The Programme Coordinator shall be responsible for overall coordination of the development, delivery and assessments of the learners in an Online Programme;

(b) Course Coordinator (One per Course): An Online Programme may have more than one Course. In such a case, one full-time dedicated Faculty at the level of Professor or Associate Professor or Assistant Professor in the subject area of the concerned Course shall be Course Coordinator for each of the Courses of an Online Programme. The Course Coordinator shall coordinate the development, delivery and assessments of the learners in the Course;

(c) Course Mentor (One per batch of 250 learners): Course Mentor shall assist the Programme/Course Coordinator in providing academic support to learners and also in managing virtual teacher-learner interaction groups. Course Mentor shall have the relevant qualifications and experience as specified for Assistant Professor under the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018;

(d) Examiners: The Higher Educational Institution shall appoint examiners for the assessment of the online learners in a Course from among the qualified faculty from within the Institution or from other Institutions and they shall be paid appropriate honorarium as per norms of the Higher Educational Institution.

(iv) Requirement of Technical Support for Online Programmes:

(a) Technical Team for Development of e-Content as Self-Learning e- Modules:

(A) Technical Manager (Production)-minimum one

(B) Technical Associate (Audio-Video recording and editing)- minimum one

(C) Technical Assistant (Audio-Video recording)- minimum one

(D) Technical Assistant (Audio-Video editing)-minimum one

(E) The technical support required for development of e-content may be outsourced to the centres across the nation having requisite facilities.

(F) These numbers are for the initial stage of e-content, for self learning e-modules development and delivery.

(b) For Delivery of Online Programmes:

(A) Technical Manager (LMS and Data Management)-minimum one (per Centre)

(B) Technical Assistant (LMS and Data Management) - minimum two

(c) For Admission and Examination for Online mode:

(A) Technical Manager (Admission, Examination and Result) -minimum one (per Centre)

(B) Technical Assistant (Admission, Examination and Result) - minimum two

(C) These activities may be carried out by the Admission/Registration and Examination Units of the Open Universities having requisite resources for their ODL Programmes under the overall supervision of Centre for Online Education for Online Programmes.

II. Dual Mode Higher Educational Institutions

1. The dual mode Higher Education Institution intending to offer Programmes in Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall have a Centre for Distance and Online Education (CDOE) for effective coordination among its Departments or Schools of Studies.
2. The Centre shall maintain and administer, in collaboration with the technology support Unit

उप कुलसचिव (प्रशासन)

अनुसंधान एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र

हि.प्र. विश्वविद्यालय, शिमला-5

of Higher Educational Institution, the Centralised Data Base of all the Open and Distance Learning and/or Online Programmes.

3. The provisions as detailed in clause (1) of sub-paragraph (B) of paragraph 1 above shall be applicable to Dual mode HEIs for Online Programmes.

III. Staffing Norms at Head Quarters:

1. As mentioned in Clause (1) of sub-paragraph (B) of paragraph 1 above, in case of Online Programmes.
2. Academic staff strength - At least two faculty members (full-time dedicated) per Open and Distance Learning Programme at Professor/Associate Professor/Assistant Professor level: Provided that in case of Under Graduate and Post Graduate programmes in same discipline, instead of 4 faculty members, 3 faculty members shall be required.
3. Administrative staff strength at Head Quarters or Main Campus (up to 5,000 students):
 - (a) Deputy Registrar - 1;
 - (b) Assistant Registrar - 1;
 - (c) Section Officer - 1;
 - (d) Assistants - 2;
 - (e) Computer operators - 2;
 - (f) Multi Tasking Staff - 2.
4. In case of the enrolment higher than 5,000 the number of positions in the Centre for Distance and Online Learning may be increased by the HEI appropriately.

IV. Physical Infrastructure:


1. Total Built-up area for Open and Distance Learning activity - Minimum 15000 sq. ft. (carpet area):

Table

S. No.	Built-up Area Type	Percentage (%)	Built-up Area (Carpet Area, in sq ft)
1.	Academic	50 per cent.	7500
2.	Administrative	10 per cent.	1500
3.	Academic support such as Library, Reading room, Computer Centre, Informational and Communication technology Labs, Video and Audio Labs etc.	30 per cent.	4500
4.	Amenities or other support facilities	10 per cent.	1500
Total			15000

Note: Built up area for toilets shall be separate.

2. Minimum requirement of Physical Infrastructure will be as per University Grants Commission (Fitness of Open Universities for Grants) Rules, 1988 and as amended from time to time, except for the existing Open Universities for the purpose of these regulations.


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अ०दू०शि० एवं मुक्त अध्यायन केन्द्र
 हि०प्र० विश्वविद्यालय, शिमला - 5

V. Academic Counselor in a Learner Support Centre:

1. Should be a post graduate from a recognised University.
2. Familiarity with basic research on the characteristics of Distance learners, their needs and difference from conventional face-to-face education.
3. Application of basic principles of instructional design.
4. Thorough knowledge of subject matter and common misconceptions related to the course(s).
5. Deep understanding of the necessity of learner-centered environment in online and blended learning mode.
6. Ability to design constructivist learning environment.
7. Practical applications of learning theories, self-paced instruction, and computer-mediated communication and learning.
8. Ability to foster a sense of community among learners.
9. Adaptability and flexibility with the capabilities and limitations of the delivery media.
10. Familiarity with the delivery medium to provide basic troubleshooting.
11. Ability to multitask.
12. Time management (e.g. respond to learners in timely manner, extensive and advance preparation and planning).
13. Professional characteristics (e.g. motivated to teach, self-confident, articulate, good writer).

Annexure V

GUIDELINES ON PROGRAMME PROJECT REPORT (PPR)

I. Overview

1. A Programme Project Report (PPR) of a Higher Educational Institution is a document prepared to introduce a new programme, which includes details of - (a) programme objectives and outcomes; (b) nature of target group of learners; (c) appropriateness of the programme with quality assurance for acquiring specific skills; (d) programme content designing and developing; (e) cost estimates for development of the programme; and (f) admission, delivery and evaluation norms.
2. The Programme Project Report is a self-disclosure by the Institution about launching the programme in the Open and Distance Learning mode and/or Online mode. The Institution has to define specific aims and objectives for each of the academic programmes which will give the direction to launch a programme and will allow to focus on results. At the end, these aims and objectives will help to demonstrate what has been achieved. The programme shall be planned with clear deliverables and knowledge experiences to be gained.

II. Contents of Programme Project Report (PPR): Programme Project Report is required to be prepared before introducing any new programme duly approved by its highest academic authority. The Programme Project Report shall contain the following contents, namely:-

- (i) **Programme's mission and objectives:** The Higher Educational Institution shall define the mission statement and objectives for the programme to be launched, which shall reflect the strategic direction and the academic goals of the Higher Educational Institution. Those shall be aligned with industrial or learners' demand, and shall be defined in such a manner that they are appropriate to be achieved.
- (ii) **Relevance of the program with HEI's Mission and Goals:** The Higher Educational Institution shall plan for such a programme to be offered through the Open and



उप कुलसचिव (प्रशासन)

अ.दू.शि. एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र

हि.प्र. विश्वविद्यालय, शिमला - 5

Distance Learning Mode and/or Online Mode that is relevant to the Higher Educational Institution's mission and goals. Therefore, it is very much important that the programme to be offered through Open and Distance Learning Mode and/or Online Mode should be aligned with Higher Educational Institution's mission and goal and will prove as major contributing factor in its achievement.

- (iii) **Nature of prospective target group of learners:** The Higher Educational Institution shall identify the target group of learners. It is required to understand their learning needs and on its basis the curriculum should be aimed. The Higher Educational Institution should also consider diverse class of learners including a class having of low level of disposable income, rural dwellers, women, unskilled men, minorities etc.
- (iv) **Appropriateness of programme to be conducted in Open and Distance Learning and/or Online mode to acquire specific skills and competence:** The Higher Educational Institution shall clearly identify the learning outcomes for the programme which shall cover the specific skills and competence to be acquired by the learner. The programme should be aimed appropriately to those learning outcomes. The learning outcomes shall include the development of knowledge and understanding appropriate to the area of study and these should also reflect academic, professional and occupational standards of that field. The learning outcomes should incorporate generic transferable skills and competencies.
- (v) **Instructional Design:** Instructional Design includes Curriculum design, detailed syllabi, duration of the programme, faculty and support staff requirement, instructional delivery mechanisms, identification of media— print, audio or video, online, computer aided, and student support service systems. The Higher Educational Institution shall define the instructional design for each of the academic programmes to be offered through the Open and Distance Learning Mode and/or Online Mode and shall map the credit hours for each course or module of the programme.
- (vi) **Procedure for admissions, curriculum transaction and evaluation:** The Higher Educational Institution shall define the admission policy for the programme with minimum eligibility and fee structure. The information related to financial assistance, if any, should be included in the policy. The Higher Educational Institution shall notify the policy of programme delivery along with the details of methods and web-based tools to be adopted. The Higher Educational Institution shall notify the activity planner including all the academic activities to be carried out by the Higher Educational Institution during the academic session. Further, the Higher Educational Institution shall also notify policy for evaluation of learner progress along with methods and tools.
- (vii) **Requirement of the laboratory support and Library Resources:** There may be programmes having practical component in syllabus. The Higher Educational Institution shall give clear guidelines about the laboratory support to the learners to perform the practical prescribed in the programme. There shall be provision of a practical book for the learners.
- (viii) **Cost estimate of the programme and the provisions:** The cost estimate shall indicate the amount assigned for programme development, delivery and maintenance.
- (ix) **Quality assurance mechanism and expected programme outcomes:** The Higher Educational Institution shall define the review mechanism for programme and continuously enhance the standards of curriculum, instructional design relevant to professional requirements of the area of study. There should be course benchmark statements. The Higher Educational Institution shall also devise the mechanism for monitoring effectiveness of the programme being offered in Open and Distance Learning mode and/or Online mode.



 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अरूणेश्वर एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हि.प्र. विश्वविद्यालय, शिमला-5

QUALITY ASSURANCE GUIDELINES OF LEARNING MATERIAL IN MULTIPLE MEDIA AND CURRICULUM AND PEDAGOGY

A. For Open and Distance Learning mode

1. Learning Materials (Print Media): Quality Standard

1. Learning Materials through print-media is termed as Self Learning Materials (SLM), being developed with the approach of self-explanatory, self-contained, self-directed, self-motivating and self-evaluating.
2. The Self Learning Material shall be self-contained providing complete course description comprising overview of units alongwith objectives, activities, assignments and additional resources.
3. There shall be description of credit value of each module or unit in the course.
4. The course material shall provide an environment for practice, at the learner's own pace and in his/her own time.
5. There shall be clear guidelines on academic integrity and netiquette (internet etiquette) expectations regarding activities, discussions and plagiarism.
6. The course shall be designed to teach concepts and skills that the learner will retain throughout the study.
7. There shall be multiple learning paths for engaging the learner in active learning.
8. The content shall provide opportunities for learners to engage in higher- order thinking, critical-reasoning activities and thinking in increasingly complex ways.
9. The following is an indicative list of quality standards for printed learning materials:
 - (i) The Self Learning Material shall be structured on the Learning Outcome based Curriculum Framework (LOCF).
 - (ii) The Self Learning Material shall be designed with the approach of two-way communication between the learner and content. The content of Self Learning Material shall be presented in an interactive, conversational format with dialogue and personal system of writing method which will create the nature of interactivity in Self Learning Materials
 - (iii) The Self Learning Material shall involve the learner actively through various experience-based activities and assignments.
 - (iv) The learner should get clear information about the structure of the programme and course.
 - (v) There shall be detailed concept/learning map in Self Learning Material for the learner so that he or she will be self-directed for completion of his or her studies with clearly stated learning outcomes.
 - (vi) The Self Learning Material shall encourage learner to apply new knowledge and skills.
 - (vii) The content of a course should be divided into a few Blocks on major related themes, each block containing a few Units on a major theme for effective learning.
 - (viii) Units in the Self Learning Material shall be developed in defined formats with the following features, namely:-
 - (a) Consistent layout and format;
 - (b) Inclusion of overview of content;
 - (c) A unit structure, Introduction, and expected learning outcomes and reference to prior learning at the beginning of the unit and Summary at it end;


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 आन्दोलन एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हि.प्र. विश्वविद्यालय, शिमला - 5

- (d) Presentation of content in appropriate sequence in sections and sub-sections synchronized with learning objectives and outcome, containing plenty of examples including national or international case studies, wherever relevant;
- (e) Explanation of icons, symbols, formula etc. used in content;
- (f) Explanation on technical, new, difficult terms or word in a glossary/ keyword section;
- (g) Inclusion of adequate suggested reading (both print and online).

II. Audio-Video Material: Quality Standards


1. The following is an indicative list of quality standards for audio-video materials:

- (i) The audio-video material shall supplement and complement the Self Learning Material and based on the curriculum structure.
- (ii) There shall be adequate consideration of learners' prior knowledge, skills and attitudes.
- (iii) Level and style of presentation and language shall be simple and appropriate to aid in self-learning.
- (iv) There shall be clear information on types of support material and study activities to be used by the learner.
- (v) It shall be clear and unambiguous, also preferably free from pedagogic jargon.
- (vi) The aim, objective and target audience for the audio or video material shall be clearly defined.
- (vii) It shall conform to the learning outcomes.
- (viii) There shall be clear guidelines with regard to the use of the audio or video material vis-a-vis other content of the course.
- (ix) Audio or video material shall be developed in forms and formats that will be easily accessible by the learners and compatible with web-based delivery.
- (x) Audio or video material shall provide continuity and coherence within and between audio or video based study sessions.
- (xi) The content need to be interactive with appropriate use of graphics, animations simulation etc. to keep the learners engaged.

III. Online and Computer based Material: Quality Standards

1. The following is an indicative list of quality standards for Online and Computer based materials:

- (i) The digital content should not be merely scanned files of the Self Learning Material. If content is scanned it should be made available in accessible format such as Word Processing, Portable Document Format or E-Pub format.
- (ii) The file size should not be very heavy so that the learners are easily able to access and download the content.
- (iii) The course content in digital format shall be easy to navigate and searchable through metadata.
- (iv) The digital content needs to be Unicode compliant so that font issues are not faced by the learners specially in the case of Indian languages.
- (v) Digital content should be accessible to all with special attention to the needs of the learners with disabilities.
- (vi) The digital content shall be available across platforms and devices.


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अंध्रप्रदेश एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हिंदू विश्वविद्यालय, भिमत - 5.

- (vii) Since the learners may not have access to unlimited Internet data plan, it is advisable that the audio-video material is made available through streaming server instead of file uploaded as such on the server.
- (viii) The compression of the digital files needs to be optimised so that the quality is not compromised and content is easily accessible.
- (ix) For digital content the appropriate required players need to be easily available or made available.

IV. Curriculum and Pedagogy: Quality Standards

I. The following is an indicative list of quality standards for curriculum and pedagogy:


- (i) The curriculum objectives shall be consistent with the mission of the Higher Educational Institution.
- (ii) There shall be involvement of all the stakeholders in the process of framing the curriculum objective.
- (iii) While designing the curriculum, the Higher Education Institution shall take into consideration the University Grants Commission Model Curriculum and the Learning Outcome- based Curriculum Framework (LOCF) and incorporate local or regional needs.
- (iv) There shall be rationale for the appropriateness of the curriculum to the stage of learning.
- (v) There shall be linkages of the curriculum to previous and subsequent stages of learning.
- (vi) There shall be such learning experiences which allow a diversity of methods (like learning from practice, opportunities for distributed and concentrated practice, learning with peers, learning in formal situations inside and outside the department, personal study, specific teacher inputs etc).
- (vii) The structure of curriculum shall be defined.
- (viii) There shall be a complete strategy on teaching and learning methods.
- (ix) The instructional methods or pedagogy and the media mix should be clearly spelt out.
- (x) A comprehensive methodology for assessment and evaluation should be clearly stated.
- (xi) The content shall be reliable and justify the learning outcome(s).
- (xii) There shall be clear definition of intended outcomes of learning, benchmarked to identifiable stages of learning.
- (xiii) There shall be the use of reference points and expertise from outside the Higher Educational Institution, if required, in programme design and in the processes of programme development and approval.
- (xiv) There shall be relevance of curriculum to national competency requirement.
- (xv) There shall be description of credit value of each module or unit in the course.

B. For Online mode

E-Learning Materials Quality Standard:

I. The online courses should comply with the following Quality standards, namely:-

- (i) The courses should follow the following four quadrant approach, as per the SWAYAM Guidelines:-
 - (a) Quadrant-I is e-Tutorial; which shall contain: Video and Audio Content in an organized form, Animation, Simulations, video demonstrations, Virtual Labs, etc, along with the transcription of the video.


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 आन्दोलन एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हिं० प्र० विश्वविद्यालय, सिल्ला - ६

- (b) Quadrant-II is e-Content; which shall contain; self-instructional material (digital Self Learning Material), e-Books, illustrations, case studies, presentations etc, and also contain Web Resources such as further references, Related Links, Open source Content on Internet, Video, Case Studies, books including e-books, research papers and journals, Anecdotal information, Historical development of the subject, Articles, etc.
- (c) Quadrant-III is the Discussion forum for raising of doubts and clarifying the same on real time basis by the Course Coordinator or his team.
- (d) Quadrant-IV is Assessment, which shall contain; Problems and Solutions, which could be in the form of Multiple Choice Questions, Fill in the blanks, Matching Questions, Short Answer Questions, Long Answer Questions, Quizzes, Assignments and solutions, Discussion forum topics and setting up the FAQs, Clarifications on general misconceptions.
- (ii) The courses shall be rich in innovative presentation techniques to ensure that learner attention is retained.
- (iii) It shall be the responsibility of the Course Coordinator to ensure that none of the graphics, animations, images, sound clips, video clips used are plagiarized or cited without formal permissions from owners.
- (iv) A four-credit course shall typically have 20 hours of video content and 20 hours of reading material.
- (v) For Quadrant III for every 250 learners registered for a programme one Mentor can be appointed per course to facilitate the Course Coordinator. The Mentor shall be the subject matter expert adept in handling technology. The Course Coordinators and Mentors shall need to participate actively in the Discussion Forum. Apart from discussion forum other interactive platforms like web conferencing may also be considered.

Table 1: Norms for offering Degree programmes through Open and Distance Learning mode and/or Online mode, based on credit system

S. No.	Level of the Programme	Duration of the programme	Credits
1.	Bachelor's Degree, Bachelor's Degree (Honours)	As per UGC Notification on Specification of Degree, 2014	As per UGC guidelines
2.	Master's Degree	As per UGC Notification on Specification of Degree, 2014	As per UGC guidelines
3.	Post Graduate Diploma	2 years	80

Table 2: Norms for delivery of courses through open and distance mode

S. No.	Credit Value of the course	Size of SLMs Range (in terms of units, to be divided into blocks)	No. of Assignments	Practical Sessions	No. of Counselling Sessions Theory (10 percent of total study Hours)	Study hours of Learner
1.	2 Credits	6-10 units	1	60 hours	6 hours	60 hours
2.	4 credits	14-20 units	2	120 hours	12 hours	120 hours
3.	6 credits	20-28 units	3	180 hours	18 hours	180 hours
4.	8 credits	30-34 units	4	240 hours	24 hours	240 hours

उप कुलपति (प्रशासन)
अच्छा शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
हिंदू विश्वविद्यालय, विंगल-5

Table 3: Norms for Delivery of Courses in Online Mode

S. No.	Credit value of the course	No. of Weeks	No. of Interactive Sessions		Hours of Study Material		Self-Study hours including Assessment etc.	Total Hours of Study (based on 30 hours per credit)
			Synchronous Online Counselling/ Webinars/ Interactive Live Lectures (1 hour per week)	Discussion Forum/ asynchronous Mentoring (2 hours per week)	e-Tutorial in hours	e-Content hours		
1.	2 credits	6 weeks	6 hours	12 hours	10	10	22	60
2.	4 credits	12 weeks	12 hours	24 hours	20	20	44	120
3.	6 credits	14 weeks	14 hours	28 hours	30	30	60	180
4.	8 Credits	16 weeks	16 hours	32 hours	40	40	88	240


Annexure VII

GUIDELINES ON SELF-LEARNING MATERIAL AND E-LEARNING MATERIAL

1. Preparation of Learning Material

A. For Open and Distance Learning mode

1. Self-Learning Materials (SLMs) should be self-explanatory, self-contained, self-directed, self-motivating and self-evaluating. It should be engaging and actively involve the learners. During the planning of the Self Learning Material, the following points should be considered very carefully:
 - (i) backgrounds of learner and learning needs;
 - (ii) learning experiences; and
 - (iii) support and preparation in adapting to flexible learning.
2. The following major points should be considered by teachers while developing the printed learning materials or e-learning materials:
 - (i) learning objectives
 - (ii) assessment of prior knowledge
 - (iii) learning activities
 - (iv) feedback of learning activities
 - (v) examples and illustrations
 - (vi) self-assessment questions/In-text questions
 - (vii) summary/key points
 - (viii) study guide
3. The learning material should lay emphasis on real-world tasks, learner's choice of tasks or situations, case studies, collaborative learning tasks, opportunities for observing others, self-evaluation.
4. **Planning for development of learning material:** Due to the absence of interaction with the teachers in the Open and Distance Learning mode, the learner has to take the decision(s) at any point during the learning path. This may create disagreement between learner's perception and the objective of the learning materials. Therefore, it is required to consider the following key points during planning for the development of learning material:
 - (i) **Learner Profile:** It is required to consider literacy level (including level of language proficiency), age group, information communication technology skills, aim of study, personal background and home situation, prior knowledge, prior skills, learning situations, etc.


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अ०टू०शि० एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हि०प्र० विश्वविद्यालय, शिमला-5


- (ii) **Background:** In Open and Distance Learning system, learner studies at her/his own pace unlike in the face-to-face mode. A substantial number of the learners are working professionals and they get time to study at their homes. If we add certain references which they cannot access at home, then it will create an obstacle in their learning. Therefore, it is necessary to consider the accessibility of course resources and references at the place of learning.
- (iii) **Learning Objectives and Outcome:** It is required to define the learning objectives and outcomes prior to initiating the process developing the learning materials. The learning objectives can be of terminal, intermediate or enabling nature. These learning objectives can be set at course, unit, or module level.
5. **Group of Learning Material:** Considering the principles of Open and Distance Learning mode of education, the programmes shall be accompanied with learning material or resources which shall comprise of self-learning material or e-learning material, e-books, practical book, student's handbook, question bank, assignment book, Audio Video material, programme guide, project manual, etc.

B. For Online mode

1. The E-Learning Material shall have the four quadrant approach; as per UGC (Credit Framework for online learning courses through SWAYAM) Regulations, 2016 taking into consideration the following, namely:-
- Quadrant-I is e-Tutorial; which shall contain: Video and Audio Content in an organised form, Animation, Simulations, Video Demonstrations, Virtual Labs, etc., along with the transcription of the video.
 - Quadrant-II is e-Content; which shall contain; self instructional material, e-Books, illustrations, case studies, presentations etc, and also contain Web Resources such as further references, Related Links, Open source Content on Internet, Video, Case Studies, books including e-books, research papers and journals, Anecdotal information, Historical development of the subject, Articles, etc.
 - Quadrant-III is the Discussion forum for raising of doubts and clarifying them on a near real time basis by the Course Coordinator or his team.
 - Quadrant-IV is Assessment, which shall contain; Problems and Solutions, which could be in the form of Multiple Choice Questions, Fill in the blanks, Matching Questions, Short Answer Questions, Long Answer Questions, Quizzes, Assignments and solutions, Discussion forum topics and setting up the FAQs, Clarifications on general misconceptions.

II. Preparedness of Learning Material

- A. **For Open and Distance Learning mode:** The preparedness level of Self Learning Material (SLM) at the time of submission of the proposal shall have the following, namely:-
- Under Graduate Programmes (3 years duration): Self Learning Material should be ready in all respect for first two years and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution.
 - Post Graduate Programmes (2 years duration): Self Learning Material should be ready in all respect for first year and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution.
 - For Post Graduate Diploma Programmes (2 years duration): Self Learning Material should be ready in all respect for first year and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution.
- B. **For Online mode:** The availability of E-Learning Material at the time of submission of the proposal shall be as per the following:
- For Post Graduate Level Programmes- First year e-learning material in four quadrants


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अखिल भारतीय विश्वविद्यालय
 हिंदू विश्वविद्यालय, शिमला - 5

for each course in the first year of study and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;

- (ii) For Under Graduate Level Programmes- First three semesters e-learning material in four quadrants for each course and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;
- (iii) For Post Graduate Diploma Programmes- First year e-learning material in four quadrants for each course in the first year of study and its approval by the statutory authorities of the Higher Educational Institution;

Provided that for remaining year/semester, the learning material for programmes shall be ready prior to beginning of next year/semester and same shall be intimated to the Commission.

Annexure VIII

LEARNER SUPPORT CENTRES

I. General:

Open and Distance Learning (ODL) mode of Education consists of three levels of functioning which are located at the Head Quarters (HQ) of the Higher Educational Institutions, Regional Centres and Study Centres (SCs) or Learner Support Centres (LSCs) established within the territorial jurisdiction of the Higher Educational Institution as defined in the following Part. The management of the processes of Admissions, Evaluation, and Declaration of Results etc. are the main responsibilities of the Head-Quarters of the Higher Educational Institution and are discharged from the main campus. Under the direct management and control of the Higher Educational Institution, Regional Centres which are the second level of functioning, perform a dynamic operational link between the Head-Quarter and the Learner Support Centres (LSCs) which are the third level of Open and Distance Learning system and are important main contact points for access by the learners, responsive and facilitating information centres, arranging contact sessions and other operations like processing of assignments etc. The Learner Support Centres (LSCs) will also be established and managed directly by the Higher Educational Institution and not through any franchise or outsourced arrangement:


Provided that a Private University established under the State Act shall be eligible to offer programmes under Open and Distance Learning mode through its Head Quarters only and duly recognized off-campus centres. A Private University shall not offer programmes under Open and Distance Learning mode through any Learner Support Centre.

II. Definition and Establishment of Learner Support Centre or Study Centre

- I. Learner Support Centre (LSC) means a Centre established and recognised by the Higher Education Institution for advising, counselling, providing interface between the teachers and the learners, rendering academic and any other related services and assistance, required *inter alia* by the learners of Open and Distance Learning Mode:

Provided that a Higher Educational Institution offering programmes in Open and Distance Learning mode shall ensure that all Study Centres or Learner Support Centres are established only in a College or Institute affiliated to a recognised university (other than a Private University) or a Government recognized Higher Educational Institution offering conventional mode programmes of equivalent level in the same broad areas under the relevant faculty such as faculty of sciences or social science or humanities or commerce or management etc. and having all the necessary infrastructure and availability of appropriate number of qualified faculty not below the rank of qualified Assistant Professors of recognised Colleges or Institutes offering a similar programme for engaging theory contact sessions and supervising practical sessions in laboratory or field:

Provided further that a Higher Educational Institution shall establish a Special Learner Support Centre for imparting instruction to persons referred to in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995,


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अन्दूशिंग एवं दूरस्थ अध्ययन केन्द्र
 हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली-5

the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act, 1999 including the employees of Defence or Security Forces and jail inmates interested to study through the Open and Distance Learning mode:

Provided also that, in case of exigency or non-availability or non-willingness of an Institution/College as specified above for a specialized programme or a special component of a programme, the HEI shall activate Work Centre/Programme Centre at the Government aided/affiliated/recognized Research and Extension Institutions such as Krishi Vigyan Kendras, State Training Institutes/Industrial Training Institutes; Government Organizations/ Departments; Accredited Laboratory; Government Licensed Industry; and approved Vocational Institutes having infrastructure, facilities and human resource as specified by the Statutory bodies for a programme or a few courses of a programme.


2. Any Study Centre or Learner Support Centre shall be established by the Higher Educational Institution after processing through the appropriate statutory bodies of the Higher Educational Institution. While processing such approvals it is mandatory to provide evidence of the preparedness for establishing Study Centres/Learner Support Centres, providing learner support services, availability of the academic, other staff and qualified academic counsellors.
3. The Higher Educational Institution shall have a Standard Operating Procedure for the smooth functioning of the Study Centre or Learner Support Centre which shall include all aspects of functions of the Study Centre or Learner Support Centre, monitoring mechanism of different services provided by the Centre, and it shall be mandatory for the Study Centre or Learner Support Centre to maintain the learner data related to conduct of counselling sessions, evaluation of assignments and effective and online grievance redressal system, which should be monitored at the level of regional centre and Head Quarters.
4. The list of Study Centres or Learner Support Centres with details such as: Name with address of the institution where the centre is located, name of the coordinator with contact details, working hours and schedules for counselling sessions, infrastructure and other facilities available in the Study Centre or Learner Support Centre shall be displayed on the web portal of the Open and Distance Learning institution and the same information shall be made available in the printed prospectus for the information of the learners and other stakeholders.
5. A Higher Educational Institution shall submit an undertaking to the Commission to the effect that the academic and instructional facilities at its Study Centres or Learner Support Centres meet all the conditions of these regulations and guidelines issued from time to time, and are commensurate with the number of academic programmes and learners' strength thereto- Provided that the Higher Educational Institution shall not carry out any of its activities related to the Open and Distance Learning mode at places other than Study Centres or Learner Support Centres under a different name such as Information Centre, Facilitation Centre, Nodal Centre, Knowledge Partner, Partner Institution, Multimedia Centres and similar such names:

Provided that, no Study Centre or Learner Support Centre shall be established beyond the territorial jurisdiction of the Higher Educational Institution or under any franchisee or outsourcing agreement, as described in these regulations:

Provided further that a Study Centre or Learner Support Centre shall not admit a learner to any programme in Open and Distance Learning mode for or on behalf of any other Higher Educational Institution.

III. Norms for Empanelment of Academic Counsellors and Counselling Sessions

1. **Eligibility conditions for appointment of academic counsellors:** The academic staff in the Study Centre or Learner Support Centre shall fulfil the minimum qualifications as laid down in the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in the Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018. In addition,


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अ.सू.सि. एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हि.प्र. विश्वविद्यालय, बिबला - 8

such academic staff should have familiarity with the Characteristics of Open and Distance Learning mode learners and their needs, difference between Open and Distance Learning and conventional face-to-face education, awareness about instructional design, familiarity with the learner centered approach in blended mode of learning, ability to use different delivery media including online and computer mediated communication and Information and Communication Technology enabled learning.

2. **Norms for Personal Contact Programmes:** Credit Based System has been followed by Open and Distance Learning single mode Higher Educational Institutions during the last more than two decades and it has got standardized for programme delivery especially by the Open Universities. Such credits depend on the total number of hours that a learner is required to cover for all activities like participation in Personal Contact Programmes, Working on Assignments, Library Consultation etc., in completing a course. In this direction, the guidelines of University Grants Commission on Choice Based Credit System (CBCS) is mandatory for all Higher Educational Institutions delivering education through conventional mode. Accordingly, for Post Graduate programmes in Open and Distance Learning mode, 16 credits per semester are assigned for a total of four semesters, on an indicative basis for explaining the concept, however shall be governed by the number of credits as defined by the Commission from time to time. In Open and Distance Learning mode Programme delivery, the component of contact with teachers is comparatively much lower than the conventional or face to face mode which is complemented by self-learning on the part of the learner.

The following table is provided for norms for counselling sessions in theory and practical courses for Open and Distance Learning mode programme delivery.

Table: ODL programmes - Contact Sessions for Theory and Practical Courses; on an indicative basis


Four Courses, each of 04 Credits, with a total of 16 Credits per semester			
Number of Assignments	10-12 credits for theory and 6-4 Credits for practical courses		Counselling for theory only Courses:
	Contact sessions- practical	Contact sessions-theory	Four courses of 4 credits each
Four per semester	60 hours of guided experiments with support of internal supervisor per 2 credits	30-36 hours	12 hours per course

Note (1): Contact session up to the extent of twenty per cent., or as defined by the Commission from time to time, could be arranged by providing Massive Open Online Courses and other online programme delivery systems.

Note (2): Practical sessions to the extent of twenty per cent., or as defined by the Commission from time to time, could be provided through virtual lab mode.

IV. Deployment of work force and other support at study or Learner Support Centres

- The Study Centres or Learner Support Centres shall be headed by a Coordinator, not below the rank of an Assistant Professor and shall be augmented with academic and non-academic staff depending on the number of learner, assigned for adequate support to the learners. There shall not be any restrictions in the capacity of intake in Open and Distance Learning programme at the Learning Support Centre or Study Centre and Main campus. The capacity of intake per programme should be commensurate with the available qualified faculty in relevant area, well equipped laboratory, library, online connectivity and Information and Communication Technology facilities, and appropriate infrastructure, along with the following:


 उप कुलसचिव (पशुसंरक्षण)
 अंडरूनिंग एवं सुसज्जित अध्ययन केन्द्र
 क्रिष्ण विश्वविद्यालय, शिमला - 5

- (i) Number of qualified counsellor to number of students shall be 1:100 per theory course;
- (ii) Number of qualified supervisors per practical course of 2 credits: 1 or more;
- (iii) Availability of laboratory: The laboratory should be in a recognised Higher Educational Institution offering a similar programme in conventional mode for a period of not less than 3 years.

V. Monitoring of functioning of the Learner Support Centres or Study Centres

The Higher Education Institution shall have dynamic Information and Communication Technology based interactive communication system between Head Quarters, Regional Centres and Study Centres.

- (i) Log in email ID shall be generated for every learner so that learners can have a two-way communication, interact with various functionaries of the Institution and provide constructive feedback for improvement in Open and Distance Learning programme delivery;
- (ii) Head Quarters, Regional Centres and Study Centre or Learner Support Centres shall maintain a web portal giving all relevant and updated information about the Open and Distance Learning programmes being delivered. The content of these shall be updated at least on a weekly basis;
- (iii) Regional Centres, as applicable shall collect a holistic report about all aspects of the functioning and quality of programme delivery of Study Centres or Learner Support Centres periodically especially during the Admissions, Examinations, and Counselling Sessions etc., and share a consolidated report with the Head Quarters on a weekly basis;
- (iv) These reports alongwith responses by learners shall be periodically
- (v) analysed for the quality audit of a programme and its delivery besides the quality of performance of the Study Centres or Learner Support Centres;
- (vi) Any remedial action shall be jointly ensured by the Head Quarters, Regional Centres and Study Centres or Learner Support Centres promptly;
- (vii) Regular visits, at least twice a year by the academic staff of the Higher Educational Institution for on the spot monitoring and interaction with functionaries of the Regional Centres and Study Centres or Learner Support Centres, the learners and the counsellors; and
- (viii) Ensuring access of "SWAYAM" and other repositories of Massive Open Online Courses by the learners at Study Centres or Learner Support Centres.

VI. Closure of Non-performing Study Centre or Learner Support Centre:


In case a Study Centre or Learner Support Centre fails to adhere to the prescribed norms or guidelines, the Higher Educational Institution shall initiate action for closure of the centre by following due procedures, so that interests of learners are taken care by some alternative arrangement.

Annexure IX

**ASSESSMENT CRITERIA FOR OFFERING ONLINE PROGRAMMES
THROUGH NON-SWAYAM LEARNING PLATFORM**

I. Provisions:

Learning Platform, other than SWAYAM, used for delivery of online programmes shall be assessed by a Technical Expert Committee duly constituted by the Commission and the learning platform shall broadly have the following provisions:


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अन्दूशि० एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हि०प्र० विश्वविद्यालय, शिमला-६

1. **User and Course management**

- (i) **User Management:** Role Based authentication, User Registration, User Profiling along with personalised dashboard. User's activities analytics. Learning Management System should have Application Programming Interface Integration facility to integrate with external Application/tools.
 - (ii) **Course Content Management:** Learning Management System must support all types of files (PDFs, docs, MP3s, MP4s etc.) and e-Learning formats, and data collection capabilities.
 - (iii) **Capability for Personalized Learning Experience:** The platform should allow to create personalised learning paths along with criteria that are necessary to be met before they move on to the next content.
2. **Collaboration and Communication:** The platform shall be able to foster communication and peer-to-peer interaction among learners with features such as online chats, discussion forums, user groups, built-in messenger etc.
 3. **Assignment and Quiz management:** Self-assessment creation (assignment, quiz), announcement. It shall support all types of Questions (Multiple Choice Questions, True and False, Matching, subjective short and long questions etc.).
 4. **Accessibility across Devices and Mobile Learning:** Learning Management System shall allow its learners to access courses on different devices, i.e. Personal Computers, Laptop, tab or smart phones.
 5. **Security and Privacy:** As Learning Management System holds personal records of learners, it is important to ensure that the Learning Management System has privacy controls, protected logins, and utilizes secure server locations to keep users' data safe.

II. **Parameters for Assessment of Online Platform:**

The assessment of a non-SWAYAM platform by the technical Expert Committee shall be broadly based on the following parameters, alongwith any other criteria as notified by the Commission from time to time:

1. **User friendliness**

Indicative terms of reference:

- (i) Ease of use/proper navigation/attractive presentations in User Interface.
- (ii) Availability of Interfaces/delivery mechanisms—web, mobile desktop, instant messaging, video conferencing, audio graphic systems etc.
- (iii) Availability of proper internet connection in case of web-based interfaces.
- (iv) Representation of content-text/graphical, exercises, tutorials, Examples, case studies etc.

2. **Content Storage and Management provisions**

Indicative terms of reference:


- (i) Production of contents;
 - (ii) Video-Audio Storage mechanism (name of cloud service provider; streaming services used);
 - (iii) Ease of access to content;
 - (iv) Reliability and availability of content at all times.
3. Synchronous Interaction provisions (video/audio conferencing, live chat etc.)
 4. Asynchronous Interaction provisions (Discussion Forum, Blogs, Wikis etc).
 5. Learner engagement provisions (interactive content, activity management, group projects).

उप कुमारी (प्रशासन)

ऑटोमैटिक एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र

डि० प्र० विश्वविद्यालय, शिमला - ६

6. Peer group interaction provisions (social media integration, group activity, breakout rooms etc.).
7. Learning Communities/Research forums.
Indicative terms of reference:
 - (i) Collaboration of internal/external communities;
 - (ii) Collaboration methodology.
8. Adaptive learning provisions (skill gap analysis, personalised content).
9. Provision for grouping the learners with different mentors
 - (i) One mentor to be assigned for 250 learners as per the regulations
10. Dashboard options for all the stakeholders.
11. Proctored examination methodology.
Examination support- formative and summative Indicative terms of reference:
 - (i) Online question bank management, paper setting, valuations
 - (ii) Online student registrations and exam scheduling
 - (iii) Online generation of grades based on continuous evaluation
 - (iv) Learner authentication
12. Examination support- Multiple choice and Long/ Short answers
13. Provisions for Online assignment creation, submission and grading
14. Availability of tool to keep students informed about activities, performance etc.
15. Plagiarism check provisions.
16. Methodology for online payment gateway
17. Flexibility.
Indicative terms of reference:
 - (i) Browsers supported,
 - (ii) Main site having responsive design.
18. Support for the standard four quadrant approach, which is followed by SWAYAM.
19. Provision of online award of certificates/degrees.
20. Proposed methodology to train the faculty to effectively Design Develop and Deliver Massive Open Online Courses (MOOCs).
21. Security features from transparency and credibility perspective.
Indicative terms of reference: (i) at all levels including IP tracking of the learner.
22. Scalability
Indicative terms of reference:
 - (i) Maximum users;
 - (ii) Number of users able to log in simultaneously.
23. Proposed methodology to ensure that the faculty engages with the student, motivates them and assesses them.
24. Provision for an appropriate organizational setup in the HEI for maintaining and running the platform.
25. Proposed methodology to ensure the quality of courses.


 उप कुलसचिव (प्रशासन)
 अ० दूर० शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
 हि० प्र० विश्वविद्यालय, दिल्ली-६

GRIEVANCE REDRESS MECHANISM**I. Scope of Grievance Redress System for Learner**

The Higher Educational Institutions, offering programmes through the Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall have a Grievance Redress System and Procedure which shall be published on the portal of Higher Educational Institution and it shall be the responsibility of the concerned Higher Educational Institution to update the same as and when required. Each of the Higher Educational Institutions shall provide an online facility for submitting grievances and track their status. The Higher Educational Institution shall also be responsible for monitoring, assessing and reviewing the effectiveness of its Grievance Redressal Procedures.

II. Guidelines and Standards for the Grievance Redress System


The Higher Educational Institution shall have a policy on Grievance Redress System based on following guidelines and standards, namely:

- (i) the policy shall be unbiased and understandable;
- (ii) there shall be time line for each stage of the process;
- (iii) the policy shall be published on Higher Educational Institutions portal so that the learners may read and refer to;
- (iv) the policy shall be made available to learners with disability in appropriate format and the provision shall be made accordingly in the policy document;
- (v) the authority or authorities involved in the grievance redressal process shall treat and investigate the facts impartially;
- (vi) the Higher Educational Institutions shall address the grievances in a timely manner so as to lessen interruption in learning process of the learner;
- (vii) the Higher Educational Institution shall have a proper communication and escalation mechanism which shall be operated and maintained through the online software application;
- (viii) the Higher Educational Institution shall maintain the confidentiality of the complainant as far as possible;
- (ix) the Higher Educational Institution shall ensure that officer(s) deputed for the learner support at the Higher Educational Institution, the Regional Centres and Learner Support Centre(s) (for Open and Distance Learning programmes) are able to provide guidance on submitting grievances in the portal;
- (x) there shall be a provision to withdraw a complaint without prejudice at any time during the procedure; and
- (xi) the learner shall be kept informed of the status in relation to his or her queries or grievance on priority.

III. Rights and responsibilities of learner

The rights and responsibilities of a learner shall be as under:

- (i) The learner has right to complain regarding any aspect related to his or her learning path including programme quality, learning resources, learner support and guidance, teaching, learning and assessment.
- (ii) The learner is entitled to approach the respective Learner Support Centres (for ODL programmes) for submitting his or her complaint. The learners of online mode may submit their complaint directly to the Higher Educational Institution. The complaint can be submitted individually or collectively by a group of learners.
- (iii) The learner shall submit a formal complaint in a manner prescribed by the Higher Educational Institution regarding expression of dissatisfaction with a service provided or the lack of a service or the quality of a service. Such expression shall be correlated with what the learners were entitled to receive.


उप कुलसचिव (प्रशासन)
अनुसंधान एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
हिन्दू विश्वविद्यालय, शिमला-5

IV. Responsibilities of the Higher Educational Institution

The responsibilities of the Higher Educational Institution shall be as under:

- (i) A Higher Educational Institution shall work with the principles of openness and collaboration.
- (ii) A Higher Educational Institution shall continuously improve the services it offers. As and when a grievance is received, the Higher Educational Institution shall investigate it thoroughly and make the necessary improvement(s) in its services.
- (iii) A Higher Educational Institution shall encourage Learner Support Centres (for Open and Distance Learning programmes) to make initial attempts to address and resolve complaints as close as possible to the point of origin, and with the minimum of formality.
- (iv) A Higher Educational Institution shall also monitor the Grievance Redressal process through its Learner Support Centres (for Open and Distance Learning programmes).
- (v) A Higher Educational Institution is responsible for privacy and confidentiality unless disclosure is necessary to proceed in the matter.
- (vi) The grievance shall be accompanied with the reasons for dissatisfaction and expected remedy. The learner shall also give the reference of Online Grievance Registration Number generated at the time of submitting the complaint at the Learner Support Centre.
- (vii) The Head of concerned School/Department/Centre of the Higher Educational Institution shall investigate the complaint(s) or refer the matter(s) to a more appropriate person, body or committee or departments, as appropriate.
- (viii) It shall be the responsibility of the Head of School/Department/Centre of the Higher Educational Institution to monitor the progress and to timely resolve the matter.
- (ix) The Head of concerned School/Department/Centre of the Higher Educational Institution shall respond in writing (letters or email etc.) through offline or online mode giving reasons for a decision and action taken there to.


V. Complaint Handling Mechanism

The Online "Complaint Handling Mechanism" facilitates learners to submit online complaints through the interactive web portal and track their resolution status. The Higher Educational Institutions shall take action as under:

- (i) The Higher Educational Institutions recognised to offer programmes through the Open and Distance Learning mode and/or Online mode shall follow guidelines related to the Complaint Handling Mechanism notified by the Commission.
- (ii) The Higher Educational Institutions shall upload all information issued by the Commission regarding the Complaint Handling Mechanism on their website.
- (iii) The Higher Educational Institutions shall inform learners enrolled in Open and Distance Learning programmes and/or Online programmes about the Complaint Handling Mechanism.
- (iv) The Higher Educational Institutions shall provide a link with title 'Complaint Handling Mechanism' on homepage of Higher Educational Institution website for creating awareness amongst the stakeholders.
- (v) The Higher Educational Institutions shall comply with all instructions as issued by the Commission regarding timely and judicious resolution of all complaints raised by the learners.

RAJNISH JAIN, Secy. (UGC)

[ADVT.-III/4/Exty./212/2020-21]


उप कुलसचिव (प्रशासन)
अ० दू० वि० एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र
हि० प्र० विश्वविद्यालय, शिमला - 6

- 67 -

Joint Proceeding of the meeting held on 10.09.2020 & 16.09.2020 at 11.30 P.M. in the Chamber of Director (ICDEOL), H.P. University, regarding compliance of the provisions of the new Regulations, 2020 Issued by the UGC (DEB). The following members were present:-

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Prof. Kulwant Singh Pathania, Director | -Chairman |
| 2. | Prof. Neelima Kanwar, Deptt. of English (ICDEOL) | -Member |
| 3. | Prof. Kuldeep Singh Katoch, Deptt. of Education (ICDEOL) | -Member |
| 4. | Dr. Ashwani Rana, Deptt. of English (ICDEOL) | -Member |
| 5. | Dr. Sharda Devi, Deptt. of History (ICDEOL) | -Member |
| 6. | Dr. Ankush Bhardwaj, Deptt. of History (ICDEOL) | -Member |
| 7. | Dr. Dev Raj, Deptt. of Sanskrit (ICDEOL) | -Member |
| 8. | Dr. Monika Sood, Deptt. of Education (ICDEOL) | -Member |
| 9. | Dr. Chaman Lal Banga, Deptt. of Education (ICDEOL) | -Member |
| 10. | Sh. Amar Singh, Asstt. Registrar (Admn) ICDEOL | -Convener. |

The Chairman welcomed the CIQA Committee members, who were present in the meeting. The provisions enumerated in the notification issued by the UGC (DEB) circulated to all the members discussed by the committee thoroughly and following decisions were taken:-

1. The Committee unanimously decided that the new Regulations, 2020 issued by the UGC (DEB), notified in the Gazette of India on 4.09.2020 is adopted by this University in letter and spirit.
2. It was also decided to upgrade the present CIQA committee with the approval of Hon'ble Vice - Chancellor in view of provisions available under Regulation 2020.
3. The Director directed all the members to go through the contents of new Regulation 2020 and prepare points for discussions, so that final decision on each points could be taken for implementation in the University.
4. Accordingly the committee again met on 16.09.2020, whereby 10 committees were proposed to implement the Regulation 2020 to adhere all the instructions/guidelines of the new Regulation 2020.

Meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(Dr. Chaman Lal Banga)

(Dr. Monika Sood)

(Dr. Dev Raj)

(Dr. Ankush Bhardwaj)

(Dr. Sharda Devi)

(Dr. Ashwani Rana)

(Prof. Kuldeep Kumar Katoch)

(Prof. Neelima Kanwar)

(Amar Singh)

-Convener-

(Prof. Kulwant Singh Pathania)
Director (ICDEOL)

उप कुलसचिव (प्रशासन)
लक्ष्मी एवं सुकत अध्ययन केंद्र
विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष - 8

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 22.09.2021 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट ।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न सम्मेलन कक्ष आर्म्सडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2 में आचार्य सिकन्दर कुमार, कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | आचार्य सिकन्दर कुमार,
कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5 | अध्यक्ष |
| 2. | श्री प्रबोध सक्सेना,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 | सदस्य |
| 3. | श्री राजीव शर्मा,
सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला - 2 | सदस्य |
| 4. | आचार्य पी. के. गर्ग,
हि.प्र. विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, शिमला-5 | सदस्य |
| 5. | आचार्य नागेश ठाकुर,
भौतिक विज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला - 5 | सदस्य |
| 6. | श्री सुनील शर्मा,
कुल सचिव, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5 | सदस्य |
| 7. | श्री बंसी लाल शुक्ला,
वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला 5- | सदस्य-सचिव |

सदस्य सचिव (वित्त समिति) श्री बंसी लाल शुक्ला द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं सम्माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय से बैठक प्रारम्भ करने हेतु उन्हें अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया ।

अध्यक्ष
कुलपति
सचिव

खंड-1

मद संख्या 1 कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति की बैठक के प्रारम्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) श्री प्रबोध सक्सेना जी, सचिव (शिक्षा) श्री राजीव शर्मा जी तथा अन्य सभी सम्माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा सूचित किया कि यह बैठक एक वर्ष से भी अधिक समय के उपरांत सम्भव हो पाई है। कुलपति महोदय ने वित्त समिति के निवर्तमान मनोनीत सदस्यों का उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया तथा नए मनोनीत सदस्यों आचार्य नागेश ठाकुर और आचार्य पी के गर्ग का स्वागत किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार का विश्वविद्यालय के इस वर्ष की सहायता अनुदान राशि को 125.50 करोड़ से 138.05 करोड़ बढ़ाए जाने पर आभार प्रकट किया।

उन्होंने यह भी सूचित किया कि विश्वविद्यालय में रिक्त चल रहे पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है तथा अभी लगभग 150 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है और बाकी रिक्त पद भरे जाने की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त गैर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी है। इस वर्ष NAAC के द्वारा भी विश्वविद्यालय का मूल्यांकन किया जाना है जिसके लिए विश्वविद्यालय बेहतर परिणाम के लिए प्रयासरत हैं तथा हम अपेक्षा करते हैं कि विश्वविद्यालय के ग्रेड में सुधार होगा। उन्होंने समिति को यह भी सूचित किया कि पिछली वित्त समिति की बैठक में 04 नए विभागों के सृजन की अनुमति प्रदान की गई थी तथा इस बैठक में भी पिछले सृजित विभागों को सुदृढ़ करने तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त नए विभाग सृजित करने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय द्वारा सावित्री बाई फुले पीठ, संत शिरोमणि गुरु रविदास पीठ एवं श्री वीरभद्र सिंह पीठ की स्थापना कर कियाशील बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है।

इसके अतिरिक्त पंजाब वेतन आयोग को लागू करने के लिए भी विश्वविद्यालय को वेतन एरियर देने के लिए लगभग 68 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी तथा इस पर लगभग 16 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता पड़ेगी।

अध्यक्ष द्वारा (P2) [Signature]

कुलपति महोदय द्वारा सूचित किया गया कि वह कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रही अर्थव्यवस्था से भली भांति परिचित हैं और उन्हें प्रदेश सरकार के सीमित संसाधनों का भी पूर्णतः बोध है लेकिन हमें शिक्षा पर किए गए प्रावधान को खर्च न मानकर इसे निवेश मानना चाहिए जिसकी समाज को कई गुणा वापसी होती है।

अंत में उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) व सभी अन्य सम्माननीय सदस्यों से, विश्वविद्यालय की प्राथमिकताओं को देखते हुए एवं प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए वित्त समिति के समक्ष रखे गए मदों पर सकारात्मक निर्णय लेने का अनुरोध किया ताकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को अग्रणी श्रेणी के विश्वविद्यालयों की पंक्ति में खड़ा किया जा सके।

अपने संबोधन के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा वित्त अधिकारी, सदस्य-सचिव, वित्त समिति को मदवार चर्चा प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की तथा वित्त समिति द्वारा मदवार की गई चर्चा एवं निर्णय निम्नलिखित है:

मद संख्या 2 वित्त समिति की दिनांक 16.06.2020 को नियमित एवं 28.09.2020 और 04.11.2020 को परिचालन द्वारा (By Circulation) की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

वित्त समिति की दिनांक 16.06.2020 को नियमित एवं 28.09.2020 और 04.11.2020 को परिचालन द्वारा (By Circulation) की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

मद संख्या 3 वित्त समिति की दिनांक 16.06.2020 नियमित एवं 28.09.2020 और 04.11.2020 को परिचालन द्वारा (By Circulation) की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट।

वित्त समिति की दिनांक 16.06.2020 नियमित एवं 28.09.2020 और 04.11.2020 को परिचालन द्वारा (By Circulation) सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट को अनुमोदित किया। वित्त समिति द्वारा दिनांक 16.06.2020 की बैठक में अतिरिक्त मसौदे की मद संख्या 9 पर लिए गए निर्णय में कोई भी परिवर्तन न करने का निर्णय लिया तथा विश्वविद्यालय नियम अनुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाए।

2024/06/24
Dr. P. C. [Signature]

मद संख्या 4 वित्तीय वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2020-21 के संशोधित बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 बजट अनुमानों को दिनांक 23.03.2021 की परिचालन द्वारा सम्पन्न हुई बैठक में अनुमोदित किया जा चुका है, जिसकी वित्त समिति द्वारा पुष्टि की गई।

मद संख्या 5 To place before the Finance Committee the matter for creation of additional positions of Teaching Faculty and Ministerial staff (as per UGC Guidelines) for four new Departments i) Library and Information Science, ii) Defence & Strategic Studies, iii) Environmental Science and iv) Microbiology opened from the academic session 2020-21.

वित्त समिति द्वारा विभागों में निम्नलिखित पदों का सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की :

(A) Teaching Posts:

Sr. No.	Name of the Department	Name of the Post	Number of Posts
1.	Library and Information Science	Assistant Professor	02
2.	Defence & Strategic Studies	Assistant Professor	02
3.	Environmental Science	Assistant Professor	02
4.	Microbiology	Assistant Professor	02

(B) Non-Teaching Posts (On Contract Basis)

Sr. No.	Name of the Department	Name of the Post	Number of Posts
1.	Library and Information Science	Jr. Library Attendant (₹ 4900-10680+1300 GP)	01
		JOA (IT) (₹ 5910-20200+1950 GP)	01
2.	Defence & Strategic Studies	Jr. Library Attendant (₹ 4900-10680+1300 GP)	01
		JOA (IT) (₹ 5910-20200+1950 GP)	01

अध्यक्ष, वित्त समिति

3.	Environmental Science	Laboratory Assistant (₹ 5910-20200+1900 GP)	01
		Jr. Library Attendant (₹ 4900-10680+1300 GP)	01
		JOA (IT)	01
		(₹ 5910-20200+1950 GP)	
4.	Microbiology	Laboratory Assistant (₹ 5910-20200+1900 GP)	01
		Jr. Library Attendant (₹ 4900-10680+1300 GP)	01
		JOA (IT)	01
		(₹ 5910-20200+1950 GP)	

मद संख्या 6 To place before the Finance Committee the matter for creation of additional positions of Teaching Faculty, Technical Manpower and Ministerial staff (as per UGC Guidelines) for four new Departments i) Department of Archaeology and Ancient History ii) Department of Population Studies, iii) Department of Data Science and Artificial Intelligence iv) Department of Forensic Science to be opened from the academic session 2020-21.

वित्त समिति द्वारा विभागों में शिक्षकों के निम्नलिखित पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की:

Sr. No.	Name of the Department	Name of the Post	Number of Posts
1.	Department of Archaeology and Ancient History	Associate Professor	01
		Assistant Professor	04
2.	Department of Population Studies	Associate Professor	01
		Assistant Professor	04
3.	Department of Data Science and Artificial Intelligence	Associate Professor	01
		Assistant Professor	04
4.	Department of Forensic Science	Associate Professor	01
		Assistant Professor	04

अनुसंधान विभाग (P.T. 3)

मद संख्या 7 विभागीय परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में प्राध्यापकों के नए पदों को सृजित करने का मामला वित्त समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु ।

वित्त समिति द्वारा विभाग में शिक्षकों के निम्नलिखित पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की:

Sr. No.	Name of the Post	Number of Posts
1.	Associate Professor	01
2.	Assistant Professor	02

मद संख्या 8 The matter of amendment in the R & P Rules to the post of Assistant Registrar/ ex-post facto recommendations, on the recommendations of the Recruitment & Promotion Committee is submitted before the Finance Committee for the consideration and decision.

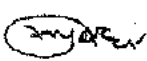
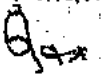


अनुमोदित ।

मद संख्या 9 The matter of amendment in the R&P Rules for the post of Personal Assistant on the analogy of the State govt. is placed before the Finance Committee for consideration and decision.

अनुमोदित ।

मद संख्या 10 विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अध्ययन केंद्र में स्वयं पोषित निधि के अंतर्गत कार्यरत श्री धीरज कांत अवस्थी, सेवादार जिनकी सेवाओं को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में समाहित करने उपरांत दिनांक 13.12.2019 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया है, के मामले में अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु ।

अनुमोदित ।

मद संख्या 11 To place before the Finance Committee the case of absorption of Mr. Avinash Bhardwaj against the post of Computer Laboratory Technician in the pay scale of Rs. 10300-34800+3200 GP in HPU Business School as per direction of the FC meeting dated 16.06.2020.

अनुमोदित । वित्त समिति द्वारा विभाग में वर्तमान में सृजित Lab Attendant के पद को समाप्त कर Computer Laboratory Technician के पद को वेतनमान 10300-34800+3200 GP में सृजित करने की स्वीकृति with prospective date प्रदान की

मद संख्या 12 भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अन्तर्गत सेवाकाल में छूट प्रदान करके सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ अनुमति हेतु प्रस्तुत ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 13 भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अन्तर्गत शैक्षणिक योगता में छूट प्रदान करके अर्ध व्यासियक सहायक के पद पर पदोन्नति का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमति हेतु प्रस्तुत ।

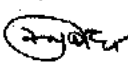



अस्वीकृत ।

मद संख्या 14 श्री प्रदीप कुमार, सेवानिवृत्त अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निहित प्रावधानों में छूट प्रदान कर उन्हें पूर्वव्यापी तिथि से अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए पूर्व में हुई भर्ती एवं पदोन्नति समिति का पुनर्विलोकन करने का मामला विचारार्थ /अनुमति हेतु वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 15 श्री दुनी चंद, भौतिकी विभाग में तकनीशियन ग्रेड-2 वेतनमान रु 10300-34800+4800 श्रेणी वेतनमान से श्री के.डी, धीमान की सेवानिवृत्ति से उपलब्ध रिक्त पद के विरुद्ध वरिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रुप-1 वेतनमान रु 15600-39100+5400 श्रेणी वेतनमान में संशोधित नियमितीकरण प्रदान करने बारे मामला ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 16 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीजी (स्नात्कोत्तर) में सत्र 2020-21 हेतु हॉस्टल निरंतरता फीस को माफ करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवम जो भी उचित संस्तुति हो हेतु रखने बारे।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 17 To place before the Finance Committee, the matter with regard to creation of (01) one post of Joint Director in the pay scale of Rs. 10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100 in the ICDEOL in pursuance to the notification No. Fin (PR)-B (7)-64/2010 dated 28.09.2012 issued by the Finance Department of Government of HP.

It was decided to first fix the cadre strength of editorial staff keeping in view the work load and existing strength at par with norm at State Government Level.

मद संख्या 18 भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अन्तर्गत सेवाकाल में छूट प्रदान करके उप कुलसचिव के पद पर श्री पूर्ण दत्त एवं श्री जगदीश राम ठाकुर सहायक कुलसचिव का पदोन्नति का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ /अनुमति हेतु प्रस्तुत ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 19 To place before the Finance Committee, the matter of adoption of Recruitment and Promotion Rules for the post of Programmers working in Computer Centre of the University, on the analogy of neighbouring university (Punjab University Chandigarh).

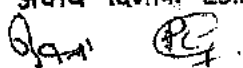
स्थगित।

मद संख्या 20 To place before the Finance Committee the matter regarding to make amendment in the R&P Rules of Himachal Pradesh Computer Staff Service (Recruitment, Promotion and certain conditions of service) Rules, 2010 for its approval.

अस्वीकृत ।

मद संख्या 21 श्री इन्द्र सिंह डोंगरा सेवानिवृत्त सुरक्षा अधिकारी के सेवा समाप्ति से बहाली तक की अवधि दिनांक 23.2.2005 से 26.8.2008 (3 वर्ष 6 माह 3 दिन) को सेवा अवधि (Duty







Period) माने जाने और इस अवधि के मध्य देय वित्त लाभों को सांकेतिक आधार पर रखने तथा उक्त अवधि को उनके सेवानिवृत्त लाभों हेतु अर्हक सेवा (Qualifying Service) में सम्मिलित करने हेतु व अन्य ऐसे मामले डॉ कुलदीप चंद अग्निहोत्री (सेवानिवृत्त आचार्य) व श्री अजय श्रीवास्तव, सह आचार्य पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 22 विश्वविद्यालय के संगणक केन्द्र परीक्षा विंग (Computer Centre Examination Wing) में रूसा प्रणाली (RUSA System) के अन्तर्गत परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को कार्यान्वित करने हेतु रखे गये दो प्रोग्रामर श्री लोकपाल व मंजुल शर्मा की सेवाओं को प्रथमतः आउटसोर्स तत्पश्चात् आकस्मिक प्रभार (Contingent Charges) पर से भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक छूट प्रदान करते हुए अनुबन्ध आधार पर लाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 23 श्री अशोक कुमार वर्मा एवं श्री मदन गोपाल शर्मा, निजी सचिव का वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर व्यक्तिगत क्रमोन्नति प्रदान करने का मामला वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ।

अस्वीकृत ।

खंड-II

मद संख्या 1 व्यवसायिक अध्ययन संस्थान (पर्यटन) में (01) एक आचार्य, (01) एक सह आचार्य, 05 सहायक आचार्य तथा गैर शिक्षक व तकनीकी कर्मचारियों में (01) एक मंडार रक्षक, (01) एक लिपिक, (01) एक चपरासी (01) एक पुस्तकालय परिचर व (01) एक कम्प्यूटर तकनीशियन के पद सृजन हेतु मामला वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

अनुमोदित

जा. (P.C.) 3

वित्त समिति द्वारा विभाग में शिक्षकों के निम्नलिखित पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की :

Sr. No.	Name of the Post	Number of Posts
1.	Assistant Professor (Tourism)	03
2.	Assistant Professor (Hotel Management)	02

मद संख्या 2 विद्वत् परिषद की स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव 06, दिनांक 16 नवंबर, 2019 की बैठक में गठित उपसमिति की दिनांक 20.12.2019 को आधिष्ठाता माषा संकाय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक के कार्य-विवरण को वित्त समिति की बैठक में चर्चा एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

अस्वीकृत।

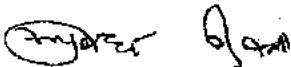
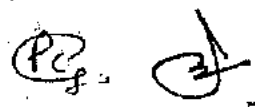
मद संख्या 3 वित्त समिति के समक्ष प्रधान निजी सचिव के 02 पद वेतनमान रुपये 37400-67000+8700 (ग्रेड-पे) तथा वरिष्ठ विशेष निजी सचिव के 02 पद वेतनमान रुपये 15600-39100+8400 (ग्रेड-पे) में सृजन करने का मामला विचारार्थ प्रस्तुत है।

अस्वीकृत।

मद संख्या 4 Creation of 04 positions of Associate Professors in Commerce (02 for ICDEOL and 02 for PG Centre, Shimla).

वित्त समिति द्वारा वाणिज्य विभाग में शिक्षकों के निम्नलिखित पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की :

Sr. No.	Name of the Department	Name of the Post	No. of Posts
1.	ICDEOL	Associate Professor	01
2.	P.G. Centre H.P University Shimla-5	Associate Professor	01

  -10-

मद संख्या 5 Placed before the Finance Committee, matter regarding Creation of two (02) posts of Assistant Professor (Mechanical-Engineering) in the pay scale Rs. (15600-39100 + 6000 GP), in the University Institute of Technology (UIT)

अनुमोदित ।

मद संख्या 6 To place before the Finance committee the minutes of the meeting of committee, [constituted vide notification of No. 1-104/2000-HPU(Genl.) Vol. V dated 04-05-2020 to waive off the Entrance Test fee, Hostel extension Fee and Research Scholar Fee in view of the Covid-19 Pandemic], for approval and decision.

वित्त समिति द्वारा संबन्धित विषय पर गठित समिति की 20.03.2021 को सम्पन्न हुई बैठक में लिए निर्णय जो कि (Not to be waved off) है के अनुसार संस्तुति प्रदान की ।

मद संख्या 7 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कम्प्यूटर प्रोग्रामर के एक पद को नियत संख्या से अधिक (Supernumerary) में सृजित करने के लिए मामला वित्त समिति की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन हेतु ।

अनुमोदित ।

मद संख्या 8 To place before the Finance Committee, the matter regarding amendment in the Recruitment and Promotion Rules for the post of Junior technician (Electrical) for approval.

अनुमोदित ।

मद संख्या 9 श्री देवेन्द्र कुमार चालक (हल्का वाहन) का प्रतिवेदन जिसमें उन्होंने पद को लिपिक के पद में परिवर्तित करने बारे अनुरोध किया गया है वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं जो भी उचित निर्णय हो हेतु रखने बारे ।

अस्वीकृत ।

अनुमोदित ११/११/२०२१ - ११ -

मद संख्या 10 सर्वश्री मूपेश कुमार शर्मा, रेवती नन्दन शर्मा, संजीव कुमार शर्मा व भाग सिंह समस्त चालक (हल्का वाहन) के प्रतिवेदन जिसमें उन्होंने उनके पद को लिपिक के पद में परिवर्तित करने बारे अनुरोध किया गया है वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं जो भी उचित निर्णय हो हेतु रखने बारे।

अस्वीकृत।

मद संख्या 11 To place before the Finance Committee the matter regarding upgradation of his post of system analyst to that of Director in the pay scale of i.e. Rs. 37400-67000+10000 AGP in r/o Dr. Mukesh Kumar, System Analyst Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-171005.

स्थगित।

मद संख्या 12 डॉ. जोगिन्द्र कुमार, परिचालक के अभ्यावेदन दिनांक 15.03.2021 जिसमें वाहन अधिकारी के पद को सीधी भर्ती द्वारा उप कुलसचिव के समक्ष वेतनमान रु 15600-39100+7600 ग्रेड पे (यू.जी.सी. स्केल) में सृजन हेतु प्रस्तुत मामला वित्त समिति से समक्ष प्रस्तुत है।

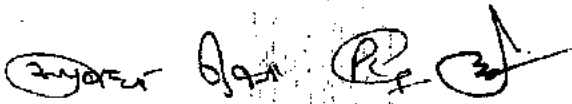
अस्वीकृत।

खण्ड III

मद संख्या 1 वित्त समिति के समक्ष हि०प्र० विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र, धर्मशाला विधि विषय के लिए दो सहायक आचार्य के पदों के सृजन बारे।

अस्वीकृत।

मद संख्या 2 To place before the Finance Committee the matter with regard to creation of one (1) Post of Professor in the subject of Sociology and six (6) posts of Assistant Professors in the subject of Sociology & Social Work i.e. 3 posts in each subject in the department of Sociology & Social Work.



वित्त समिति द्वारा विभाग में शिक्षकों के निम्नलिखित पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की:

Sr. No.	Name of the Post	Number of Posts
1.	Professor (Sociology)	01
2.	Assistant Professor (Sociology)	02
3.	Assistant Professor (Social Work)	02

मद संख्या 3 To place before the Finance committee the matter regarding creation of additional three posts of Assistant Professors in Painting.

वित्त समिति द्वारा विभाग में शिक्षकों के निम्नलिखित पदों के सृजन हेतु स्वीकृति प्रदान की:

Sr. No.	Name of the Post	Number of Posts
1.	Assistant Professor in Painting	02

मद संख्या 4 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों / संस्थानों/विभागों में संयुक्त/उप निदेशकों के पदों के सृजन का प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ व उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय के विभिन्न केन्द्रों/संस्थानों/विभागों में संयुक्त/उप निदेशकों के पदों हेतु वर्तमान उपलब्ध मानव संसाधनों में से ही (by way off internalization कर) निर्धारित मानदेय के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल में मुख्य अध्यापक के पद को समाप्त कर प्रधानाचार्य के पद सृजन करने हेतु स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 5 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सावित्रीबाई फुले पीठ, संत शिरोमणि गुरु रविदास पीठ एवं राजा वीरमद सिंह पीठ स्थापित/ कियाशील करने हेतु मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ व उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

अनुमोदित।

अध्यक्ष - वित्त (P. S.)

81

मद संख्या 6 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षक पदों के सृजन का प्रकरण वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ व उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

वित्त समिति द्वारा सहायक कुलसचिव के 10 पदों को सैद्धांतिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा सृजन करने का प्रस्ताव की अनुमति प्रदान की गई। इससे पूर्व इस सम्बन्ध में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या 7 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संकाय के कार्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु विभिन्न श्रेणियों के पदों को सृजित करने तथा इन पदों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग के संशोधित भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1985 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अपनाने बारे मामला वित्त समिति के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

वित्त समिति द्वारा नियमित पदों का सृजन न कर इस तरह की सेवाओं को न्यूनतम आवश्यकतानुसार तथा वित्तीय संसाधनों के मध्यनजर outsource करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 8 To place the matter before Finance Committee the matter of upgradation of the post of Executive Engineer (Const.) to the Superintending Engineer as a measure personal to Sh. Sanjay Sharma.

प्रदेश सरकार में यदि किसी कर्मचारी का एक ही पद पर 24 वर्ष का ठहराव हो तथा जहां पर 03 वर्ष या इससे कम समय में किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति का समय बचा हो तो उस अवस्था में व्यक्तिगत उन्नयन/कसोन्नति प्रदान की जा सकती है। अतः वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मापदंड का परीक्षण कर इस विषय में उचित कार्यवाही की जाये।

मद संख्या 9 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अधिशासी अभियंता के एक पद को दिनांक 30.12.2013 से दिनांक 18.10.2020 तक नियत संख्या से अधिक (Supernumerary) में सृजित करने के लिए मामला वित्त समिति की कार्योत्तर स्वीकृति / अनुमोदन हेतु।

स्वीकृत    -14-

अनुमोदित ।

-82-

मद संख्या 10 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सहायक जन सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री दिनेश कुमार एवं फॉटोग्राफर के पद पर कार्यरत श्री नरेश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन जो कि पेंशन लाभ के लिए सामान्य भविष्य निधि में समायोजित करने से संबंधित है, का मामला हि.0प्र0 विश्वविद्यालय की वित्त समिति के समक्ष अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि यह मामला सम्पूर्ण विवरण/न्यायलय मामलों के साथ वित्त विभाग के परीक्षणार्थ/विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या 11 To place the request of Smt. Suminder Gupta, Ward Sister for personal up-gradation to the post of Matron in the pay band of Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay before the Finance committee for consideration.

प्रदेश सरकार में यदि किसी कर्मचारी का एक ही पद पर 24 वर्ष का ठहराव हो तथा जहां पर 03 वर्ष या इससे कम समय में किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति का समय बचा हो तो उस अवस्था में व्यक्तिगत उन्नयन/कमोन्नति प्रदान की जा सकती है। अतः वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मापदंड का परीक्षण कर इस विषय में उचित कार्यवाही की जाये।

मद संख्या 12 To place before the Finance Committee the request of Smt. Sneh Lata, School Teacher, H.P. university Model School, Shimla for upgradation to the post of Head Teacher (HT).

अस्वीकृत ।

मद संख्या 13 To place the request of Sh. Tilak Raj, Junior Assistant before the Finance Committee regarding granting him extension for a further period of six months w.e.f. 1.6.2021 on fixed salary after retirement.

अस्वीकृत ।

अनुमोदित ।

-15-

खंड-IV

यथासंस्थान मर्दे

मद संख्या 1 To place before the Finance Committee the matter of creation of one supernumerary post of Junior Office Assistant (IT) under General (PWBD-Visually impaired Blind low vision category) in compliance of judgment/order dated 11.08.2021 in CWPOA No. 4462/2020 titled as Jagdish Kumar Versus State of HP & others.

वित्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस पद को पहले से स्वीकृत रिक्त पदों में से ही भरा जाए तथा सम्बन्धित उम्मीदवार को विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक बुनियादी एवं कम्प्युटर प्रशिक्षण Composite Regional Centre(CRC), Sundernagar or National Institute for the Visually Handicapped (NIVH), Dehradun or Composite Training Centre(CTC), Ludhiana से प्रदान कराया जाए ।




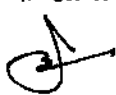
मद संख्या 2 The amendments in Rule-14.1-A and 14.7-B of Himachal Pradesh University Ministerial and Administerial Service (Recruitment, Promotion and Certain conditions of service) Rules, 1973 is placed before the Finance Committee for its consideration and approval.

अनुमोदित ।

मद संख्या 3 To place before the Finance Committee the matter with regard to creation of (02) two posts of Joint Directors in the pay scale of Rs. 10025-275-10300-340-12000-375-13500-400-15100 in the ICDEOL.

It was decided to first fix the cadre strength of editorial staff keeping in view the work load and existing strength at par with norm at State Government Level.

मद संख्या 4 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत 09 सुरक्षा रक्षकों, जिनको मूलतः बिना सृजित पदों के, भाड़े के आधार पर, निश्चित वेतन रु 8517/- मासिक पर लगाया गया था एवं तदोपरांत अनुबन्ध आधार पर एवं उसके बाद नियमित पर परिवर्तित किया गया है , द्वारा सेना में प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर वेतन वृद्धियां प्रदान करने बारे निवेदन के संदर्भ में

कार्यकारिणी परिषद से प्राप्त निर्णय/ अनुमोदन, कि विश्वविद्यालय के सुरक्षा विंग में कार्यरत सुरक्षा रक्षकों के पद पर नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोटे के अंतर्गत नियुक्त माना जाए तथा उन्हें सभी देय लाभ एवं वेतन वृद्धियां प्रदान की जाए, अनुसार नियमों में छूट प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं जो भी उचित संस्तुति हो हेतु ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 5 To place before the Finance Committee the matter with regard to engage/deployed the suitable persons/manpower on 'Outsource Basis'

(1) Mali (Trained/Experienced 10 Nos., (2) Helpers- 08 Nos., (3) Security Guards (Ex-serviceman) - 20 Nos. (15 for campus and 5 for R.C. Dharamshala), (4) Pump Operators-03 Nos., (5) Fitters -02 Nos.

वित्त समिति द्वारा नियमित पदों का सृजन न कर इस तरह की सेवाओं को न्यूनतम आवश्यकतानुसार तथा वित्तीय संसाधनों के मध्यनजर outsource करने की स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 6 हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालयक्षेत्रीय केंद्र, मौहली, खनियारा, धर्मशाला, कांगड़ा में स्टाफ नर्स के सृजित पद पर श्रीमति मधु बाला के स्थायी विलय करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं उचित संस्तुति हेतु ।

वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस मामले का पुनः परीक्षण करने के उपरान्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से NOC के साथ अगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

मद संख्या 7 To waive of the rent of shopkeepers in the University Campus for the lockdown period i.e. April 2020 to May 2020 and May 2021(Three Months)

अस्वीकृत ।

अनुमोदित

अनुमोदित


अनुमोदित


अनुमोदित


मद संख्या 8 To place before the Finance Committee the representation of Dr. Ashwani Kumar, Assistant Director (Sports), HPU Regional Centre, Dharamshala for grant of pay scale of Rs. 15600-39100+6000AGP.


वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इस संवर्ग की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया, कार्यकलाप तथा पदों के विवरण के साथ अगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

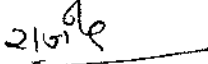
बैठक धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुई।



(बन्सी लाल शुक्ला)
सदस्य


(सुनील शर्मा)
सदस्य

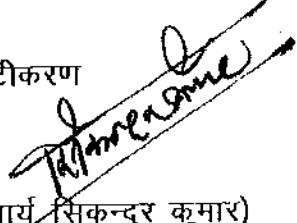

(आचार्य पी के गर्ग)
सदस्य


(आचार्य नागेश ठाकुर)
सदस्य


(राजीव शर्मा)
सदस्य


(प्रबोध सक्सेना)
सदस्य

पुष्टीकरण


(आचार्य सिकन्दर कुमार)
कुलपति,

हि.प्र. विश्वविद्यालय, शिमला-5

Annexure-A

**A
PROPOSAL
TO
ESTABLISH
CENTER FOR INDIAN MATHEMATICS
AT
DEPARTMENT
OF
MATHEMATICS & STATISTICS
HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY
SHIMLA (H.P.)**

Sanjay K. J. *Sharma* *Tease* *Shah* *Pune*
Sharma *Sharma*

Sharma
उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला - 171005

A Proposal to Establish
Centre for Indian Mathematics
at
Department of Mathematics & Statistics
Himachal Pradesh University, Shimla-171005

1. Introduction

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा ।
तद्वद्वेदाङ्ग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम् ॥ वेदांग ज्योतिष

"Like the crests on the head of peacock, like the gems on the hoods of the cobras, Mathematics is at the top of the Vedāṅga Śāstras"

The above śloka in Sanskrit highlights the importance of mathematics among all other branches of knowledge (sciences), since Vedic period.

Indian Mathematics is one of the oldest and longest-lasting traditions of scientific thought. It emerged in the Indian subcontinent in 1200 BC and lasted until the end of the 18th century. Contributions by Indian mathematicians such as Aryabhata, Brahmagupta, Bhaskara II, and Varāhamihira have been indispensable in the development of science and mathematics and for the benefit of humankind, as a whole. Specifically, many important mathematical concepts such as; decimal number system, concept of zero as a number, negative numbers, arithmetic, and algebra were developed and envisioned by Indian mathematicians. These mathematical concepts and ideas were traveled to the Middle East, China, and Europe which led to further developments of the subject that now form the basis of modern mathematics.

Indian mathematician Aryabhata, who wrote the *Aryabhatiya* (or *Aryabhatiyam*) a Sanskrit astronomical treatise, represented the pinnacle of astronomical knowledge during 5th-6th century. Later on, Indian astronomy concepts were significantly influenced Islamic astronomy, Chinese astronomy, European astronomy, and others. Other astronomers of the classical era who further elaborated on Aryabhata's work include; Brahmagupta, Varahamihira, and Lalla. An identifiable native Indian astronomical tradition remained active throughout the medieval period and during 16th or 17th century, especially within the Kerala school of astronomy and mathematics.

Vedic Mathematics, another system of mental mathematics and heuristics for increased calculative and cognitive abilities, was also developed in India

1
[Signatures]

उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला

- 88 -


6

2

Handwritten:

Teene

- Received
From Shale
Parker


 उप-मुख्यमंत्री (अ.प्र.)
 जिला मुख्यालय
 जिला -

- x. To bring out Newsletter/Journal of expository nature on Indian mathematics.
- xi. And to implement all other initiative and decisions taken in Advisory Board in its meetings from time to time.

4. The Advisory Board

- i. Vice-Chancellor, H. P. University, Shimla: Chairman
- ii. Chairperson, Department of Mathematics and Statistics, H. P. University, Shimla: Member
- iii. All Professors of the Department: Members
- iv. Two Nominees of the Hon'ble Vice-Chancellor: Members
- v. Director, Centre for Indian Mathematics: Convener

The term of Advisory Board will be of three years. The Director of Centre will run all the programs/courses of the centre under the guidance of the Advisory Board, and will look after the day to day functioning of the Centre.

5. Board of Studies of the Centre

The Board of Studies (BoS) of the Centre to start Diploma/Certificate courses will be the same as that of Mathematics, Department of Mathematics and Statistics (PG), with Director of the Centre as an additional member in the existing BoS.

6. Infrastructure Needed

- i. Director's office room one
 - ii. Office room one
 - iii. Faculty/Staff/Research persons' room three
 - iv. Visitors' room one
 - v. Research Scholars room one
 - vi. Seminar Hall with 50 persons seating capacity one
 - vii. A room for hosting library to be equipped with the books and journals related to Indian Mathematicians one
 - viii. Computers and printers 5 each
- *The Department of Mathematics & Statistics already has acute shortage of accommodation and therefore will not be able to provide the above listed accommodation from Sr No (i) to (iii) in the present set up of the Department.

7. Administrative, Research Staff/Secretarial Staff/Research Scholars

[Handwritten signatures and initials are present below the section header, including names like Bhana, K. reena, and others.]

[Faint handwritten text and a circular stamp are visible in the bottom right corner.]

- i. **Director (one):** The Director shall be the administrative head and overall incharge of the Centre. However, Director will take all decisions jointly in consultation with the Chairperson and all the communications of the Centre for Indian Mathematics (CIM) to the Vice-Chancellor will be routed through Chairperson, Department of Mathematics & Statistics. But, the policy decisions will have to be approved in the meeting of the Advisory Board.
- ii. **Assistant Professors** two
- iii. **Staff:**
Office assistant: one
Multi-tasking staff/ Peon: one
- iv. **Research Scholars:** two (at least).

8. Selection Procedure/honorarium and tenure

- i. **Director:** Director will be appointed/nominated by the Vice-Chancellor as per the procedure lay down by the EC and applicable to Chairs established/functioning in the University from time to time. In addition to this, the Director should be/ should have been: A Professor of Mathematics with at least 5 years of teaching and research experience.

The other terms and conditions/ honorarium/salary etc. shall be the same as applicable for the post of Director/Head of the Chairs established in the University from time to time.

- ii. **Assistant Professor:** To start the post graduate Diploma in Ancient Indian Mathematics and Certificate Course in Vedic Mathematics, the centre will require two regular faculty members, that is, Assistant Professors of Mathematics.

- (a) The essential qualifications for the selection of these faculty members will be as per HPU/ UGC Norms /Regulations.
- (b) A Diploma in Vedic Mathematics will be desirable qualification for these posts.

iii. **Research Scholars:**

- (a) Research Scholars of the Department pursuing Ph. D. degree may be associated with the Centre for its all activities.
- (b) Any student may be enrolled for Ph. D. with Centre for Indian Mathematics with the approval of Standing Committee and other related committees of the Department of Mathematics and Statistics.

~~Account~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~Revenue~~ ~~and~~ ~~Statistics.~~
~~Revenue~~ ~~and~~ ~~Statistics.~~

ANNEXURE-1

CHAPTER	SECTION	EXISTING PROVISION First Ordinance, H.P. University, Volume-1	PROPOSED PROVISION UGC Regulations, 2020
X	10.26	<p>Except for the course in Basic Mathematics, 20% marks in each course shall be assigned to internal assessment, which shall be based on periodical tests, written assignments, case discussions, quizzes, seminar papers, etc. The Chairman of the Department shall forward these marks to the Controller of Examinations at least two weeks before the commencement of the semester examination, and shall preserve the record, on the basis of which internal assessment awards have been prepared, for six months after the date of declaration of the results, for inspection by the University, if so required.</p> <p>Further, the revised marks scheme as prevailing through Conventional mode in MBA Programme is 60:40 as notified vide Notification No. 7-1/2019-HPU(Acad) dated 17.01.2020 and 03.02.2020.</p>	<p>Provided also that the weight age for different components of assessments for both Open and Distance Learning mode and Online mode shall be as under:-</p> <p>(i) Continuous or formative assessment (in semester): Maximum 30 percent.</p> <p>(ii) Summative assessment (end semester examination or term end examination): Minimum 70 percent.</p> <p>The Higher Educational Institution shall notify all assessment tools to be used for formative and summative assessments.</p> <p>As per AICTE Model Curriculum for Management Program (MBA) January, 2018, the Programme Structure and Credits shall be 102 credits.</p>

उप-कुलपति (सैमजिक)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
शिमला-171005



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

RAJIV GANDHI NATIONAL FELLOWSHIP (RGNF) FOR
SCHEDULED CASTE/SCHEDULED TRIBE CANDIDATES

INTRODUCTION

The Rajiv Gandhi National Fellowship (RGNF) Scheme for Scheduled Caste and Scheduled Tribes is formulated and funded by Ministry of Social Justice & Empowerment and Ministry of Tribal Affairs. The scheme is open to candidates who belong to Scheduled Caste & Scheduled Tribe and wish to pursue higher studies such as regular and full time M.Phil. and Ph.D degrees in Sciences, Humanities, Social Sciences and Engineering & Technology. There are 2000 slots for Scheduled Caste and 667 slots for Scheduled Tribe candidates every year for all the subjects.

OBJECTIVE

The scheme has been initiated keeping in view the social background of the candidates for the deprived section of the society and to provide them opportunity to undertake advanced studies and research. The objective of this award is to provide fellowships in the form of financial assistance to unemployed students belonging to SC/ST to pursue higher studies leading to M.Phil and Ph.D degrees (full-time) in Sciences, Humanities and Social Sciences and Engineering & Technology, in Indian Universities/Institutions/ Colleges approved under Section 2(f) and 12(B) of the UGC Act, and in Non-Universities/Institutions.

TARGET GROUP/ELIGIBILITY

TARGET GROUP: Unemployed SC/ST Candidates who have passed the Post Graduate examination in concerned subject and who desire to pursue full-time research without JRF of UGC-NET or UGC-CSIR NET.

ELIGIBILITY: The candidate should belong to SC/ST and should have passed the Post Graduate examination. The selection will be made on the basis of merit of the candidates. The candidate must get himself/herself registered for M.Phil./Ph.D at the first available opportunity but not later than within a period of two years from the receipt of award letter. This period is not extendable. However, the actual payment of fellowship will be made with effect from the date of joining only.

Handwritten signature and date:
4.6.16
Dr. [Signature]

-94-

NATURE OF ASSISTANCE AVAILABLE UNDER THE SCHEME:

The tenure of fellowship is initially for two years under the RGNEF Scheme. Before expiry of this period, the work of the Fellow will be evaluated by a Committee of three members comprising of Head of the Department, Supervisor and one outside subject expert to be constituted by the concerned Department of the /University/Institution/College. If the research work is found satisfactory, his/her tenure will be extended further for a period of three years under the enhanced emoluments of the Rajiv Gandhi National Senior Research Fellowship (RGNSRF). The recommendation of the Committee shall be submitted to the UGC for upgradation to the level of RGNSRF (Annexure-VIII). The work done and the time spent on scholarships or fellowships of any agency other than the UGC will not be taken into account while considering the proposals for enhancement in the value of fellowship. The fellowship may be withdrawn if the work is not considered satisfactory or the candidate fails in any of the examinations related to Ph.D.

In case the work for the first two years is not found satisfactory, an additional year will be given to him/her for improvement. However, during this period he/she will be designated as Rajiv Gandhi National Junior Research Fellow. In such cases work will be evaluated again before third year of the tenure, and if improvement is found, the Fellow will get two more years under the RGNSRF. Thus, the total period of fellowship (RGNJRF and RGNSRF) is for five years, with no further provision of extension.

The fellow doing M.Phil will be paid fellowship amount upto the period of 02 years or the date of dissertation whichever is earlier. The fellow doing Ph.D will be paid fellowship amount upto 5 years or the date of viva whichever is earlier.

The payment of fellowship for the gap period from M.Phil to Ph.D may be made and shall be counted in the total tenure of the fellowship i.e. for five years if the candidates are actually working in the university during the gap period. However the total period of the fellowship shall remain five years. The gap period for the registration in Ph.D after completion of M.Phil is one year.

THE CANDIDATE WOULD BE ELIGIBLE FOR FOLLOWING FINANCIAL ASSISTANCE.

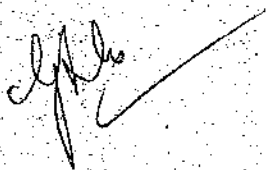
The amount of fellowship/contingency etc. must be paid to the fellow by the University/Institute/College in the first week of every month in respect of selected candidates prior to 2011-12 thereafter e-payment is optional towards payment of grant in respect of selected candidates 2011-12 onwards

Fellowship in Science, Humanities and Social Science	@ Rs. 16000/- p.m. for initial two years @ Rs. 18000/- p.m. for remaining tenure	JRF
Contingency A	@ Rs. 10000/- p.a. for initial two years @ Rs. 20500/- p.a. for remaining tenure	Humanities & Social Sciences
Contingency B	@ Rs. 12000/- p.a. for initial two years @ Rs. 25000/- p.a. for remaining tenure	Science, Engg. & Technology
Departmental Assistance	@ Rs. 3000/- p.a. per student to the host institution for providing infrastructure	All Subject
Escorts/Reader assistance	@ Rs. 2000/- p.m. in cases of physically handicapped & blind candidates	All Subject
HRA	As per rules of the University/Institutions	All Subject

HOUSE RENT ALLOWANCE : Suitable single-seated hostel accommodation may be provided to RGNRF candidate in the University/Institution/College. In case of non-availability, HRA as per rules of the university/ institution/ college will be paid to the Fellow subject to the submission of an HRA certificate through the Registrar/Director/Principal, Rajiv Gandhi National Junior Research Fellow provided with accommodation in a hostel recognized/maintained by the institutions may be reimbursed the hostel fee, excluding mess, electricity, water charges, etc. A certificate to this effect is to be furnished through the Registrar/Principal (Annexure II). If the fellow makes his/her own arrangements of accommodation, he/she may be entitled to draw HRA as per categorization of the cities by the Government of India. The fellow will submit a certificate for the purpose to the UGC for claiming HRA through the concerned University/Institution/College.

Medical: No separate/fixed medical assistance is provided. However, the Fellow may avail of the medical facilities available in the University/Institution/College.

Leave: The candidates are entitled for a maximum period of 30 days of leave in a year in addition to public holidays. They are not entitled to any other vacations. Women candidates are



Statement of exp-
University/Instity
months a Co
branch of p
PRO

...at full rates of fellowship once during the tenure...

In special cases Rajiv Gandhi National Junior Research Fellow may be allowed leave without fellowship by the Commission upto one academic year during the entire tenure of the award for accepting teaching assignments on a temporary basis, provided the assignment is in the same city/town. In other cases, leave without fellowship will be restricted to a period not exceeding three months during the tenure of the award on the recommendations of the supervisor and the institution. The period of leave without fellowship will be counted towards the total tenure of the award. RGNJRF/RGNSRFs are advised to apply for leave through University/Institution/ Colleges well in advance for the approval of the Commission.

PROCEDURE FOR APPLYING FOR THE SCHEME

Applications are invited through online mode once in a year through advertisement in leading newspapers and Employment News. The same is also uploaded in the UGC Website www.ugc.ac.in. The selection is made on the basis of merit and as per the procedure of the Commission.

PROCEDURE FOR APPROVAL OF THE UGC

Applications received will be scrutinized, and short listed by the Commission. The decision of the Commission will be final and binding. The Commission reserves the right to withhold the award without assigning any reason. On completion of the above procedure, the Joining Report of the candidate, duly signed by the supervisor/head of institution, is to be sent to the UGC through the Registrar/Director/Principal. On receipt of the Joining Report and other required documents (Annexure III), the admissible grant for the first year will be released to the concerned university which will be informed to release the grant from the funds already sanctioned by the Commission for this purpose.

PROCEDURE FOR RELEASE OF GRANT

On receipt of the above mentioned letter, the institutions/Bank may pay the fellowship amount to the fellow. The amount received from the grants paid by the Commission for the purpose in the first year will be used for the purpose of subsequent installments of the grant, that is, for the purchase of books, travel, etc., a Utilisation Certificate along with a

[Handwritten signature]

-97-

statement of expenditure incurred may be sent to the Commission by the concerned University/Institution/College (Annexures IV, V, VI and VII). At the end of every three months a Continuation Certificate in the prescribed form (Annexure-I) to the designated branch of the Bank

PROCEDURE FOR MONITORING THE PROGRESS OF THE SCHEME

1. The fellow will undertake full-time research work under the approved guide in a subject selected by him and approved by the university/selection committee.
2. The fellow shall present to the university, through his/her supervisor, half-yearly progress reports ending the month of June and December, and the University/Institution/College will maintain a record of progress by obtaining the same.
3. If a fellow wishes to relinquish the fellowship during the tenure, it should be done with the prior approval of the University/Institution/College and the Commission. The fellow should also obtain prior permission of the University/Institution/College and Commission for appearing in any examination conducted by any University/Institution/College or public body.
4. The fellow shall not accept or hold any appointment, paid or otherwise, or receive emoluments, salary, stipend, etc. from any other source during the tenure of the award. The fellow, with the consent of the guide/head of department, may assist the University/Institution/College in its academic work, including tutorials, evaluation of test papers, laboratory demonstration work, seminar symposia, etc., provided such work is not likely to hamper the research programme on hand.
5. The fellowship may be terminated at any time without assigning any reasons and the Commission's decision in this regard shall be final and binding. No extension is permissible beyond the total period of five years and Awardee ceases to be a RGNJRF/RGNSRF immediately after expiry of the tenure.

OTHER CONDITIONS:

The University/ Institution/College shall admit the fellows under RGNE scheme for research leading to M.Phil. or Ph.D. irrespective of the stipulated number of research students assigned to the Supervisor or the Department in the concerned subjects.

TRANSFER OF FELLOWSHIP:

[Signature]

The Fellow will be permitted to transfer the fellowship from University/Institution/College to another University/Institution/College under special circumstances with prior approval of the UGC on the basis of "No Objection Certificate" from both Universities/ Institution/College. However, the Fellow shall be relieved by the previous University/Institution/College only after his accounts are settled and unspent balance if any, refunded to the UGC.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. P. Singh', is written on the left side of the page.

-99-

**CENTRAL SECTOR SCHEME OF 'NATIONAL FELLOWSHIP'
FOR
PROVIDING FELLOWSHIP TO SCHEDULED CASTE
STUDENTS TO PURSUE M. Phil. AND Ph. D.**

GUIDELINES GOVERNING THE AWARD OF FELLOWSHIP
(Effective from 01.04.2020).



GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

RGNI / NISC / NIST

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
Department of Social Justice & Empowerment

CONTENTS

Sl.No.	Topic	PageNo.
I.	Background	2
II.	Objective	2
III.	Scope of the Scheme	2
IV.	Implementing Agency	3
V.	Eligibility	3
VI.	Number of Fellowships	5
VII.	Duration of Fellowships	6
VIII.	Rate of Fellowships	6
IX.	Procedure for Applying for JRF	8
X.	Aadhaar based ID	9
XI.	Evaluation and Monitoring of the Scheme.	9

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
Department of Social Justice & Empowerment

**CENTRAL SECTOR SCHEME OF NATIONAL FELLOWSHIP FOR PROVIDING
FELLOWSHIP TO SCHEDULED CASTE STUDENTS
TO PURSUE M.Phil. & Ph. D**

Effective from 01.04.2020

I. Background

National Fellowship scheme for Scheduled Caste Students, is a Central Sector Scheme introduced during the financial year 2005-06 to provide opportunities to Scheduled Castes students for pursuing higher education leading to M.Phil/Ph.D degrees in Sciences, Humanities and Social Science streams.

II. Objectives:

The objective of the scheme is to provide fellowships in the form of financial assistance to students belonging to SC category to pursue higher studies leading to M.Phil/Ph.D in Science, Humanities, Social Science, in Indian Universities/Institutions/Colleges recognized by University Grants Commission (UGC).

III. Scope of the scheme

The scheme provides for new 2000 Fellowships (1500 Junior Research Fellows for Humanities/ Social Sciences and 500 Junior Research Fellows for Science stream) per year to such Scheduled Caste students to undertake advanced studies and research leading to M.Phil/ Ph.D Degrees, who have qualified in the following tests:

- i) National Eligibility Test- Junior Research Fellowship (NET-JRF) of UGC or
- ii) UGC-Council of Scientific and Industrial Research (UGC-CSIR) NET-JRF joint test.)

These 2000 slots are over and above the number of SC students selected under the normal reservation policy of the Government for

UGC Fellowships. The scheme is implemented on the pattern of the scheme of UGC Fellowships being awarded to research students pursuing M. Phil/Ph.D.

The scheme covers all Universities/Institutions recognized by the University Grants Commission (UGC) as under :

- a. Central/State Universities (including constituent and affiliated institutions) included under Section 2(f) of UGC Act, 1956 and having valid accreditation from NAAC.
- b. Deemed Universities under Section 3 of UGC Act i.e. Institution for higher education notified by Central Government to be deemed University, in consultation with UGC and having and having valid accreditation from NAAC.
- c. Institution fully funded by State/ Central Government and empowered to award degrees.
- d. Institutions of National Importance as notified by Ministry of Human Resource Development.

(mhrd.gov.in/institutions-national-importance)

IV. **Implementing agency**

UGC is the nodal agency for implementing the scheme and is responsible for laying down procedures/ guidelines for implementing the scheme, including selection of beneficiaries and disbursement of fellowships to selected candidates.

V. **Eligibility**

- (i) Fellowships shall be awarded to candidates for pursuing regular and full time M.Phil./Ph.D. courses in Universities/Research Institutions recognized by UGC.
- (ii) Scheduled Castes candidates who have already secured admission and qualify NET examination will be given preference. Such candidates will be required to join the fellowship within 3 months of the issue of the JRF award letter.

- (iii) In case sufficient candidates, who have already secured admission are not available, candidates who have not yet secured admission will also be selected in the order of merit in the NET examination.

Such candidates will be eligible to receive fellowship under National Fellowship for SC scheme, subject to admission for M.Phil./Ph.D in Universities/IITs/ Institutions. The validity period of the offer is three years w.e.f. the date of issue of the JRF Award letter under the Scheme.

A scholar is eligible to receive only one fellowship at a time. The scholar is required to declare that he/she will not accept/receive any other monetary benefit/scholarship/fellowship from any other source. In other words, a scholar who is awarded fellowship under this scheme shall not accept any other fellowship/scholarship or hold any appointment, paid or otherwise, or receive any emoluments, salary, stipend etc. from any other source during the tenure of the award (except in case of 'academic leave' of one year). In case, a scholar is already in receipt of any scholarship/fellowship, he/she will have to relinquish either the previous scholarship/fellowship/any other monetary benefit or to forgo the selection under this scheme.

A scholar who does not complete his/her research work during the period of fellowship shall not be eligible to apply again under this scheme. Similarly, a scholar who has completely or partially availed any of these fellowship for Ph.D. earlier shall also not be eligible for fellowship under this schemes.

- (iv) After two years of joining JRF, if the progress in the research work of the awardee is found satisfactory, his/her tenure will be extended for a further period of three years as Senior Research Fellowship (SRF) as per UGC Fellowship Guidelines issued from time to time in case of students enrolled for Ph.D or M.Phil. + Ph.D.
- (v) With regard to combined course of M.Phil and Ph.D., Fellowship will be provided initially for 02 years for M.Phil and after upgradation to Ph.D course, for another 03 years.

- (vi) The fellowship shall be paid from date of issue of JRF award letter under the Scheme for National Fellowship or date of joining of the M.Phil./Ph.D., whichever is later.
- (vii) In case of integrated Ph.D. or M.Phil. to Ph.D., the maximum tenure is 5 years including M.Phil. period of fellowship. For doing M.Phil., fellowship shall be granted for two years or upto the date of submission of M.Phil. dissertation, whichever is earlier.
- (viii) The maximum allowed gap period for continuation from M.Phil. to Ph.D. under this scheme shall be 2 years (from the date of declaration of result of M.Phil to date of admission to Ph.D.). However, the total tenure of fellowship shall remain five years excluding the gap period. No fellowship shall be paid during the gap period.
- (ix) The fellowship shall be granted up to the date of submission of Ph.D. thesis or five years of tenure, whichever is earlier. No extension is permissible beyond the total period of five years of fellowship.
- (x) Employees of any University/ College/ Educational Institution/ Central/ State/ UT Government shall be excluded from availing Fellowship, even if they are on Study Leave or Extra Ordinary Leave to pursue the M.Phil./Ph.D. course.

VI. Number of Fellowships with effect from 2018-19:

- (i) The total number of fellowships to be awarded to the Scheduled Castes students under the scheme is 2000 every year. Out of the 2000 slots available under National Fellowship scheme for SC students 1500 will be allocated for National Eligibility Test- Junior Research Fellowship (NET-JRF) of UGC and remaining 500 for science category students through UGC-Council of Scientific and Industrial Research (UGC-CSIR) NET-JRF joint test (for Science streams).
- (ii) If, in an academic year, the allocated slots (i.e 1500 for UGC-NET-JRF and 500 for UGC-CSIRNET-JRF) remain substantially unfilled

(25% or more); the slot allocation may be reviewed in the next academic year and revised accordingly.

- (iii) These 2000 slots will be over and above the SC students selected under the normal reservation policy of the Government.
- (iv) There will be an inclusive provision of reservation for Person with Disabilities (PwD) who belongs to SC category for the consideration as per norms of existing quota of PwD., as per "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016". The minimum degree of disability should be 40% in order to be eligible for any concessions/benefits.

VII. Duration of Fellowship

Name of the Course	Maximum duration	Admissibility of JRF and SRF	
		Junior Research Fellowship (JRF)	Senior Research Fellowship (SRF)
M. Phil	2 years	2 Years	Nil
Ph.D	5 years	2 years	Remaining 3 years
M.Phil + Ph.D	5 years	2 years	Remaining 3 years

VIII. Rate of fellowships and other facilities

(i) The rates of fellowship for JRF and SRF will be at par with the UGC Fellowships. **The rates applicable w.e.f. 01.01.2019 are as follows:**

S.No.	Head	Rates Applicable for	
		JRF	SRF
1.	Fellowship in all streams.	Rs. 31,000/- p.m. for initial two years	Rs. 35,000/- p.m. for remaining tenure
2.	Contingency for Humanities & Social Sciences	Rs.10,000/- p.a. for initial two years	Rs.20,500/- p.a. for remaining tenure
3.	Contingency for Sciences.	Rs. 12,000/- p.a. for initial two years	Rs. 25,000/- p.a. for remaining tenure.
4.	Escort/Reader assistance (All subjects)for physically and visually handicapped candidates	Rs.2, 000/- p.m.	Rs.2, 000/- p.m.

5.	House Rent Allowance (HRA)	@ 8%, 16% and 24% to those students who are not provided with hostel accommodation, in accordance with Govt. of India norms, as applicable in the city/ location where the research fellows are working.
----	----------------------------	--

Note regarding HRA:

- a. In case, hostel accommodation is provided to the scholars by their institutions, the scholar is eligible to draw only the hostel fee excluding mess, electricity, water charges etc.
- b. In case hostel accommodation offered by the university/institution is refused by the candidate, he/she will forfeit his/her claim of HRA.
- c. In case of non-availability of hostel accommodation, the scholar may be provided with single accommodation by the host institution. In such cases, the rent paid by the scholar on actual basis shall be reimbursed, subject to the ceiling of HRA as per Govt. of India norms.
- d. If the scholar makes his/her own arrangements of accommodation, he/she shall be entitled to draw HRA as per ceiling and categorization of cities by the Govt. of India.
- e. In case, the scholar wishes to draw HRA, he/she is required to claim HRA on monthly basis by submitting monthly confirmation Certificate in the prescribed format, to his/her institution.

(ii) Other facilities such as medical facilities, leave including maternity leave will be governed as per the guidelines of UGC in case of their fellowship programme.

IX. Procedure for Applying for the Scheme (JRF):

- (i) UGC is the nodal agency for implementing the National Fellowship scheme for SC students.
- (ii) The selection for the award of fellowship to students will be made on the basis of merit of each UGC-NET-JRF or UGC-CSIRNET-JRF examination.
- (iii) While the merit for award of fellowships under NFSC will be drawn up through the NET examination, preference will be given to such students who have already secured admission. However, in case sufficient such candidates are not available, candidates who have not secured admission will also be selected in the order of merit in the NET examination. A separate merit list will be drawn up for such candidates if required.
- (iv) Candidates who have already secured admission are required to join the fellowship within 3 months of issue of JRF award letter under the Scheme. The duration for joining the course will not be extended, candidature of such candidates, who do not join the fellowship within 3 months, shall be cancelled.
- (v) The qualified candidates, who have not secured admission at the time of application for Fellowship under the Scheme, are required to get admission for regular and full time M.Phil./Ph.D in a recognised research institution at the first available opportunity but no later than three years from the date of award of fellowship.
- (vi) Genuineness of the Scheduled Caste Certificate furnished by the awardee shall be verified by the concerned University/Institution before allowing the awardee to avail fellowship under the scheme.
- (vii) The decision of the UGC in regard to awarding the Fellowship shall be final and no appeal would lie against any decision by UGC in regard thereof.
- (viii) The results shall be published on UGC website. Award letters can be downloaded from UGC online application portal or as advertised by UGC.

X. Aadhar based I.D:

Payment of Fellowships and any other admissible allowance should be made to beneficiaries through their bank accounts. The Ministry of Social Justice vide notification number 428 dated Feb,16,2017 has notified Aadhaar as an identity document under Section 7 of Aadhaar Act 2016 for all Scholarship Schemes w.e.f. 16th February 2017. UGC henceforth will make provisions for capturing details of Aadhaar, Aadhaar EID and other alternative documents as provided for in the said notification on their respective Scholarship portals or otherwise for disbursement of fellowship directly in to the beneficiary's account.

XI. Evaluation and Monitoring

- (i) A dashboard to monitor progress, geographic spread, discipline wise students enrolled, sanctions, completion of courses, etc. shall be put in place by UGC on its portal to be accessed by Ministry of Social Justice & Empowerment via login credential.
- (ii) Implementation charges payable to UGC will be based on actual expenditure, subject to ceiling of 1% of the total fellowship disbursed by the UGC.
- (iii) A grievance redressal call centre shall be set up to take care of complaints of students availing of JRF/SRF.

National Fellowship for Higher Education of ST Students 2015-17

[Home](#)[About\(NFST\)](#)[Download](#)

INTRODUCTION

The Rajiv Gandhi National Fellowship (RGNF) scheme for Scheduled Tribes has been renamed as National Fellowship for Higher Education of ST Students and is formulated and funded by Ministry of Tribal Affairs. The scheme is open to candidates who belong to Scheduled Tribe and are pursuing higher studies such as regular and full time M.Phil and Ph.D degree in Sciences, Humanities, Social Sciences and Engineering & Technology. There are 750 slots for Scheduled Tribe candidates every year for all the subjects.

[Admin](#) | [UGC Home](#) | [Contact Us](#) | © 2020 University Grants Commission

209067

Total No of Hits Since September 23, 2015

110 -

National Fellowship for Scheduled Caste Students

[Home](#)

[About\(NFSC\)](#) ▼

[Download](#) ▼

INTRODUCTION

The National Fellowship (NF) Scheme for Scheduled Caste is formulated and funded by Ministry of Social Justice & Empowerment. The scheme is open to candidates who belong to Scheduled Caste and are pursuing higher studies such as regular and full time M.Phil. and Ph.D. degrees in Sciences, Humanities, Social Sciences and Engineering & Technology. There are 2000 slots for Scheduled Caste every year for all the subjects. 3% fellowships are reserved for Persons with Disabilities candidates belonging to SC categories as per provision laid down by the Government of India.

CARE : WE EXPECT HEAVY LOAD ON THE WEBSITE TOWARDS THE LAST DATE FOR APPLYING. PLEASE, THEREFORE, APPLY WELL BEFORE THE CLOSING DATE TO AVOID NETWORK CONGESTION / DISCONNECTION & INABILITY TO REGISTER YOUR APPLICATION.

[Admin](#) | [UGC Home](#) | [Contact Us](#) | © 2020 University Grants Commission

Total No. of Hits Since June 1, 2015

-11-

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NEW DELHI-110 002**

F.No. 82-44/2020 (SA-III)

Date: 29 September, 2021

NOTIFICATION

The Ministry of Social Justice and Empowerment had modified the selection procedure for the identification of candidates for award of **"National Fellowship for Scheduled Caste students" (NFSC)** for research leading to award of M.Phil/Ph.D. The revised guidelines were effective from 01.04.2020, i.e., for the selection year 2020-21 and onward. As per the revised selection procedure - *'The selection for the award of fellowship to students will be made on the basis of merit of each UGC-NET-JRF or CSIR-NET-JRF examinations and the candidates, who have already secured admission and qualify NET examination will be given preference.'* The guidelines are attached herewith.

Accordingly, National Testing Agency (NTA) vide its Public Notice dated 01.12.2020 had issued the list of candidates who were found eligible for award of NFSC on the basis of UGC-NET June 2020 Examination. The NTA issued an updated result on 19.03.2021 with some additional selections under NFSC - 2020-21 (June, 2020 cycle). A list containing details of additional selected candidates is attached.

It may be noted that e-Certificates of Eligibility for Assistant Professor have already been uploaded on <https://ugcnet.nta.nic.in>

The candidates, whose roll numbers are given in the list are eligible to receive fellowship for pursuing research leading to award of M.Phil/Ph.D as per the guidelines of scheme, terms & conditions contained in the Award letter and this Notification.

The candidates and the institutions where the identified candidates are pursuing their research or where a candidate seeks admission are required to adhere to the following:

1. The candidates, whose roll numbers are given in the attached list, may also check their result on UGC website at www.ugcnetonline.in. The candidates, who want to avail the fellowship for pursuing research leading to award of M.Phil/Ph.D may download their Award Letter from www.ugcnetonline.in.
2. The candidates and their institutions may note that the selections have been made on the basis of information given by the candidates, while applying for NET. Therefore, their selection is provisional. The eligibility of the candidate, for the fellowship, is required to be ensured by University/Institution at the time of admission to M.Phil/Ph.D. If the candidate is already admitted, the eligibility of candidate, for fellowship be ensured at the time of processing the claim for fellowship.

3. The fellowship will be payable from the date of issue of result of NFSC i.e. **30.11.2020** (in case, the candidate is already pursuing M.Phil/Ph.D) OR from the actual date of joining M.Phil/Ph.D, whichever is later. Therefore, if a candidate has already taken admission, for M.Phil./Ph.D through regular and full time mode, in any UGC recognised University/Institution and his/her roll number is given in the list, he/she should apply for fellowship **within three months** only.
4. The identified candidates who have not taken admission/registration are advised to get admission/registration for regular and full time M.Phil/Ph.D in a UGC recognised University/Institution at the first available opportunity but **not later than three years** from the date of issue of award letter.
5. For claiming the fellowship the candidates are advised to fill in the '**Verification Form cum Joining Report**' and submit it to the officials concerned of their institutions. The verification form shall be duly signed/countersigned by the scholar, the Guide, the Head of Department and the Registrar of University/Director of Institute. A proforma of the 'Verification Form cum Joining Report' is also **attached** below.
6. The fellowship amount shall be disbursed by UGC directly into the bank account of Awardee. The fellowship is payable for a maximum period of five years.
7. Apart from verifying the credentials of candidate, the university/institution is also required to strictly follow the following:
 - I. Read the guidelines of scheme and this notification thoroughly.
 - II. Verify and ensure that the candidate is eligible for receiving the fellowship under the scheme as per the guidelines and this notification.
 - III. Ensure the authenticity and correctness of claim of candidate that he/she belongs to a notified Scheduled Caste category.
 - IV. Verify/authenticate the required educational qualifications and marks obtained by him/her.
 - V. Ensure that all the documents required as per the guidelines and notification are completely and correctly filled by the scholar in the formats prescribed by UGC.
 - VI. Deposit all the documents submitted by the candidate and keep their record in its safe custody and upload the required information, on the scholarship payment portal for claiming the fellowship through DBT mode.

VII. Ensure that both the 'Verification Form cum Joining Report' and 'Certificate by the Institution' are strictly as per the format given hereunder, are completely filled, properly scanned and uploaded on the scholarship portal.

8. After satisfying itself of the genuineness of the claim and verification of all facts as given in the verification form cum joining report, the concerned institution shall link the candidate on the portal, give all the details and upload a legible and complete copy of scanned 'verification form cum joining report' (Annexure-I) along with the 'Certificate by the Institution' (Annexure-II) on the scholarship payment portal <https://scholarship.canarabank.in/>

9. Once the candidate starts receiving the fellowship, Institution shall ensure that all the claims for Fellowship, HRA and contingency are received regularly by them and the data is uploaded by them in a time bound manner on scholarship portal on monthly basis (before 15th of every month).

10. The data of scholar is required to be uploaded by a 'Maker' and approved by a 'Checker' who should be permanent officials of that university/institution & duly authorised by the Head of Institution to access the scholarship payment portal.

Important Note:

- I. *Strict action, as per law, shall be taken against the scholar for furnishing any type of wrong/misleading information in respect of his/her eligibility and other details for getting the fellowship and for furnishing wrong/misleading information during the tenure of research period. UGC reserves the right to take action/initiate proceedings against such scholars and for recovery of full amount of paid fellowship along with interest.*
- II. *The institution concerned and its officials shall be held responsible if any payment is made to an ineligible scholar on the basis of uploading of wrong/misleading information on the payment portal. Action shall be taken against the institution/officials including blacklisting of the institution and recovery of paid amount of fellowship with interest from the institution/officials concerned.*
- III. *Un-authorised access of the scholarship payment portal shall invite action under the relevant provisions of the Information Technology (IT) Act.*

-114-

Annexure-I

**University Grants Commission
New Delhi-110002**

National Fellowship for Scheduled Caste Students (NFSC) – 2020-21		PHOTOGRAPH OF CANDIDATE
VERIFICATION FORM CUM JOINING REPORT FOR AVAILING FELLOWSHIP UNDER THE SCHEME		
1	Name of Scholar/Candidate	
2	Date of Birth	
3	12 digit unique AADHAAR Number	
4	Whether belong to a notified Scheduled Caste (SC) category	
5	No. of UGC-NET e-Certificate for eligibility for Assistant Professor	
6	NFSC-2020-21 Award letter Number and UGC-Ref.No.	
7	Year of passing of Master's Degree or equivalent examination	
8	Percentage of Marks in Master's Degree or equivalent examination	
9	Pursuing research for M.Phil or Ph.D	
10	Date of Admission for M.Phil/Ph.D	
11	Whether registered for M.Phil/Ph.D	
12	If already registered, give date of registration	
13	Whether pursuing research through full time regular mode	
14	Whether engaged in any type of employment (part-time/ad-hoc/full time or any other)	
15	Name of University where admitted for M.Phil/Ph.D	
16	Name of Institution where pursuing research	
17	Name, designation and official address of SUPERVISOR. (Only a full time regular teacher of concerned university/institution can act as a supervisor)	
18	Whether received (earlier) or receiving any other fellowship/ scholarship/ monetary assistance from UCC or any other source for pursuing M.Phil/Ph.D. (If yes, give details)	
19	I hereby declare that each and every fact given above is true and correct. I also authorise UGC to recover any excess/wrong payment from me.	
20	Signature of candidate with date	

-45-

Annexure-II

**University Grants Commission
New Delhi-110002**

CERTIFICATE BY THE INSTITUTION

1. Certified that all the facts/information given in the VERIFICATION FORM CUM JOINING REPORT FOR AVAILING FELLOWSHIP UNDER THE SCHEME (**Annexure-I**) as given by the candidate Mr./Ms. _____ has been verified and is found to be true and correct. He/She is a full time and regular student of our institution.
2. We have read the 'Guidelines' of the scheme and the Notification.
3. Certified that the candidate belongs to Scheduled Caste category as notified by the Government of India.
3. He/She is eligible for receiving the fellowship under 'National Fellowship for Scheduled Caste students-2020-21'
6. As per our knowledge he/she has neither received nor receiving any other fellowship/scholarship/monetary assistance from UGC or any other source for pursuing either M.Phil or Ph.D. **OR** He/she was getting fellowship/scholarship under the scheme _____ for M.Phil/Ph.D, and the entire amount has been refunded by him/her.
7. We understand that UGC will disburse the amount of fellowship directly to the account of candidate on the basis of information and details of candidate being uploaded (**Annexure-I & II**) by our institution on the scholarship portal.
8. Certified that University/Institution is complying with UGC (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil/Ph.D Degree) Regulations, 2016 and its amendments issued from time to time.
8. AISHE code of our Univesity/Institution is _____

Signature of candidate:	Signature of Guide/ Supervisor
Date:	Date:
Name:	Seal:
	Name:
	Designation:

Signature of Head of Department:	Signature of Head of Institution:
Date:	Date:
Seal:	Seal:
Name:	Name:
Designation:	Designation:

Set No. 2

Total Pages (1 to 7) - 1/6 -

Annexure to on spot-Item No. 1

File No. 1-20/2018-HPU(UIT) NEW PROPOSALS
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No. 1: *3/12/2019*
Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

(Justification of Agenda Item:

The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vo-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vo-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vo-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:

[Signature]

DIRECTOR

Univ. Institute of Technology,

Himachal Pradesh University,

Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

(From pre page)

"Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

Point for Consideration:

The redistributions of Sanctioned Teaching Posts which need to be filled-up in accordance to above mentioned: (i) Director/Professor-01(37400-67000+10000 Grade pay), (ii) Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11(37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Branches namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) will be placed before Standing Committee of Academic Council for consideration and approval.

[Signature]
 Director
 University Institute of Technology
 Suranjan, Shri...

Set No. 16

Total pages (1 to 7) - 118 -

File No. 1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS-
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No. : Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

(Justification of Agenda Item):

The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:

[Signature]
DIRECTOR
University Institute of Technology,
Himachal Pradesh University,
Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

Approved as per
Annexure-I item
is further recommended
for EC

[Signature]
3/12/21

-119-

(From pre page)

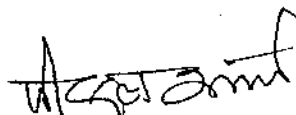
"Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

Point for Consideration:

The redistributions of Sanctioned Teaching Posts which need to be filled-up in accordance to above mentioned: (i) Director/Professor-01(37400-67000+10000 Grade pay), (ii) Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11(37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Branches namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) will be placed before Standing Committee of Academic Council for consideration and approval.


DIRECTOR
UIT
Hd
Bhawan, Shri, Shri

Set No. 7

File No. 1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS-
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No. : 1 Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

(Justification of Agenda Item:

The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled- attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:

[Signature]
DIRECTOR
University Institute of Technology,
Himachal Pradesh University
Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

Approved Item
regarding redistribution
of Sanctioned
Vacant posts & Recruitment
for EC
21/11/2021
Dear Faculty
Social Science

(From pre page)

"Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

Point for Consideration:

The redistributions of Sanctioned Teaching Posts which need to be filled-up in accordance to above mentioned: (i) Director/Professor-01(37400-67000+10000 Grade pay), (ii) Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11(37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Branches namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) will be placed before Standing Committee of Academic Council for consideration and approval.

[Signature]
DIRECTOR

Dr. ...

Hd.

Surintendent, Shimla

File No.1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No.

Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

(Justification of Agenda Item:

The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:

[Signature]
DIRECTOR

University Institute of Technology,
Himachal Pradesh University
Summer-Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

-123-

-2-

(From pre page)

"Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

Point for Consideration:

The redistributions of Sanctioned Teaching Posts which need to be filled-up in accordance to above mentioned: (i) Director/Professor-01(37400-67000+10000 Grade pay), (ii) Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11(37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant-Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Branches namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) will be placed before Standing Committee of Academic Council for consideration and approval.

[Signature]
 Director
 University Institute of Technology
 Haryana
 Sonapatna, Sonapatna

File No. 1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS-
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No. : 1 Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

(Justification of Agenda Item):

The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:

[Signature]
DIRECTOR
University Institute of Technology,
Himachal Pradesh University,
Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p...

Approved as
per annexure A
and further
recommended
by E.C.
J. D. Singh
3.12.21
Vice Chancellor
Nominer

(From pre page)

"Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

Point for Consideration:

The redistributions of Sanctioned Teaching Posts which need to be filled-up in accordance to above mentioned: (i) Director/Professor-01(37400-67000+10000 Grade pay), (ii) Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11(37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Branches namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) will be placed before Standing Committee of Academic Council for consideration and approval.

U. S. Singh
 Director
 U. S. Singh
 H. S. Singh
 Sumit Singh, Secretary

File No.1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS-
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No. : 1 Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

Justification of Agenda Item:

The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:

[Signature]
DIRECTOR
University Institute of Technology,
Himachal Pradesh University
Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

(From pre page)

"Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

Point for Consideration:

The redistributions of Sanctioned Teaching Posts which need to be filled-up in accordance to above mentioned: (i) Director/Professor-01 (37400-67000+10000 Grade pay), (ii) Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant-Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Branches namely, Information Technology (IT), Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities (ASH) will be placed before Standing Committee of Academic Council for consideration and approval.

[Signature]
 DIRECTOR
 UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
 HUDA, SURAT
 SURAT, GUJARAT

Set No. 6

File No.1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS-
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No. : I Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

Approved as per
annexure attached
and recommended for
EC.

3/12/2021

Justification of Agenda Item:

The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:

[Signature]
DIRECTOR
Un. Institute of Technology,
Himachal Pradesh University
Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

(From pre page)

"Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

Point for Consideration:

The redistributions of Sanctioned Teaching Posts which need to be filled-up in accordance to above mentioned: (i) Director/Professor-01(37400-67000+10000 Grade pay), (ii) Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11(37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Branches namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) will be placed before Standing Committee of Academic Council for consideration and approval.

[Signature]
 DIRECTOR
 UIT
 HOD
 Suwanee J. S. Shinde

Approved as per Annexure
and further recommended
for EC to consider

File No. 1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS-
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

32.6.2021
21.12.2021

Item No. : 1
Dean
Life Sciences

Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

(Justification of Agenda Item:

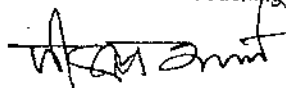
The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:


DIRECTOR
Univ. Institute of Technology,
Himachal Pradesh University
Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

File No.1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS-
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No. : 1 Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

Justification of Agenda Item:

The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:

[Signature]
DIRECTOR
University Institute of Technology,
Himachal Pradesh University
Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

Approved as per
annexure attached
and recommended for
E.C.

[Signature] 31/11/2021
(Dean Faculty
of Education)

(From pre page)

"Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

Point for Consideration:

The redistributions of Sanctioned Teaching Posts which need to be filled-up in accordance to above mentioned: (i) Director/Professor-01(37400-67000+10000 Grade pay), (ii) Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11(37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Branches namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) will be placed before Standing Committee of Academic Council for consideration and approval.

Accepted
 Director
 University Institute of Technology
 Haldwari, Uttarakhand

File No.1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS-
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No. : (Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

Justification of Agenda Item:

The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:

[Signature]
DIRECTOR
University Institute of Technology,
Himachal Pradesh University
Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

Approved as per
amended and recommended
E.C.

31/12/2021
(Dean Faculty
of Education)

File No.1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS-
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No. : | Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

Agenda item
approved as per
Annexure and
recommended
for E.C.
(Dean, ED+SS)
3/12/2021

(Justification of Agenda Item:

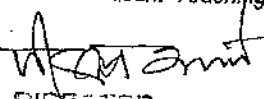
The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 26.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:


DIRECTOR
University Institute of Technology,
Himachal Pradesh University
Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

135-

(From pre page)

"Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

Point for Consideration:

The redistributions of Sanctioned Teaching Posts which need to be filled-up in accordance to above mentioned: (i) Director/Professor-01(37400-67000+10000 Grade pay), (ii) Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11(37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant-Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Branches namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) will be placed before Standing Committee of Academic Council for consideration and approval.

[Signature]

DIRECTOR

UNIVERSITY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
HARIDWAR
SOMERSET, SHRI...

IMG_20211203_110613.jpg

[illegible]

<https://doi.org/10.1016/j.jmb.2018.05.005>

CONFIDENTIAL

File No.1-20/2018-HPU(UIT)NEW-PROPOSALS-
OFFICE INCHARGE: DIRECTOR, UNIVERSITY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA.

Item No. : | Matter place before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistributions of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i): Director/Professor-01, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Departments namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH).

Justification of Agenda Item:

The Executive Council vide Resolution No.26 of its meeting held on 22nd January, 2019 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl) dated 22.08.2000 and 22.07.2004, Notification No.9-30/2002-HPU(Genl)Vol-I dated 22.03.2016 Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 23.02.2019 Sanctioned and Vacant Teaching Posts as attached in the Annexure-"A" for kind perusal please.

In response to the aforesaid notification Himachal Pradesh University has Advertised the Teaching Posts in University Institute of Technology (UIT) i.e. Professor = 05, Associate Professor = 08 and Assistant Professor = 51 Posts vide Advertisement No.17/2020 dated 30.12.2019, out of which Post of One Associate Professor and 22 Assistant Professors are filled-up attached at Annexure-"B" for kind perusal please.

It is pertinent to mentioned here that Executive Council vide Resolution No.18 of its meeting held on 30th March, 2021 has approved and notified vide Notification No.9-30/2000-HPU(Genl)Vol-II dated 22nd June, 2021 the creation of Six Departments in University Institute of Technology (UIT) namely Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) for smooth functioning of the University Institute of Technology (UIT), Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla-5.

Keeping in view the requirement of New Branches/Departments started in the University Institute of Technology (UIT), it is necessary to fill-up the vacant Teaching Posts in their respective Departments/Branches in the interest of the students and smooth functioning of the Institute in accordance.

In this context a Departmental Council (HoDs) meeting was held on 15th November, 2021 and has decided for filling-up of Sanctioned Vacant Teaching Posts in the redistribution form which is given below:

[Signature]
DIRECTOR

University Institute of Technology,
Himachal Pradesh University
Summer Hill, Shimla-5

Contd..2/p....

Agenda item
approved as per
measure and
further teleconfered
for E.C.
(Vice-Chancellor
Nominated)

(From pre page)

"Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

Point for Consideration:

The redistributions of Sanctioned Teaching Posts which need to be filled-up in accordance to above mentioned: (i) Director/Professor-01(37400-67000+10000 Grade pay), (ii) Professor-06 (37400-67000+10000 Grade pay), (iii) Associate Professor-11(37400-67000+9000 Grade pay) and (iv) Assistant Professor-28 (15600-39100+6000 Grade pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the Six Branches namely, Information Technology(IT), Computer Science Engineering(CSE), Electronics & Communications Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities(ASH) will be placed before Standing Committee of Academic Council for consideration and approval.

[Signature]
 Director
 University Institute of Technology
 Surinagar, Shimla

3:17 PM

Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
academicbranch31@gmail.com

Gmail - Item for standing committee of Academic Council (through Circulation)

Fri, Dec 3, 2021 at 2:57 PM

139-

Dr Arun Gupta
Dean, Dental Sciences



Address not found

Your message wasn't delivered to
gmchospitalchamba@gmail.com because the address
couldn't be found, or is unable to receive mail.

[LEARN MORE](#)

The response was:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking
the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at
<https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> h2sor1466814pfn.9 - gsmt

Final-Recipient: rfc822; gmchospitalchamba@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at

550 5.1.1 <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> h2sor1466814pfn.9 - gsmt

Last-Attempt-Date: Fri, 03 Dec 2021 01:27:50 -0800 (PST)

----- Forwarded message -----

From: Academic Branch <academicbranch31@gmail.com>

To: gmchospitalchamba@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 3 Dec 2021 14:58:56 +0530

Subject: Fwd: Item for standing committee of Academic Council (through Circulation)

----- Message truncated -----

Academic Branch <academicbranch31@gmail.com>
To: gmchchamba@gmail.com

Fri, Dec 3, 2021 at 3:01 PM

[Quoted text hidden]

----- Forwarded message -----

From: Academic Branch <academicbranch31@gmail.com>

To: gmchospitalchamba@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 3 Dec 2021 14:58:56 +0530

Subject: Fwd: Item for standing committee of Academic Council (through Circulation)

----- Message truncated -----

ashumoni gupta <guptaashumoni@gmail.com>

To: Academic Branch <academicbranch31@gmail.com>

Fri, Dec 3, 2021 at 3:46 AM

✓ approved as per annexure and further recommended for executive council

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=79458ade31&view=pt&search=all&permthid=thrproject627&messageid=0.1>

1/1

-140-

Himachal Pradesh University
(NAAC Accredited 'A' Grade University)
University Institute of Technology
Summer Hills, Shimla-5

File No.1-20/2018-HPU(UIT) New Proposals-

Dated: 15.11.2021

Minutes of the Meeting of Department Council

A meeting of Department Council (HoD's) of the UIT under the Directorship of Prof. P. L. Sharma was held in the Director's Room on 15th November, 2021 at 04:00 PM.

The following members were present:

- | | | |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Prof. P. L. Sharma, | Director |
| 2. | Dr. Sumesh Sood, | Co-Ordinator |
| 3. | Dr. Ramesh Chand Thakur | Co-Ordinator |
| 4. | Dr. Shyam Chand, | Associate Professor |
| 5. | Dr.(Mrs) Neeru Sharma, | Associate Professor |
| 6. | Dr. Balvir Singh Thakur, | Assistant Professor |
| 7. | Dr. Akshay Bhardwaj, | Assistant Professor |
| 8. | Dr. Sanjay Sharma, | Assistant Professor |
| 9. | Dr. Mahesh Sharma, | Assistant Professor |

The following decisions were taken:

Agenda Item: To fill-up the vacant posts of Teaching Staff which were not filled in response to Advertisement No.Rectt.17/2019 dated 30.12.2019 of University Institute of Technology (UIT).

Decision: As per the need of the different Departments of the University Institute of Technology (UIT), the Committee has decided that the Sanctioned Vacant Posts may be re-distributed as per following criteria for the smooth functioning of the UIT. The Departments/Branches-wise filled-up and Vacant Teaching Posts details are given below:

(a) Sanctioned Teaching Posts Advertised vide No.17/2019 dated 30.12.2019

Sr. No	Name of Post & Pay Scale	Sanctioned Posts	Advertisement No. 17/2019	Filled-up	Vacant
1.	Director/Professor 37400-67000+10000 AGP	01	-	-	01
2.	Professor 37400-67000+10000 AGP	06	05	-	06
3.	Associate Professor 37400-67000+9000 AGP	12	08	01	11
4.	Assistant Professor 15600-39100+6000 AGP	56	51	28	28

Contd..p.2/...

14/1-

-2-

(b) Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Vacant Teaching Post upto October, 2021			Remarks
		Professor	Associate Professor	Assistant Professor	
1.	Director/Professor	01	-	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	03	-
2.	Electrical Engineering (EE)	01	02	07	-
3.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	05	-
4.	Information Technology(IT)/ Computer Sciences Engineering(CSE)	02	04	13	-
	(a) Maths/Physics	01	-	-	-
	(b) Physics	-	01	-	-
	(c) Maths	-	01	-	-
	Total	07	11	28	-

(c) Required redistribution of Vacant Sanctioned Teaching Posts

Sr. No.	Name of Deptt./Branches	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1.	Director/Professor	01	-	-
2.	Civil Engineering (CE)	01	02	01
3.	Electrical Engineering (EE)	01	02	04
4.	Electronics & Communication Engineering (ECE)	01	01	-
5.	Computer Sciences Engineering (CSE)	01	02	10
6.	Information Technology (IT)	01	02	08
7.	Applied Science & Humanities (ASH) Maths/ Physics			
	(a) Physics/Maths	01	-	-
	(b) Physics	-	01	-
	(c) Maths	-	01	02
	(d) Mechanical	-	-	01
	(e) Physical Education	-	-	01
	(f) Economics	-	-	01
	Total	07	11	28

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

Mahesh Sharma Sanjay Sharma Akshay Bhardwaj Balvir Singh Thakur
(Mahesh Sharma) (Sanjay Sharma) (Akshay Bhardwaj) (Balvir Singh Thakur)

Neeraj Sharma Shyam Chand Ramesh Chand Thakur Sumesh Sood
(Neeraj Sharma) (Shyam Chand) (Ramesh Chand Thakur) (Sumesh Sood)
Prof. P. L. Sharma
(Prof. P. L. Sharma)

742-NA
HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY
CENTRAL ADMINISTRATION SECTION
Dated Shimla-5, the 22nd August, 2000

No. HPU/2000-HPU(Genl) Dated Shimla-5, the 22nd August, 2000
NOTIFICATION

The Executive Council vide Resolution No. 7 (Final) of its meeting held on 27.6.2000, has been pleased to approve the creation of the following teaching and non-teaching posts in the University Institute of Information and Technology, for starting of B.T./M.T. course, with immediate effect.

Sr. No.	Name of the post w. Salary	No. of posts
1.	Professor (Rs. 16400-22600) UGC	One
2.	Reader (Rs. 12000-18300) UGC	One
3.	Assistant (Rs. 8000-13500) UGC	Three
4.	System Administrator or Programmer (Rs. 8000-13500) UGC	One
5.	Superintendent Grade-II (Rs. 6400-10640) (State)	One
6.	Steno-Typist (Computer Literate) (Rs. 3330-5200) (State)	One
7.	Data Entry Operator cum Clerk (Computer Literate) (Rs. 3120-5160) (State)	One
8.	Peon (Rs. 2520-4040) with initial start of Rs. 2620/- (State)	One

The expenditure on the salary of these posts will be met out of the fees received in the institute.

(Signature)
(DHIRUV VASHEST)
REGISTRAR

- Enclst. No. Even. Dated Shimla-5, the 22nd August, 2000
- Copy forwarded for information and necessary action to:-
1. The Dean of Studies, HPU, Shimla-5.
 2. The Coordinator, UNIT, HPU, Shimla-5.
 3. All the Chairmen/Chairpersons of teaching Depts., HPU.
 4. The Director (SDBOL)/HPU Regional Centre, Dharamsala.
 5. The Finance Officer/Joint Controller, LAD, HPU, Shimla-5.
 6. The Registrar (Acad.)/HPU with ref. to Notification No. 7/2000-HPU (Acad.) dated 13th July, 2000.
 7. The Principal, HPU Evening College, Shimla-5.
 8. The Registrar (Adm.)/HPU with ref. to Notification No. 1/2000-HPU (Adm.) dated 13th July, 2000.
 9. The Registrar (PS to VC/PVC)/(PS to Registrar/PA to D.R. (Adm.))
 10. Supdt. (Meeting)/(Committee)/(Regulations)/(Revision)/(Misc. (Union)) S.A. Section.
 11. File No. 9-2/80-HPU (Genl)/No. 9-6/80-HPU (Genl)/No. 16-9/80-HPU (Genl)
 12. Guard file.

May allow to keep it on record please.

(Signature)
REGISTRAR.

(Signature)
12/8/00
12/8

-143-

Himachal Pradesh University
General Administration Section

No.9-30/2000-HPU(Genl.)

Dated: Shimla-5, the 26.7.2004

NOTIFICATION

The Executive Council, vide Resolution No.16(14), of its meeting, held on 27-3-2004 has approved the creation of following Teaching & Non-Teaching posts on contractual basis in the University Institute of Information Technology (UIIT), as per educational qualifications and other terms/conditions of contractual appointments laid down in the relevant annexure of the proposal:-

A. TEACHING POSTS(S)

<u>Name of Post</u>	<u>Number of Position</u>	<u>Remarks</u>
1. Director/Professor (Rs.16400-22400) (UGC)	One	Sec append ed below note also.*
2. Assistant Professor (Rs.12000-18300) (UGC) (as per AICTE Norms)	Three	-do-
3. Lecturer (Rs.8000-13500)	Ten	a) Information Tech./Computer Sciences & Engineering -5 b) Electronics & Communication -3 c) Applied Science i) Physics-1 ii) Mathematics-1
4. System Analyst (Rs.12000-18300)	One	Computer Laboratory. -do-
X5. System Administration Programmer (Rs. 8000-13500)	One	Computer Laboratory -do-
X6. Laboratory Attendant (Rs. 3120-5160)	Five	i) Computer Laboratory ii) Physics' basic Electrical Engrg Laboratory iii) Electronics Laboratory iv) Computer Network Lab. v) Engineering Drawing Laboratory.
7. Programmer (Rs. 8000-13500)	One	Computer Network Lab -do-
8. Lab Technician (Rs. 5000-8100)	One	Computer Network Lab. -do-
9. Draughtsman (Rs. 5800-9300)	One	Engg Drawing Lab -do-
10. Semi-Professional Asstt (Rs. 3000-8100)	One	Library -do-
11. Library Attendant (Rs.3120-5160)	One	Library -do-

24/7/04
 O.I.T.A.
 28/8/04

Contd. 2/

144-
1. /
2.
-2-
3.
B. NON-TEACHING POST(S)

1. Section Officer
(Rs. 7220-11660) One ✓
2. Clerk Cum Data Entry Opr.
(Rs. 3120-5160) One ✓
3. Store Keeper
(Rs. 3120-5160) One ✓
4. Store Attendant
(Rs. 2520-4140) One ✓

See appended below
note also

-do-

-do-

-do-

*Note:-

The appointment will be offered on contract basis initially for a period of one year on a salary of initial basic pay of the scale plus D.A. as frozen at the time of appointment. However, the expenditure on the salary of these posts will be met out of the fee/funds received in the Institution (TNT)

Enclt. No. Even.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

Registrar

Dated:- 26.7.2004

1. The Dean of Studies/Dean Students' Welfare/Dean, CDC, HPU.
2. The Director, UIT, HPU.
3. The Director, ICDBOL/BBA/IMS/Regional Centre, Dharamshala/ASC, HPU.
4. The Finance Officer/Joint Controller, LAD, HPU.
5. All the Chairpersons of teaching Depts. HPU.
6. The Dy Registrar (Asst. & Finance) Academic, HPU.
7. The Asst Registrar, Teaching, HPU.
8. The Principal, HTUCBS, Shimla-I.
9. The Section Officer, Recru., HPU.
10. The SPS to VC/PS to Registrar/PA (Admin) HPU.
11. The Supdt. Meetings, Regulations, Committees, Revisions, Unions, Telephones.
12. Guard file.

Registrar

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

-145-

संख्या 9-30/2002- हि.प्र.वि.वि.(सा0) खण्ड-1

दिनांक

22 MAR 2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की अनुशंसा अनुसार कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनांक 27-01-2016 की मद्द संख्या 24(3) के अनुसार विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में स्वयं वित्त पोषित निधि से शिक्षकों के निम्नलिखित पद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतनमान में सृजन कर भरने की अनुमति प्रदान की:-

Sr.No.	Designation	IT&CSE(Branches)	No. of Post(s)	Pay Scale	Remarks
1.	Professor	1(IT)&1(CSE)	02	37400- 67000+10000	To be filled on regular pay scale
2.	Associate Professor	1(IT)&1(CSE)	02	37400- 67000+9000	To be filled on regular pay scale
3.	Assistant Professor	4(IT)&4(CSE)	08	15600-39100+6000	On contract
4.	Assistant Professor	Electronics Engg.	01	15600-39100+6000	On contract
5.	Assistant Professor	Mechanical Engg.	01	15600-39100+6000	On contract
6.	Assistant Professor	Mathematics	01	15600-39100+6000	On contract
7.	Assistant Professor	Physics	01	15600-39100+6000	On contract
8.	Assistant Professor	Management	01	15600-39100+6000	On contract
9.	Assistant Professor	English		15600-39100+6000	On contract

हालांकि उपरोक्त पदों को भरने से पूर्व इनके भर्ती एवं पदोन्नति नियम शैक्षणिक योग्यता AICTE मानकों के अनुसार होंगे जिसकी पुष्टि वित्त समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

इसके अतिरिक्त परिषद ने वित्त समिति की अनुशंसा अनुसार विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में वर्तमान कार्यरत शिक्षकों को नियमानुसार स्वयं वित्त पोषित निधि के अर्जित ही पदोन्नति एवं जीवन वृत्त योजना career advancement (CAS) के लाभ देने हेतु पदोन्नति एवं भर्ती नियम बनाने के निर्देश दिए।

(डॉ० पंकज ललित)

कुलसचिव

दिनांक

22 MAR 2016

पृष्ठांकन संख्या: सम।

प्रतिलिपि:-

1. अधिष्ठाता अध्ययन/छात्र कल्याण/मुख्य छात्रापाल, हि0प्र0वि0, शिमला।
2. अधिष्ठाता समस्त संकाय/अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्ष/निदेशक, हि0प्र0वि0, शिमला।
3. अधिशासी अभियन्ता(निर्माण/डिजाइन)/पुस्तकालयाध्यक्ष, हि0प्र0वि0, शिमला।
4. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक/आन्तरिक लेखा अधिकारी/मुख्य सुरक्षा अधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी/हि0प्र0वि0, शिमला।
5. निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय दूरदर्शी शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र/शारीरिक शिक्षा।
6. निदेशक, यू0आई0आई0टी0 हि0प्र0वि0, शिमला को इस निवेदन के साथ की वे AICTE मानकों के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति नियम तथा CAS के लाभों को संस्थान के शिक्षकों के लिए संशोधन का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष निर्णयानुसार प्रस्तुत करें।
7. प्रभाषी स्थापना शाखा हि0प्र0वि0, शिमला।
8. निदेशक, आई0आई0एच0एस0/ए0ई0आर0सी0/पी0ई0सी0सी0/एच0आर0डी0सी0 यू0आई0एल0एस0।
9. निदेशक, हि0प्र0वि0 वि0 क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।
10. प्रधानाचार्य, हि0प्र0वि0 वि0 सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, शिमला।
11. समस्त साविधिक अधिकारी/शाखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, हि0प्र0वि0, शिमला।
12. सचिव/वरिष्ठ निजी सचिव कुलपति/वरिष्ठ निजी सचिव प्रतिकुलपति/निजी सहायक कुलसचिव, हि0प्र0वि0, शिमला।
13. रक्षक मिसिल।

कुलसचिव

No.9-30/2000-HPU(Gent.)Vol.II

-146-

Dated: Shimla-5, the 23rd February, 2019.

NOTIFICATION

The Executive Council vide item No.26 of its meeting held on 22.01.2019, on the recommendations of the Finance Committee vide Res. No.7 under On Spot Item of its meeting held on 18.01.2019 read with Res. No. 17 has approved the starting of B.Tech. Courses in Civil Engineering (60 seats), Electrical Engineering (60 seats) and Electronics & Communications Engineering (60 seats) under Self-Financing Scheme in the University Institute of Information Technology (UIIT) and also approved the creation and filing up of following Teaching and Non-Teaching Posts in the main Stream of the University as under:

Sr.No.	Name of the Posts	No. of Posts	Pay Scale
1.	Professor	03	Rs.37400-67000+10000(AGP)
2.	Associate Professor	06	Rs.37400-67000+9000(AGP)
3.	Assistant Professor	30	Rs.15600-39100+6000(AGP)
4.	JOA (Accounts)	01	Rs.5910-20200+1950(GP)
5.	JOA(IT)	02	Rs.5910-20200+1950(GP)
6.	Lab. Attendant	06	Rs.5910-20200+1900(GP)
7.	Clerk (Hostel)	02	Rs.5910-20200+1900(GP)
8.	Hostel Attendant	02	Rs.5910-20200+1900(GP)
9.	Peon	03	Rs.4900-10680+1300(GP)

Further, 06 posts of Chowkidar and 02 posts of Mali shall be filed-up through outsource and also approved the outsourcing of Security and Cleaning Services.

However, the posts of Networking Engineer/Junior Technician (Grade-IV) and Mechanic (Civil-01, Electrical-01 and Electronics & Communications-01) shall be notified separately after the R&P Rules and pay scale for the said posts are adopted/notified by the University.

(Ghanshyam Chand) HAS
REGISTRAR

Endst.No.Even.

Dated: Shimla-5, the 23rd February, 2019.

Copy to:

1. The Dean of Studies/DSW/Chief Warden, HPU, Shimla-5.
2. The Director, UIIT, HPU, Shimla-5 with the request to report the start of New Courses in the next meeting of Academic Council.
3. The Finance Officer/Controller of Examinations, HPU, Shimla-5.
4. The Assistant Registrar(Estt.)/(Rectt.), HPU, Shimla-5.
5. The Assistant Registrar(Academic), HPU, Shimla with the direction to report the start of New Courses in the next meeting of Academic Council.
6. The Joint Controller (LAD)/Internal Audit Officer, HPU, Shimla-5.
7. The SPS to Hon'ble Vice-Chancellor/PVC/PA to Registrar, HPU, Shimla-5.
8. The Assistant Registrar(Budget), HPU, Shimla with the direction to report the action taken on items No.07 under On Spot Item in the ensuing meeting of the Finance Committee.
9. The Section Officer (GAD), HPU, Shimla-5 with the direction to report the action taken on items No.17 & 26 (on the sport item No.-7 of Finance Committee meeting held on 18.01.2019) of the meeting of the 22.01.2019 in the ensuing meeting of the Executive Council.
10. The Supdt.(Revision/Regulations), HPU, Shimla-5 with the request to take further necessary action with respect to adoption of R&P Rules and Pay Scale for the posts of Networking Engineer (Junior Tech. Grad-IV) and Mechanic (Civil-01, Electrical-01 and Electronics & Communications-01).
11. The Guard file.

24/2
REGISTRAR

No. 9-30/2000-HPU(Genl.)Vol.II

Dated: Shimla-5, the

22 JUN 2021

NOTIFICATION

The Executive Council vide Res. No. 18 of its meeting held on 30-03-2021 has approved the recommendations of the Department Council of University Institute of Technology (UIT) dated 24-2-2021 wherein UIT shall be divided into multiple departments, as under:

i)	Department of Information Technology (IT)
ii)	Department of Computer Science Engineering (CSE)
iii)	Department of Electronics & Communication Engineering (ECE)
iv)	Department of Civil Engineering (CE)
v)	Department of Electrical Engineering (EE)
vi)	Department of Applied Sciences and Humanities

Suneel Sharma (HAS)

REGISTRAR

Endst.No.Even

Dated: 22 JUN 2021

Copy to :

1. The Dean of Studies/ DSW/Chief Warden, HPU, Shimla-5.
2. The Director, (UIT), HPU, Shimla-5.
3. The Finance Officer/ Controller of Examinations/P&DO/ACOE, HPU, Shimla-5.
4. The Deputy Registrar/Assistant Registrar (Estt./Recd./Fin.), HPU, Shimla-5.
5. The Joint Controller (LAD)/ Internal Audit Officer, HPU, Shimla-5.
6. The Deputy Registrar (Academic), HPU, Shimla-5 with the direction to report the action taken to the Academic Council.
7. The Section Officer, (GAD), HPU, Shimla-5 with the direction to report the action taken to the Executive Council.
8. The Supdt. (Regulation/ Revision/Committee), HPU, Shimla-5.
9. The SPS to Vice-Chancellor/PA to Registrar, HPU, Shimla-5
10. The Guard file.

REGISTRAR

28/6/21

Supdt. U.I.T.

28/6/21

File No-7-1/2021-HPU (Acad)
(NAAC Accredited "A" Grade University)
Himachal Pradesh University, Summer-Hill, Shimla-5
Academic Branch

Dated: 03-12-2021

To

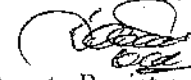
1. All the Dean of the Faculties, HPU, Shimla-5.
2. The Dean, Planning and Teachers' Matters, HPU, Shimla-5
3. Prof. Nainjeet Singh Negi, HPU, Shimla-5.
4. Prof. Khem Chand, Deptt. of Mathematics, HPU, Shimla-5.
5. Dr. Niranjna Bhandari, Deptt. of Sociology, HPU, Shimla-5.

Subject: **Proceedings of the meeting of the Standing Committee of Academic Council (by circulation) held on 03-12-2021.**

Sir/Madam

Please find enclosed a copy of the Proceeding of the meeting of the Standing Committee of the Academic Council which was held on 03-12-2021 (by circulation) for information.

Yours faithfully,

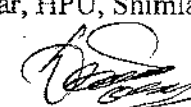

Deputy Registrar (Acad)
H.P. University, Shimla-5.
Dated: 03-12-2021.

Encls. As above

Endst. No. even

Copy forwarded for information to:-

1. The Controller of Examination, H.P. University, Shimla-171005.
2. The D.R./A.R. (D.S. Office), H.P. University, Shimla-171005.
3. The A.R. Admn), HPU, Shimla-171005.
4. The D.R./A.R. (Secrecy), HPU, Shimla-5.
5. The SPS to Vice-Chancellor/PA to Dean of Studies/Registrar, HPU, Shimla-5.


Deputy Registrar (Acad)

शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 23.12.1994 की बैठक में मद संख्या 19 के अन्तर्गत गठित स्थायी समिति की दिनांक 03.12.2021 को परिचालन द्वारा (by circulation) आयोजित बैठक की कार्यवाही।

शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की आपात् बैठक दिनांक 03.12.2021 को परिचालन द्वारा (by circulation) आयोजित की गई तथा निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. आचार्य, ए. के. भट्ट, अधिष्ठाता अध्ययन, अध्यक्ष एवं संयोजक।
2. आचार्य, ए. के. भट्ट, अधिष्ठाता, योजना एवं शिक्षक मामले।
3. आचार्य, रघुविन्द्र सिंह, अधिष्ठाता, विधि संकाय।
4. आचार्य, विजय कुमार, अधिष्ठाता वाणिज्य एवं प्रबन्धन संकाय।
5. आचार्य, ममता मोक्टा, अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय।
6. आचार्य, विजय चौधरी, अधिष्ठाता, होम्योपैथी एवं आर्युवेद संकाय।
7. आचार्य, आनंद सागर, अधिष्ठाता जीव विज्ञान संकाय।
8. आचार्य, नैन सिंह, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय।
9. आचार्य, नागेश ठाकुर, अधिष्ठाता, प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिकी संकाय।
10. आचार्य, पी.के. गर्ग, अधिष्ठाता इन्वॉयरमेंट डेवेलपमेंट एंड सस्टेनिबिलिटी स्टडीज।
11. डॉ. आशु कुमार गुप्ता, अधिष्ठाता दंत संकाय।
12. आचार्य, खेमचन्द, गणित विभाग, हि.प्र.वि.वि. शिमला-5.
13. आचार्य, नैनजीत सिंह नेगी, गणित विभाग, हि.प्र.वि.वि. शिमला-5.
14. डॉ. निरंजना भण्डारी, समाजशास्त्र विभाग, हि.प्र.वि.वि. शिमला-5.

अधिष्ठाता अध्ययन, अध्यक्ष/संयोजक, शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति के निर्देशानुसार शैक्षणिक शाखा द्वारा शैक्षणिक परिषद् की स्थाई समिति के उपरोक्त सम्माननीय सदस्यों को कार्यसूची को परिचालन द्वारा (by circulation) प्रेषित किया गया।

Item No. 1:- Matter placed before the Standing Committee of Academic Council for consideration and approval regarding redistribution of Sanctioned Vacant Teaching Posts: (i) Director/Professor, (ii): Professor-06 (37400-67000+10000 Grade Pay), (iii) Associate Professor-11 (37400-67000+9000 Grade Pay) and (iv) Assistant Professor -28 (15600-39100+6000 Grade Pay) in University Institute of Technology (UIT) to run the six Departments namely, Information Technology (IT), Computer Science Engineering (CSE), Electronics & Communication

P.T.O

Engineering (ECE), Civil Engineering (CE), Electrical Engineering (EE) and Applied Sciences and Humanities (ASH).

The Agenda item alongwith its annexures supplied by circulation to each of the member of the Standing Committee of Academic Council as mentioned supra which was perused in detail by the members of the Standing Committee and have accorded their approval and further recommended for Executive Council.

Sd/-
देवीराम,
उप- कुलसचिव, (शे.)

पुष्टिकरण

Sd/-
आचार्य, अरविन्द कुमार भट्ट
अधिष्ठाता अध्ययन, हि.प्र.वि.वि.
शिमला-5.

अनुमोदित

Sd/-
आचार्य, सिकन्दर कुमार,
माननीय, कुलपति महोदय,
हि.प्र.वि.वि. शिमला-5.